



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1

PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 28]

नई दिल्ली, बुधवार, फरवरी 1, 2017/माघ 12, 1938

No. 28]

NEW DELHI, WEDNESDAY, FEBRUARY 1, 2017/MAGHA 12, 1938

वित्त मंत्रालय

(आर्थिक कार्य विभाग)

(बजट अनुभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 1 फरवरी, 2017

फा. सं. 2(9)—बी(डी)/2017.—निम्नलिखित सर्वसाधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाता है :—

बजट 2017-2018

वित्त मंत्री

अरुण जेटली

का

भाषण

1 फरवरी, 2017

अध्यक्ष महोदया,

वसंत पंचमी के इस पावन दिवस पर मैं वर्ष 2017-18 का बजट प्रस्तुत करता हूँ। वसंत ऋतु जन-मन को आशा एवं उल्लास से परिपूर्ण कर देने वाली ऋतु है। मैं इस अवसर पर सभी को अपनी हार्दिक बधाई देता हूँ।

2. अध्यक्ष महोदया, हमारी सरकार से जनता को ढेरों उम्मीदें हैं जिन्हें पूरा करने के लिए जनता ने हमें चुना है। जनता की असंख्य उम्मीदों में से एक सबसे बड़ी उम्मीद यह है कि जनता हमसे एक अच्छे शासन की उम्मीद करती है। जनता की उम्मीदों में मुद्रास्फीति एवं मूल्य वृद्धि, रोजाना के कामों में भ्रष्टाचार और निरंतर साथ चलने वाले पूंजीवाद की मार जैसी कुछ अत्यधिक महत्वपूर्ण समस्याओं से जनता को राहत पहुंचाना शामिल है। जनता हमसे देश के प्राकृतिक संसाधनों को आवंटित किए जाने, उन्हें इस्तेमाल में लाए जाने के लिए तैयार करने तथा इस्तेमाल में लाने के लिए अपनाए जाने वाले तरीके में भी बड़ा बदलाव लाने की उम्मीद कर रही थी।

3. पिछले ढाई वर्षों से हम अपने देश की शासन व्यवस्था में एक बड़ा बदलाव लाने की दिशा में काम कर रहे थे। हमने

- स्व-निर्णय पर आधारित प्रशासन के स्थान पर नीति एवं व्यवस्था आधारित प्रशासन को अपनाया है;
- निर्णय लेने की प्रक्रिया में पक्षपात के स्थान पर पारदर्शिता को तरजीह दी है;
- एक विस्तृत और गैर-जिम्मेदार हकदारी के बजाय पूरी तरह निर्धारित सुपुर्दगी व्यवस्था को अपनाया है; और
- अनौपचारिक अर्थतंत्र के बजाय एक औपचारिक व्यवस्था को अपनाया है।

मुद्रास्फीति, जो एक लम्बे समय से दो अंकों में बनी हुई थी, को काबू में कर लिया गया है; विकास की मंद गति की जगह तीव्र विकास की गति ने ले ली है; और काले धन के खिलाफ एक बड़ी लड़ाई छेड़ दी गई है। हमने इन सभी मोर्चों पर बिना थके काम किया है और हमें इस रास्ते पर आगे चलने में लोगों का भरपूर समर्थन मिला है जिससे हम प्रोत्साहित हुए हैं। सरकार को अब जनता के धन के एक विश्वासपात्र अभिरक्षक के रूप में देखा जाने लगा है। मैं इस अवसर पर भारत की जनता द्वारा हमारी सरकार को दिए गए भरपूर समर्थन के लिए उनके प्रति अपनी कृतज्ञता व्यक्त करता हूँ।

4. हम बहुत से अन्य उपायों को करना भी जारी रखेंगे ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि विकास के लाभ किसानों, कामगारों, गरीबों, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों, महिलाओं एवं समाज के दूसरे कमजोर तबकों तक पहुंच सकें। हमारा विशेष ध्यान अपने युवाओं में शक्ति का संचार करने पर होगा ताकि वे विकास एवं रोजगार के लाभों को प्राप्त कर सकें।

5. **अध्यक्ष महोदय,** मैं यह बजट ऐसे समय पर प्रस्तुत कर रहा हूँ जबकि पिछले एक वर्ष के दौरान दुनिया भर में बड़ी आर्थिक और राजनीतिक घटनाएं हुई हैं जिनके कारण वैश्विक आर्थिक व्यवस्था अत्यधिक अनिश्चितता के दौर से गुजर रही है। इसके बावजूद, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा यह अनुमान लगाया गया है कि विश्व के सकल घरेलू उत्पाद में वर्ष 2016 में 3.1% की और वर्ष 2017 में 3.4% की वृद्धि होगी। उन्नत अर्थव्यवस्था वाले देशों में विकास की दर **1.6% से 1.9%** के बीच और उभरती हुई अर्थव्यवस्था वाले देशों में **4.1% से 4.5%** के बीच होने की आशा है। मौजूदा संकेतकों के अनुसार, कुछ बड़ी अर्थव्यवस्था वाले देशों में बृहत आर्थिक नीति के अधिक विस्तृत रूप में होने की आशा है। वर्ष 2016 में तुलनात्मक रूप से निम्न प्रदर्शन के बाद अनेक उभरती हुई अर्थव्यवस्था वाले देशों में विकास की गति के वर्ष 2017 में फिर से पटरी पर आ जाने की आशा है। ये सब बातें आगामी वर्ष के लिए भरपूर संभावनाएं प्रस्तुत करने वाले सकारात्मक संकेत हैं।

6. तथापि, उभरती हुई अर्थव्यवस्था वाले देशों के सामने तीन प्रमुख चुनौतियां बनी हुई हैं। **पहली**, अमरीकी फेडरल रिजर्व द्वारा की गई मौजूदा आर्थिक नीतिगत व्यवस्था, जिसमें इसने वर्ष 2017 में नीति दरों में एक से अधिक बार वृद्धि करने की मंशा जाहिर की है, के कारण उभरती हुई अर्थव्यवस्था वाले देशों में पूंजी के अंतर्वाह में कमी आएगी और पूंजी के देश से बाहर जाने की गति तेज होगी। **दूसरी**, वस्तुओं के मूल्य और विशेषकर कच्चे तेल के मूल्यों में अनिश्चितता बनी रहने के कारण उभरती हुई अर्थव्यवस्था वाले देशों की राजकोषीय स्थिति प्रभावित हुई है। तथापि, उम्मीद है कि यदि इसमें कोई वृद्धि होती है तो शेल गैस और तेल उत्पादकों की तत्काल प्रतिक्रिया के कारण तेल के मूल्य प्रभावित होंगे। इससे कच्चे तेल और पेट्रोलियम के मूल्यों में कमी आएगी। **तीसरी**, विश्व के अनेक हिस्सों में संरक्षणवाद के लिए दबाव में निरंतर वृद्धि होने के कारण वस्तुओं, सेवाओं तथा लोगों के वैश्वीकरण से दूर जाने की घटनाओं में वृद्धि होने के संकेत दिखाई दे रहे हैं। इन घटनाक्रमों के कारण भारत सहित उभरती हुई अर्थव्यवस्था वाले अनेक देशों से निर्यात पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना है।

7. इन सभी घटनाओं के बीच भारत विश्व के आर्थिक परिदृश्य में एक चमकते हुए सितारे के समान खड़ा है। भारत की बृहत आर्थिक स्थिरता इसकी आर्थिक सफलता का आधार बना हुई है। सीपीआई मुद्रास्फीति जुलाई, 2016 में **6%** से घटकर दिसम्बर, 2016 में **3.4%** रह गई है और इसके भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा अधिदेशित 2% से 6% की रेंज के भीतर बने रहने की आशा है। अनुकूल मूल्य स्थितियां विवेकसम्मत बृहत आर्थिक प्रबंधन को दर्शाती हैं, जिनके परिणामस्वरूप कृषि उत्पादन और विशेषकर दालों के उत्पादन में तेजी आई है। भारत का चालू खाता घाटा पिछले वर्ष के सकल घरेलू उत्पाद के लगभग **1%** से घटकर वर्ष 2016-17 के पूर्वार्ध में सकल घरेलू उत्पाद का 0.3% रह गया है। प्रत्यक्ष विदेशी

निवेश पिछले वर्ष की पहली छमाही के ₹1,07,000 करोड़ से बढ़कर वर्ष 2016-17 के पूर्वार्ध में ₹1,45,000 करोड़ हो गया है। इससे वैश्विक स्तर पर प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) के अंतर्वाह में 5% की कमी आने के बावजूद हमारे देश में 36% की वृद्धि दिखाई देती है। 20 जनवरी, 2017 की स्थिति के अनुसार हमारा विदेशी मुद्रा भंडार 361 बिलियन अमरीकी डालर हो गया है, जो लगभग 12 महीनों तक आयात के लिए एक आसान कवर निरूपित करता है।

8. सरकार अर्थव्यवस्था की सार्वजनिक निवेश संबंधी जरूरतों से समझौता किए बिना राजकोषीय समेकन के पथ पर निरंतर आगे बढ़ रही है। विदेशी मोर्चे पर भारतीय अर्थव्यवस्था ने एफसीएनआर जमाराशियों की निकासी, अमरीकी चुनावों के कारण बनी अस्थिरता की स्थिति, तथा फेडरल रिजर्व द्वारा ब्याज दरों में वृद्धि किए जाने सहित अनेक आघातों को सफलतापूर्वक सहन किया है। अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा लगाए गए एक पूर्वानुमान के अनुसार, वर्ष 2017 में भारत के एक तेजी से विकसित हो रही प्रमुख अर्थव्यवस्था बनने की आशा है।

9. पिछले दो वर्षों के दौरान जारी अनेक वैश्विक रिपोर्टों और मूल्यांकनों से यह ज्ञात होता है कि भारत ने अपनी नीतियों, पद्धतियों एवं आर्थिक दशा में उल्लेखनीय सुधार किया है। विश्व बैंक की 'डूईंग बिजनेस रिपोर्ट'; अंकटाड की 'वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट, 2016'; वर्ल्ड इकोनोमिक फोरम की 2015-16 और 2016-17 की 'ग्लोबल कम्पीटिटिवनेस रिपोर्ट'; और अनेक अन्य रिपोर्टों से इस बात का पता चलता है। भारत विश्व में छठा सबसे बड़ा विनिर्माणकारी देश बन गया है, पहले यह नौवें स्थान पर था। अब हमारे देश को वैश्विक विकास के प्रेरक के रूप में देखा जाने लगा है।

10. पिछले एक वर्ष के दौरान हमारे देश में अनेक ऐतिहासिक एवं प्रभावपूर्ण आर्थिक सुधार एवं नीतिगत निर्णय किए गए हैं। वास्तव में, भारत रूपांतरणकारी सुधार कार्यों को करने वाले बहुत थोड़े देशों के समूह में शामिल था। दो अत्यधिक महत्वपूर्ण नीतिगत पहल अर्थात् जीएसटी के लिए संविधान संशोधन बिल को पारित कराना और संसद में इसे लागू किए जाने की दिशा में कार्य करना; तथा उच्च मूल्य वर्ग के बैंक नोटों का विमुद्रीकरण। विकास की गति में तेजी लाने, प्रतिस्पर्धा, अप्रत्यक्ष कर को सरल बनाने तथा इस प्रक्रिया में अधिक पारदर्शिता लाने के संदर्भ में हमारी अर्थव्यवस्था के लिए जीएसटी के लाभों पर संसद के दोनों सदनों में व्यापक विचार-विमर्श किया जा चुका है। मैं संविधान संशोधन विधेयक को सर्वसम्मति से पारित करने के लिए दोनों सदनों के सभी सदस्यों को धन्यवाद देता हूं। मैं संबंधित सभी समस्याओं को जीएसटी कौंसिल में समाधान कराने के लिए राज्य सरकारों को भी धन्यवाद देता हूं।

11. उच्च मूल्य वर्ग के बैंक नोटों का विमुद्रीकरण गत दो वर्षों के दौरान हमारी सरकार द्वारा किए गए अनेक उपायों में शामिल है। यह एक साहसिक एवं निर्णायक उपाय है। अनेक दशकों से कई लोगों के लिए कर-वंचना उनकी जीवनशैली में शामिल हो गयी है। इसके कारण जनता के व्यापक हितों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता रहा है तथा इसके फलस्वरूप कर-वंचना करने वाले लोगों में अनुचित संपन्नता बढ़ी है तथा निर्धन एवं सुविधाविहीन लोगों के लिए परेशानियां पैदा हुई हैं। इसके कारण एक समानांतर अर्थव्यवस्था का जन्म हुआ है जो किसी भी समावेशी विकास की दिशा में आगे बढ़ने वाले समाज के लिए अस्वीकार्य है। विमुद्रीकरण द्वारा एक नये 'क्षितिज' का निर्माण हुआ है जिसमें सकल घरेलू उत्पाद के विकास की दर तुलनात्मक रूप से अधिक होगी तथा अर्थव्यवस्था अधिक स्वच्छ एवं वास्तविक होगी। यह कार्य भ्रष्टाचार, काला धन, जाली करेंसी और आतंकवादी गतिविधियों के वित्तपोषण को समाप्त करने के लिए हमारी सरकार द्वारा लिए गए संकल्प का एक हिस्सा है। अन्य सभी सुधारों के समान ही, स्पष्ट है कि यह उपाय भी स्थापित व्यवस्था के लिए कष्टकारी सिद्ध होगा क्योंकि इसमें वर्षों से चली आ रही स्थिति में बदलाव लाने पर विचार किया गया है। यदि नई मुद्रा को बाजार में लाने की अवधि के दौरान मुद्रा की कमी के कारण आर्थिक क्रियाकलापों में कोई व्यवधान आया हो तो उम्मीद है कि इसके कारण अर्थव्यवस्था पर केवल एक क्षणिक प्रभाव ही पड़ेगा। मुझे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी द्वारा कही गई यह बात याद आती है कि 'सही उद्देश्य की प्राप्ति के लिए किया गया कार्य कभी भी विफल नहीं होता।'

12. विमुद्रीकरण से भ्रष्टाचार में कमी, अर्थव्यवस्था के अधिकाधिक डिजिटाइजेशन, वित्तीय बचतों में वृद्धि तथा अर्थव्यवस्था को अधिकाधिक उचित रूप प्राप्त होने के संदर्भ में दीर्घावधिक लाभ सृजित होने की प्रबल संभावना है और इन सभी के फलस्वरूप सकल घरेलू उत्पाद में तेजी से वृद्धि के साथ-साथ कर-राजस्व में भी वृद्धि होगी। विमुद्रीकरण से संसाधन के कर-वंचकों से सरकार को अंतरित होने में सहायता मिली है तथा सरकार इन संसाधनों का प्रयोग निर्धनों और वंचित वर्गों के कल्याण के लिए कर सकती है। बैंकों की कम ब्याज दरों पर ऋण देने की क्षमता में वृद्धि होना तथा

समाज के सभी तबकों द्वारा काफी अधिक संख्या में डिजिटाइजेशन को अपनाना इसका साक्षी है। हम निश्चयपूर्वक इस बात पर विश्वास करते हैं कि विमुद्रीकरण तथा जीएसटी, जो हमारी सरकार की तीसरी रूपांतरकारी उपलब्धि अर्थात् जैम (जनधन, आधार, मोबाइल) परिकल्पना पर आधारित है, का हमारी अर्थव्यवस्था तथा हमारे लोगों के जीवन पर युगांतरकारी प्रभाव पड़ेगा।

13. अध्यक्ष महोदया, हम वृद्धि एवं विकास के मार्ग के एक अत्यधिक महत्वपूर्ण मोड़ पर खड़े हैं।

इस मोड़ पर घबरा के न थम जाइए आप
जो बात नयी है उसे अपनाइए आप
डरते हैं नयी राह पे क्यों चलने से
हम आगे-आगे चलते हैं आजाइए आप

14. पुनः मौद्रिकरण ने गति पकड़ ली है और जल्दी ही यह आसान स्तर पर आ जाएगा। विमुद्रीकरण के प्रभाव आगामी वर्ष तक नहीं रह जाएंगे। इसे ध्यान में रखते हुए, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष ने भी 2016 के संबंध में भारत के सकल घरेलू उत्पाद में कमी आने की घोषणा करते हुए 2017 और 2018 में सकल घरेलू उत्पाद में क्रमशः 7.2% और 7.7% की वृद्धि होने का अनुमान लगाया है। तथापि, विश्व बैंक इस संबंध में अधिक आशावादी है तथा इसने भारत में सकल घरेलू उत्पाद की विकास दर वर्ष 2016-17 में 7%, वर्ष 2017-18 में 7.6% और वर्ष 2018-19 में 7.8% रहने का अनुमान लगाया है। हमारी अर्थव्यवस्था में यह वृद्धि हमारी नीतिगत तथा आर्थिक सुधारों को जारी रखने के संबंध में हमारी प्रतिबद्धता; अवसंरचना सुविधाओं तथा विकास परियोजनाओं में सार्वजनिक निवेश में वृद्धि; तथा विश्व अर्थव्यवस्था में फिर से तेजी आने की आशा के संदर्भ में निर्यात में वृद्धि के आधार पर अनुमानित की गई है। विमुद्रीकरण के कारण हमारी बैंकिंग प्रणाली में काफी अधिक नकदी जमा हो गई है, जिससे इन बैंकों द्वारा उधार पर ब्याज में कमी आएगी तथा अधिकाधिक लोगों को बैंक ऋण दिए जा सकेंगे। इससे आर्थिक क्रियाकलापों में काफी अधिक तेजी होगी और इसके अनेक अन्य प्रभाव भी होंगे।

15. माननीय प्रधानमंत्री द्वारा 31 दिसम्बर, 2016 को दिए गए भाषण में इस चरण पर हमारी अर्थव्यवस्था से संबंधित अनेक महत्वपूर्ण मुद्दों पर बात की गई थी जैसेकि निर्धनों के लिए आवास; किसानों को राहत; सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमियों को ऋण सहायता; डिजिटल लेन-देन को प्रोत्साहन देना; गर्भवती महिलाओं तथा वरिष्ठ नागरिकों को सहायता प्रदान करना; एवं मुद्रा योजना के तहत दलितों, जनजातीय समुदाय के लोगों, पिछड़ वर्ग के लोगों तथा महिलाओं को प्राथमिकता प्रदान करना।

16. इस बजट को तैयार करते समय मेरा समग्र विचार ग्रामीण क्षेत्रों, अवसंरचना तथा गरीबी उन्मूलन के क्षेत्र में अधिक व्यय करने तथा ऐसा करते हुए राजकोषीय विवेक के सर्वोत्तम मानकों को बनाए रखना रहा है। मैंने आर्थिक सुधारों को जारी रखने, अधिक मात्रा में निवेश को बढ़ावा देने और विकास की गति को त्वरित करने की आवश्यकता को भी ध्यान में रखा है।

17. पिछला एक वर्ष अन्य प्रमुख सुधारों का साक्षी रहा है जैसेकि शोधन अक्षमता एवं दिवालियापन संहिता का अधिनियमन; मुद्रास्फीति संबंधी लक्ष्य निर्धारण के लिए भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम में संशोधन; वित्तीय सस्मिडी तथा लाभ के संवितरण हेतु आधार विधेयक का अधिनियमन; एफडीआई नीति में उल्लेखनीय सुधार; वस्त्र सेक्टर के लिए रोजगार सृजन संबंधी पैकज; तथा अनेक अन्य उपाय। हम निर्धनों तथा सुविधाविहीन वर्गों के लाभ के लिए आर्थिक सुधार की प्रक्रिया को जारी रखेंगे।

18. अध्यक्ष महोदया, वर्ष 2017-18 के बजट में तीन प्रमुख सुधारों का उल्लेख किया गया है। पहला, बजट प्रस्तुत करने की तिथि को अग्रिम करके इसे 1 फरवरी को प्रस्तुत किया जा रहा है ताकि संसद लेखा अनुदान को पारित करने की प्रक्रिया से बच सके तथा मौजूदा वित्त वर्ष समाप्त होने से पूर्व ही वित्त वर्ष 2017-18 के लिए एक विनियोग विधेयक पारित कर दे। इससे मंत्रालय तथा विभाग आगामी वित्त वर्ष के आरंभ से ही नई योजनाओं सहित सभी योजनाओं और परियोजनाओं पर कार्य कर सकेंगे। वे मॉनसून शुरू होने से पहले उपलब्ध काम के समय का पूरी तरह उपयोग कर सकेंगे। दूसरा, रेल बजट का आम बजट के साथ विलय करना एक ऐतिहासिक कदम है। हमने वर्ष 1924 से चली आ

रही इस औपनिवेशित प्रथा को बंद कर दिया है। इस निर्णय से रेलवे सरकार की राजकोषीय नीति के केंद्र में आ जाएगा तथा इससे रेलवे, राजमार्गों तथा अंतर्देशीय जलमार्गों के बीच मल्टी मॉडल परिवहन आयोजना तैयार की जा सकेगी। तथापि, रेलवे की कार्यात्मक स्वायत्तता बनाए रखी जाएगी। तीसरा, हमने व्यय के आयोजना एवं आयोजना-भिन्न वर्गीकरण को समाप्त कर दिया है। इससे हमें विभिन्न क्षेत्रों तथा मंत्रालयों के लिए आवंटन के संबंध में समग्र दृष्टि अपनाने में सहायता प्राप्त होगी। इससे संसाधनों के इष्टतम आवंटन को बढ़ावा मिलेगा।

19. अध्यक्ष महोदया, हम यह जानते हैं कि हमें अपने लोगों के लिए काफी कुछ करने की आवश्यकता है। जनता की आशाओं को पूरा करने के कार्य को जारी रखते हुए अगले वर्ष के लिए हमारा एजेंडा टीईसी इंडिया अर्थात् 'ट्रांसफार्म, एनर्जाइज एंड क्लीन इंडिया (भारत में आमूल परिवर्तन लाने, शक्ति का संचार करने तथा स्वच्छ भारत बनाने)' पर रहेगा। टीईसी इंडिया कार्यक्रम में निम्नलिखित शामिल है :

- प्रशासन की गुणवत्ता तथा हमारी जनता के जीवन की गुणवत्ता में आमूल परिवर्तन लाना;
- समाज के विभिन्न तबकों विशेषकर युवाओं एवं कमजोर तबकों में शक्ति का संचार करना तथा उन्हें उनकी वास्तविक क्षमता को पहचानने में समर्थ बनाना; और
- देश में भ्रष्टाचार, काला धन और अपारदर्शी राजनीतिक वित्तपोषण की बुराइयों को समाप्त करना।

मैं इस व्यापक एजेंडा को आगे बढ़ाने के लिए अपने बजट प्रस्तावों को दस विशिष्ट स्तंभों के अंतर्गत रखने का प्रस्ताव करता हूँ जिनमें निम्नलिखित शामिल हैं :

- (i) **किसान :** हम किसानों की आय को अगले पांच वर्षों में दोगुना करने के लिए प्रतिबद्ध हैं;
- (ii) **ग्रामीण आबादी :** रोजगार तथा बुनियादी अवसंरचना उपलब्ध कराना;
- (iii) **युवा :** इन्हें शिक्षा, कौशल एवं रोजगार उपलब्ध कराकर इनमें शक्ति का संचार करना;
- (iv) **गरीब तथा विशेष सुविधाओं से वंचित वर्ग :** सामाजिक सुरक्षा, स्वास्थ्य सुविधा प्रणालियों तथा वहनीय आवास सुविधाओं को सुदृढ़ बनाना;
- (v) **अवसंरचना :** दक्षता, उत्पादकता तथा जीवन स्तर में सुधार लाने के लिए;
- (vi) **वित्तीय क्षेत्र :** सुदृढ़ संस्थाओं के माध्यम से विकास एवं स्थायित्व को बढ़ावा देना;
- (vii) **डिजिटल अर्थव्यवस्था :** गति, उत्तरदायित्व एवं पारदर्शिता के लिए;
- (viii) **सार्वजनिक सेवा :** जनता की भागीदारी के जरिए प्रभावी शासन एवं दक्ष सेवा सुपुर्दगी की व्यवस्था करना;
- (ix) **विवेकपूर्ण राजकोषीय प्रबंधन :** संसाधनों का इष्टतम प्रयोग सुनिश्चित करना तथा राजकोषीय स्थायित्व को बनाए रखना; और
- (x) **कर-प्रशासन :** ईमानदार व्यक्तियों को सम्मान देना।

I. किसान

20. भारतीय किसान ने एक बार फिर से इस वर्ष अपनी प्रतिबद्धता तथा समुत्थान शक्ति प्रदर्शित की है। पिछले वर्ष की तुलना में खरीफ और रबी फसलों के अंतर्गत कुल बुआई क्षेत्रों में वृद्धि हुई है। मानसून की स्थिति अपेक्षाकृत बेहतर रहने से कृषि क्षेत्र में चालू वर्ष के दौरान 4.1% की वृद्धि होने की आशा है।

21. पिछले वर्ष के बजट भाषण में मैंने पांच वर्षों में किसानों की आय को दोगुना करने के लिए किसानों की 'आय सुरक्षा' पर ध्यान केंद्रित किया था। मैंने इस संबंध में अनेक उपायों की भी घोषणा की थी। हमें और अधिक उपाय करने होंगे तथा किसानों को उनके उत्पादन एवं उत्पादकता में वृद्धि करने; और फसल प्राप्ति के उपरांत आने वाली चुनौतियों का सामना करने के लिए समर्थ बनाना होगा।

- 22.** अच्छी फसल के लिए, किसानों को समय से पर्याप्त ऋण उपलब्ध कराया जाना चाहिए। वर्ष 2017-18 के लिए कृषि ऋण हेतु लक्ष्य ₹10 लाख करोड़ के रिकार्ड स्तर पर निर्धारित किया गया है। हम अल्पसेवित क्षेत्रों, पूर्वी राज्यों तथा जम्मू व कश्मीर राज्यों में रहने वाले किसानों के लिए पर्याप्त ऋण की व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए विशेष प्रयास करेंगे। किसानों को सहकारी ऋण ढांचे से लिए गए ऋण के संबंध में माननीय प्रधानमंत्री द्वारा घोषित 60 दिनों के ब्याज के भुगतान से छूट का लाभ भी प्राप्त होगा।
- 23.** लगभग 40% छोटे एवं सीमांत किसान सहकारी ढांचे से ऋण प्राप्त करते हैं। प्राथमिक कृषि ऋण सोसाइटियां ऋण वितरण के लिए अग्र सिरे के रूप में कार्य करती हैं। हम जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंकों की कोर बैंकिंग प्रणाली के साथ सभी 63,000 क्रियाशील प्राथमिक कृषि ऋण सोसायटियों के कम्प्यूटरीकरण तथा समेकन के लिए नाबार्ड को सहायता उपलब्ध कराएंगे। यह कार्य ₹1900 करोड़ की अनुमानित लागत पर 3 वर्ष के भीतर पूरा कर लिया जाएगा जिसके लिए राज्य सरकारों द्वारा वित्तीय प्रतिभागिता की जाएगी। इससे लघु एवं सीमांत किसानों को ऋण का निर्बाध प्रवाह सुनिश्चित होगा।
- 24.** बुआई करते समय किसानों के मन में प्राकृतिक आपदाओं के प्रति सुरक्षा का भाव होना चाहिए। हमारी सरकार द्वारा शुरू की गई फसल बीमा योजना इस दिशा में उठाया गया एक प्रमुख कदम है। इस योजना का विस्तार क्षेत्र 2016-17 में फसल क्षेत्र के 30% से बढ़कर 2017-18 में 40% और 2018-19 में 50% हो जाएगा। बजट अनुमान 2016-17 में इस योजना के लिए ₹5,500 करोड़ का बजट प्रावधान किया गया था जिसे बकाया दावे का निपटान करने के लिए 2016-17 के संशोधित अनुमान में बढ़ाकर ₹13,240 करोड़ कर दिया गया था। वर्ष 2017-18 के लिए मैंने इस मद के लिए ₹9,000 करोड़ की राशि का प्रावधान किया है। इस योजना के अंतर्गत बीमाकृत राशि 2015 के खरीफ मौसम में ₹69,000 करोड़ थी जो दोगुने से अधिक होकर 2016 के खरीफ मौसम में ₹1,41,625 करोड़ हो गई है।
- 25.** मृदा स्वास्थ्य कार्ड जारी करने की गति में तेजी आ रही है। किसानों को वास्तविक लाभ तभी प्राप्त होगा जबकि मिट्टी के नमूनों की शीघ्र जांच की जाए तथा मृदा में उपस्थित पोषक तत्वों के स्तर के बारे में उन्हें जानकारी हो। इसलिए सरकार कृषि विज्ञान केंद्रों में नई लघु प्रयोगशालाओं को स्थापित करेगी तथा देश के सभी 648 कृषि विज्ञान केंद्रों का 100% कवरेज सुनिश्चित करेगी। इसके अतिरिक्त, योग्य स्थानीय उद्यमियों द्वारा 1000 लघु प्रयोगशालाएं स्थापित की जाएंगी। सरकार इन उद्यमियों को ऋण संबद्ध सब्सिडी उपलब्ध कराएगी।
- 26.** नाबार्ड में एक दीर्घावधिक सिंचाई कोष स्थापित किया जा चुका है। माननीय प्रधानमंत्री ने इसकी स्थायी निधि में ₹20,000 करोड़ की अतिरिक्त राशि शामिल करने की घोषणा की है। इस कोष में कुल निधि बढ़कर ₹40,000 करोड़ हो जाएगी।
- 27.** 'प्रति बूंद अधिक फसल' लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए नाबार्ड में एक समर्पित सूक्ष्म सिंचाई कोष स्थापित किया जाएगा। इस कोष की आरंभिक निधि ₹5,000 करोड़ होगी।
- 28.** फसल कटाई के बाद के चरण के लिए, हम किसानों को बाजार में अपनी उपज की बेहतर कीमतें प्राप्त करने में समर्थ बनाने के लिए कदम उठाएंगे। राष्ट्रीय कृषि बाजार (ई-नाम) दायरे का मौजूदा 250 बाजारों से 585 एपीएमसी तक विस्तार किया जाएगा। स्वच्छता ग्रेडिंग और पैकेजिंग सुविधाओं की स्थापना के लिए प्रत्येक ई-नाम बाजार को ₹75 लाख की अधिकतम सीमा तक सहायता प्रदान की जाएगी। इससे किसानों को अपनी उपज का अधिक मूल्य मिल सकेगा।
- 29.** बाजार सुधार का कार्य शुरू किया जाएगा और राज्यों से एपीएमसी से खराब होने वाली वस्तुओं को विमुक्त करने (डिनोटिफाई) का अनुरोध किया जाएगा। इससे किसानों को अपनी उपज को बेहतर कीमतों पर बेचने का अवसर मिलेगा।
- 30.** हमारा उन किसानों को एकीकृत करने का भी प्रस्ताव है जो बेहतर मूल्य प्राप्त करने और फसल कटाई के पश्चात हानियों को कम करने के लिए कृषि प्रसंस्करण इकाइयों के साथ फल और सब्जियां उगाते हैं। इसलिए संविदा खेती के संबंध में एक मॉडल कानून तैयार किया जाएगा और इसे अपनाने के लिए राज्यों को भेजा जाएगा।

31. डेयरी, किसानों के लिए अतिरिक्त आमदनी का एक महत्वपूर्ण जरिया है। दुग्ध प्रसंस्करण सुविधा और अन्य सुविधाओं की उपलब्धता से किसान मूल्य वृद्धि के जरिए लाभान्वित होंगे। 'आपरेशन फ्लड' कार्यक्रम के तहत स्थापित दुग्ध प्रसंस्करण इकाइयों की एक बड़ी संख्या पुरानी और अव्यावहारिक हो गई है। 3 वर्षों में ₹8000 करोड़ की संचित निधि से नाबार्ड में एक दुग्ध प्रसंस्करण एवं अवसंरचना निधि की स्थापना की जाएगी। आरंभ में, इस निधि की शुरुआत ₹2000 करोड़ की संचित निधि से की जाएगी।

II. ग्रामीण आबादी

32. अब मैं उस ग्रामीण क्षेत्र पर आता हूँ, जो महात्मा गांधी के हृदय के अत्यधिक करीब था।

33. यदि हम केंद्रीय बजट, राज्य के बजटों, स्वयं-सहायता समूहों के लिए बैंक संबद्धता आदि से ग्रामीण गरीबों के उद्देश्य से संचालित सभी कार्यक्रमों को जोड़ दें, तो ग्रामीण क्षेत्रों में हर वर्ष ₹3 लाख करोड़ से अधिक की राशि खर्च की जाती है। जवाबदेही, परिणामों और सामंजस्य (कन्वर्जेंस) में सुधार लाने पर स्पष्ट ध्यान केंद्रित करने के साथ, हम वर्ष 2019 अर्थात् महात्मा गांधी की 150वीं जयंती तक एक करोड़ परिवारों को गरीबी से निजात दिलाने, 50,000 ग्राम पंचायतों को गरीबी मुक्त बनाने के लिए अंत्योदय मिशन शुरू करेंगे। हम वार्षिक वृद्धियों के साथ मौजूदा संसाधनों का अधिक कारगर तरीके से उपयोग करेंगे। यह अभियान प्रत्येक वंचित परिवार के लिए स्थायी रूप से आजीविका हेतु एक सूक्ष्म योजना पर ध्यान केंद्रित करने के साथ कार्य करेगा। आधार रेखा से प्रगति की निगरानी करने के लिए गरीबी मुक्त ग्राम पंचायतों के लिए एक मिली-जुली सूची विकसित की जाएगी।

34. हमारी सरकार ने किसानों की आमदनी को दोगुना करने के हमारे संकल्प के समर्थन हेतु मनरेगा को उन पर अभिमुख करने के लिए गंभीर प्रयास किए हैं। प्रत्येक ग्रामीण परिवार को कम से कम 100 दिन का रोजगार प्रदान करते हुए, मनरेगा को खेती की उत्पादकता और आमदनी में सुधार लाने हेतु उत्पादक परिसंपत्तियों का सृजन करना चाहिए। मनरेगा निधियों से, पिछले बजट में घोषित खेती से जुड़े 5 लाख तालाबों और 10 लाख कंपोस्ट खाद के गड़दों का लक्ष्य पूरी तरह प्राप्त कर लिया जाएगा। वास्तव में, खेती से जुड़े 5 लाख तालाबों के लक्ष्य के मुकाबले मार्च, 2017 तक लगभग 10 लाख खेती से जुड़े तालाबों का कार्य पूरा कर लिए जाने की आशा है। वर्ष 2017-18 के दौरान, खेती से जुड़े और 5 लाख तालाबों का कार्य शुरू किया जाएगा। इस एकल उपाय से ग्राम पंचायतों को जल की कमी से अत्यधिक राहत मिल जाएगी।

35. मनरेगा में महिलाओं की भागीदारी विगत में 48% से कम थी, जो बढ़कर 55% तक हो चुकी है।

36. माननीय सदस्यगण, आपको यह जानकर प्रसन्नता होगी कि वर्ष 2016-17 में मनरेगा के तहत ₹38,500 करोड़ के बजट प्रावधान को वर्ष 2017-18 में बढ़ाकर ₹48,000 करोड़ कर दिया गया है। यह मनरेगा के लिए अब तक का सबसे अधिक आवंटन है। मनरेगा की सभी परिसंपत्तियों की भू-संबद्धता (जिओ-टैग) और उन्हें लोगों की जानकारी में रखने की पहल ने बेहतर पारदर्शिता की संस्थापना की है। हम मनरेगा कार्यों की योजना के लिए अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी का भी बड़े पैमाने पर उपयोग कर रहे हैं।

37. प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (पीएमजीएसवाई) को अब अभूतपूर्व ढंग से लागू किया जा रहा है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत सड़क निर्माण की गति 2016-17 में तेजी से बढ़कर प्रतिदिन 133 किमी सड़क हो गई है, जबकि 2011-2014 की अवधि के दौरान इसका औसत 73 किमी प्रतिदिन था। हमने वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित खंडों में 100 से अधिक व्यक्तियों वाले पर्यावासों को सड़कों से जोड़ने का कार्य भी प्रारंभ कर दिया है। हम यह कार्य प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत 2019 तक पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। मैंने इस योजना के लिए 2017-18 में ₹19,000 करोड़ की राशि प्रदान की है। राज्यों के अंशदान को मिलाकर, वर्ष 2017-18 में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना पर ₹27,000 करोड़ की राशि खर्च की जाएगी।

38. हम, बेघर और कच्चे मकानों में रहने वालों के लिए 2019 तक 1 करोड़ मकान पूरा करने का प्रस्ताव करते हैं। हमने प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के लिए बजट अनुमान 2016-17 में बजट आवंटन को ₹15,000 करोड़ से बढ़ाकर 2017-18 में ₹23,000 करोड़ कर दिया है।

39. हम 1 मई, 2018 तक 100% ग्रामीण विद्युतीकरण का लक्ष्य प्राप्त करने के अपने पथ पर अग्रसर हैं। 2017-18 में दीन दयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना के तहत ₹4,814 करोड़ के बढ़े हुए आवंटन का प्रस्ताव किया गया है।
40. मैंने बजट अनुमान 2016-17 में ग्रामीण क्षेत्रों में कौशल विकास और आजीविका के अवसरों को बढ़ावा देने के लिए दीन दयाल अंत्योदय योजना और राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के लिए बजट आवंटन 2017-18 में ₹4,500 करोड़ करने का भी प्रस्ताव किया है। प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पीएमईजीपी) और क्रेडिट सहायता योजनाओं के लिए आवंटन तीन गुना से भी अधिक बढ़ा दिया गया है।
41. सुरक्षित स्वच्छता और खुले में शौच करने का अंत करने को बढ़ावा देने में स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) ने जबरदस्त प्रगति की है। ग्रामीण भारत में स्वच्छता का दायरा अक्टूबर, 2014 में 42% से बढ़कर लगभग 60% हो गया है। अब खुले में शौच करने से मुक्त गांवों को पाइपयुक्त जल आपूर्ति के लिए प्राथमिकता दी जा रही है।
42. हमारा अगले चार वर्षों में आर्सेनिक और फ्लोराइड प्रभावित 28,000 पर्यावासों को सुरक्षित पेय जल उपलब्ध कराने का प्रस्ताव है। यह राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम (एनआरडीडब्ल्यूपी) का उप-मिशन होगा।
43. ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों को नए कौशल उपलब्ध कराने के लिए, 2017-18 तक कम से कम 20,000 व्यक्तियों को तत्काल प्रशिक्षण के लक्ष्य के साथ 2022 तक 5 लाख व्यक्तियों को राजगिरी प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा।
44. पंचायती राज संस्थाओं के पास विकास कार्यक्रमों को कार्यान्वित करने के लिए अभी भी मानव संसाधनों की कमी है। इस प्रयोजन हेतु 2017-18 के दौरान एक कार्यक्रम 'परिणामों के लिए मानव संसाधन सुधार' प्रारंभ किया जाएगा।
45. सरकार, किसानों और ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों के जीवन और पर्यावरण में सुधार लाने के लिए उनसे घनिष्ठ सहयोग के साथ कार्य करती रहेगी। यह हमारी सरकार के लिए समझौता न करने वाला कार्यक्रम है। 2017-18 में ग्रामीण, कृषि और संबद्ध क्षेत्रों के लिए कुल आवंटन ₹1,87,223 करोड़ है, जो पिछले वर्ष की तुलना में 24 प्रतिशत अधिक है।

III. युवा

46. अब मैं युवा साथियों के लिए अपने प्रस्तावों की बात करता हूँ।
47. गुणवत्तापरक शिक्षा हमारे युवा साथियों को स्फूर्ति प्रदान करेगी। स्वामी विवेकानंद के शब्दों में 'जो शिक्षा आम लोगों को जीवन हेतु संघर्ष करने के लिए उन्हें सुसज्जित करने में सहायक नहीं होतीतो क्या ऐसी शिक्षा सार्थक है?'
48. हमने अपने विद्यालयों में वार्षिक ज्ञान परिणाम मापने की प्रणाली शुरू करने का प्रस्ताव किया है। स्थानीय नवोन्मेषी अंश के जरिए सृजनशीलता को बढ़ावा देने के लिए विज्ञान की शिक्षा और पाठ्यक्रम में लचीलेपन पर बल दिया जाएगा।
49. व्यापक पहुंच, लैंगिक समानता और गुणवत्ता में सुधार सुनिश्चित करने के लिए स्थानीय नवोन्मेष को प्रोत्साहित करने हेतु माध्यमिक शिक्षा के लिए नवोन्मेष निधि सृजित की जाएगी। इसमें आईसीटी समर्थित ज्ञान रूपांतरण शामिल होगा। ध्यान 3479 शैक्षिक रूप से पिछड़े ब्लॉकों पर होगा।
50. उच्च शिक्षा में हम विश्वविद्यालय अनुदान आयोग में सुधार प्रारंभ करेंगे। अच्छी गुणवत्ता वाली संस्थाओं को बेहतर प्रशासनिक और शैक्षणिक स्वायत्तता प्राप्त करने में समर्थ बनाया जाएगा। महाविद्यालयों की पहचान प्रत्यायन और रैंकिंग के आधार पर की जाएगी और उन्हें स्वायत्तता का दर्जा दिया जाएगा। परिणाम पर आधारित प्रत्यायन और क्रेडिट आधारित कार्यक्रमों के लिए एक संशोधित ढांचा तैयार किया जाएगा।
51. हम सूचना प्रौद्योगिकी का प्रयोग करने और कम से कम 350 ऑनलाइन पाठ्यक्रमों वाले प्लेटफॉर्म **स्वयं** शुरू करने का प्रस्ताव करते हैं। यह विद्यार्थियों को सर्वोत्तम अध्यापकगणों द्वारा पढ़ाए गए पाठ्यक्रमों को आभासी रूप से

उपस्थित होने; उच्च गुणवत्ता वाले पाठन संसाधनों तक पहुंच; वाद-विवाद मंचों पर भागीदारी; परीक्षा देने और शैक्षणिक ग्रेड प्राप्त करने में समर्थ बनाएगा। स्वयं तक पहुंच को शिक्षा के लिए समर्पित डीटीएच चैनलों के साथ जोड़कर इसका विस्तार किया जाएगा।

52. हम उच्च शिक्षण संस्थाओं में सभी प्रवेश परीक्षाएं आयोजित करने के लिए स्वायत्त और स्व-संपोषित प्रमुख समीक्षा संगठन के रूप में एक राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी की स्थापना का प्रस्ताव करते हैं। यह सीबीएसई, एआईसीटीई और अन्य प्रमुख संस्थाओं को इन प्रशासनिक उत्तरदायित्वों से मुक्त कर देगी ताकि वे शैक्षिक कार्यों पर अधिक ध्यान दे सकें।

53. हमारे पास बहुत बड़ा जनसांख्यिकी फायदा है। अपने युवाओं की क्षमता को अधिकतम बढ़ाने के लिए जुलाई, 2015 में स्किल इंडिया मिशन प्रारंभ किया गया था।

54. प्रधानमंत्री कौशल केंद्रों (पीएमकेके) को पहले ही 60 से ज्यादा जिलों में शुरू किया जा चुका है। हम अब देश भर में 600 से ज्यादा जिलों में इन केंद्रों का विस्तार करने का प्रस्ताव करते हैं। देश भर में 100 भारत अंतरराष्ट्रीय कौशल केंद्र स्थापित किए जाएंगे। ये केंद्र उन्नत प्रशिक्षण और विदेशी भाषाओं में भी पाठ्यक्रम पेश करेंगे। यह हमारे उन युवकों की सहायता करेंगे जो देश से बाहर नौकरी के अवसर तलाश रहे हैं।

55. हम 2017-18 में ₹4000 करोड़ की लागत से आजीविका संवर्धन हेतु कौशल अर्जन और ज्ञान जागरूकता कार्यक्रम (संकल्प) शुरू करने का भी प्रस्ताव करते हैं। **संकल्प** ₹3.5 करोड़ युवाओं को बाजार संगत प्रशिक्षण प्रदान करेगा।

56. औद्योगिक मूल्यवर्द्धन हेतु कौशल सुदृढीकरण (**स्ट्राईव**) का अगला चरण भी 2017-18 में ₹2,200 करोड़ खर्च करके शुरू किया जाएगा। **स्ट्राईव** का ध्यान औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों (आईटीआई) में दिए जा रहे व्यावसायिक प्रशिक्षण की गुणवत्ता और बाजार संगतता में सुधार करने और उद्योग समूह दृष्टिकोण के जरिए प्रशिक्षु पाठ्यक्रमों के सुदृढीकरण पर होगा।

57. कपड़ा क्षेत्र में रोजगार सृजन का विशेष कार्यक्रम पहले ही शुरू किया जा चुका है। इसी तरह की स्कीम चमड़ा और फुटवियर उद्योग के लिए क्रियान्वित की जाएगी।

58. पर्यटन बड़ा रोजगार सृजक है और इसका अर्थव्यवस्था पर गुणक प्रभाव पड़ता है। राज्यों की भागीदारी से विशेष प्रयोजन साधनों (एसपीवी) पर निर्भर रहते हुए पांच विशेष पर्यटन क्षेत्र स्थापित किए जाएंगे। पूरे विश्व में अतुल्य भारत 2.0 अभियान शुरू किया जाएगा।

IV. गरीब तथा विशेष सुविधाओं से वंचित वर्ग

59. अध्यक्ष महोदया, मैं अब गरीबों और वंचितों के लिए अपने प्रस्तावों की ओर आता हूं।

60. सबका साथ सबका विकास बालिका और महिलाओं से शुरू होता है। गांव स्तर पर 14 लाख आईसीडीएस आंगनवाड़ी केंद्रों में ₹500 करोड़ के आवंटन से महिला शक्ति केंद्र स्थापित किए जाएंगे। यह ग्रामीण महिलाओं के सशक्तिकरण हेतु कौशल विकास, रोजगार, डिजिटल साक्षरता, स्वास्थ्य और पोषाहार के अवसरों के लिए 'वन स्टाप' सामुहिक सहायता सेवाएं प्रदान करेगा। माननीय प्रधानमंत्री द्वारा 31 दिसम्बर, 2016 को गर्भवती महिलाओं को वित्तीय सहायता की राष्ट्रव्यापी स्कीम की घोषणा पहले ही की जा चुकी है। इस स्कीम के अंतर्गत उस गर्भवती महिला के बैंक खाते में सीधे 6,000 रुपए अंतरित कर दिए जाएंगे जो किसी चिकित्सा संस्था में बच्चे को जन्म देगी और अपने बच्चों का टीकाकरण कराएगी।

61. मैंने सभी मंत्रालयों की विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत महिला और बाल विकास के लिए आवंटन बजट अनुमान 2016-17 में ₹1,56,528 करोड़ से बढ़ाकर बजट अनुमान 2017-18 में ₹1,84,632 करोड़ कर दिया है।

62. हम सस्ते आवासों में अधिक निवेश सुसाध्य बनाने का प्रस्ताव करते हैं। सस्ते आवासों को अब संरचना का दर्जा दिया जाएगा जो इन परियोजनाओं को इनसे संबंधित लाभ लेने में समर्थ बनाएगा।

- 63.** राष्ट्रीय आवास बैंक 2017-18 में लगभग ₹20,000 करोड़ के व्यष्टि आवास ऋणों का पुनर्वित्तपोषण करेगा। विमुद्रीकरण से उत्पन्न अधिक नकदी को धन्यवाद कि बैंकों ने आवासों सहित अपनी उधार देने की दरें पहले ही कम करनी शुरू कर दी हैं। इसके अतिरिक्त, माननीय प्रधानमंत्री द्वारा आवास ऋणों के लिए ब्याज सहायता की घोषणा भी की गई है।
- 64.** गरीबी सामान्यतया कमजोर स्वास्थ्य से जुड़ी होती है। यह गरीब ही होते हैं जो विभिन्न दीर्घकालिक बीमारियों से सबसे अधिक पीड़ित होते हैं। इसलिए सरकार ने 2017 तक कालाजार और फिलारियासिस, 2018 तक कोढ़ और 2020 तक खसरा समाप्त करने की कार्य योजना तैयार की है। 2025 तक तपेदिक समाप्त करने का लक्ष्य भी है। इसी तरह, आईएमआर 2014 में 39 से घटाकर 2019 तक 28 और एमएमआर 2011-13 में 167 से घटाकर 2018-2020 तक 100 करने के लिए कार्य योजना बनाई गई है। 1.5 लाख स्वास्थ्य उप-केंद्रों को स्वास्थ्य और तंदुरुस्ती केंद्रों में बदला जाएगा।
- 65.** हमें द्वितीयक और तृतीयक स्तरों की स्वास्थ्य देखभाल सुदृढ़ करने के लिए विशेषज्ञ डाक्टरों की समुचित उपलब्धता सुनिश्चित करने की जरूरत होगी। इसलिए हमने प्रति वर्ष अतिरिक्त 5,000 स्नातकोत्तर सीटें सृजित करने का निर्णय लिया है। इसके अतिरिक्त, बड़े जिला अस्पतालों में डीएनबी पाठ्यक्रम शुरू करने; चुनिंदा ईएसआई और नगर निगमों के अस्पतालों में स्नातकोत्तर शिक्षण सुदृढ़ करने और ख्यातिप्राप्त निजी अस्पतालों को डीएनबी पाठ्यक्रम शुरू करने के लिए प्रोत्साहित करने हेतु उपाय किए जाएंगे। हम राज्य सरकारों के साथ मिलकर इन कार्यों को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। सरकार भारत में चिकित्सा, शिक्षा और प्रैक्टिस के विनियामक ढांचे के संरचनात्मक परिवर्तन के लिए आवश्यक कदम उठाने के लिए वचनबद्ध है।
- 66.** झारखंड और गुजरात में दो नए अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान स्थापित किए जाएंगे।
- 67.** हम औषधियों की उपलब्धता किफायती कीमतों पर सुनिश्चित करने तथा जेनेरिक औषधियों को बढ़ावा देने के लिए औषध और सौंदर्य प्रसाधन नियमावली में संशोधन करने का प्रस्ताव करते हैं। चिकित्सा उपकरणों को विनियमित करने के लिए नई नियमावली भी तैयार की जाएगी। ये नियम अंतरराष्ट्रीय नियमानुसार होंगे और इस क्षेत्र में निवेश आएगा। इससे इन उपकरणों की लागत कम होगी।
- 68.** हम एक श्रमानुकूल माहौल बनाना चाहते हैं जहां श्रमिक अधिकारों की रक्षा होगी और सौहार्दपूर्ण संबंधों से उत्पादकता में बढ़ोतरी होगी। मौजूदा श्रम कानूनों को सरल और युक्तिसंगत बनाने तथा इन्हें (i) वेतन (ii) औद्योगिक संबंध (iii) सामाजिक सुरक्षा और कल्याण तथा (iv) सुरक्षा और कार्य स्थितियों पर 4 संहिताओं में सम्मिलित करने के लिए विधायी सुधार किए जाएंगे। आदर्श दुकान और स्थापना विधेयक, 2016 पर विचार करने और इसे अपनाने के लिए सभी राज्यों को परिचालित किया गया है। इससे महिला रोजगार के अतिरिक्त रास्ते खुलेंगे। वेतन भुगतान अधिनियम में किया गया संशोधन श्रमिकों और इज़ आफ डूईंग बिजनेस के लाभार्थ हमारी सरकार द्वारा की गई एक और पहल है।
- 69.** हमारी सरकार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अल्पसंख्यकों के कल्याण की योजनाओं के क्रियान्वयन को विशेष महत्व दे रही है। अनुसूचित जातियों के कल्याण के लिए किया जाने वाला आवंटन बजट अनुमान 2016-17 में ₹38,833 करोड़ से बढ़ाकर 2017-18 में ₹52,393 करोड़ किया गया है जो लगभग 35 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाता है। अनुसूचित जनजातियों के लिए किया जाने वाला आवंटन बढ़ाकर ₹31,920 करोड़ किया गया है और अल्पसंख्यक मामलों का आवंटन ₹4,195 करोड़ किया गया है। सरकार नीति आयोग द्वारा इन क्षेत्रों में व्यय की परिणाम आधारित निगरानी की शुरुआत करेगी।
- 70.** वरिष्ठ नागरिकों के लिए आधार आधारित स्मार्ट कार्ड योजना की शुरुआत की जाएगी जिसमें उनका स्वास्थ्य संबंधी ब्यौरा दर्ज होगा। वर्ष 2017-18 के दौरान 15 जिलों में प्रायोगिक योजना के जरिए इसकी शुरुआत की जाएगी। एलआईसी वरिष्ठ नागरिकों के लिए निश्चित पेंशन की योजना क्रियान्वित करेगी जिसमें 10 वर्ष के लिए 8 प्रतिशत प्रति वर्ष का गारंटीकृत प्रतिलाभ मिलेगा।

V. अवसंरचना

71. टेक इंडिया एजेंडा का पांचवा घटक अवसंरचना है।

72. रेलवे, सड़कें और नदियां देश की जीवन रेखा हैं। यह मेरा सौभाग्य है कि मैं स्वतंत्र भारत का पहला संयुक्त बजट प्रस्तुत कर रहा हूं जिसमें रेलवे भी शामिल है। अब हम ऐसी स्थिति में हैं कि हम निवेश को रेलवे, सड़कों, जलमार्गों और नागर विमानन में लगा सकते हैं। वर्ष 2017-18 के लिए, रेलवे की कुल पूंजी और विकास संबंधी व्यय ₹1,31,000 करोड़ रखा गया है। इसमें सरकार द्वारा मुहैया कराए गए ₹55,000 करोड़ शामिल हैं।

73. अन्य बातों में, रेलवे चार प्रमुख क्षेत्रों पर अपना फोकस रखेगी, जो इस प्रकार हैं :

- (i) यात्री सुरक्षा
- (ii) पूंजीगत और विकास कार्य
- (iii) स्वच्छता; और
- (iv) वित्त और लेखा सुधार

74. यात्री सुरक्षा के लिए, 5 वर्ष की अवधि में ₹1 लाख करोड़ रुपए की निधि से एक राष्ट्रीय रेल सुरक्षा कोष सृजित किया जाएगा। सरकार से प्राप्त मूल पूंजी के अलावा रेलवे अपने स्वयं के राजस्व और अन्य स्रोतों से शेष संसाधनों की व्यवस्था करेगा। सरकार इस कोष से वित्तपोषण किए जाने वाले विभिन्न सुरक्षा संबंधी कार्यों के क्रियान्वयन हेतु स्पष्ट दिशानिर्देश और समय-सीमा निर्धारित करेगी। ब्राड गेज लाइनों पर मानव रहित लेवल क्रॉसिंग को 2020 तक समाप्त किया जाएगा। सुरक्षा तैयारी और अनुरक्षण व्यवहार को बेहतर बनाने के लिए अंतरराष्ट्रीय विशेषज्ञों की सहायता ली जाएगी।

75. अगले तीन वर्षों में, समग्र परिणाम में 10 प्रतिशत की वृद्धि किए जाने का प्रस्ताव है। इसे चिह्नित कॉरिडोरों के आधुनिकीकरण और उन्नयन के जरिए किया जाएगा। वर्ष 2016-17 में 2,800 किमी रेलवे लाइनों की तुलना में 2017-18 में 3,500 किमी लाइनें शुरू की जाएंगी। पर्यटन और तीर्थाटन के लिए समर्पित रेलगाड़ियां शुरू करने के लिए कदम उठाए जाएंगे।

76. रेलवे ने 9 राज्य सरकारों के साथ संयुक्त उद्यमों की स्थापना की है। निर्माण और विकास के लिए 70 परियोजनाओं की पहचान की गई है।

77. स्टेशनों के पुनर्विकास के संबंध में शुरुआत की जा चुकी है। स्टेशनों के पुनर्विकास के लिए 2017-18 के दौरान कम से कम 25 स्टेशनों का चयन किए जाने की संभावना है। लिफ्ट और एस्कलेटर्स की व्यवस्था करके 500 स्टेशन दिव्यांगजन अनुकूल बनाए जाएंगे।

78. मध्यावधिक संदर्भ में 7,000 स्टेशनों पर सौर विद्युत की व्यवस्था करने का प्रस्ताव है। 300 स्टेशनों में पहले ही इसकी शुरुआत की जा चुकी है। 1000 मेगावाट सौर मिशन के भाग के रूप में 2,000 रेलवे स्टेशनों के लिए कार्य शुरू किया जाएगा।

79. हमारा ध्यान स्वच्छ रेल पर है। एसएमएस आधारित 'क्लीन माई कोच सेवा' शुरू की गई है। अब, कोच संबंधी सभी शिकायतों और जरूरतों को दर्ज करने के लिए एक एकल विंडो प्रणाली 'कोच मित्र' सुविधा की शुरुआत किए जाने का प्रस्ताव है। वर्ष 2019 तक, भारतीय रेल के सभी कोचों में जैव शौचालय लगाए जाएंगे। ठोस अपशिष्ट के पर्यावरण अनुकूल निपटान और जैविक अपशिष्ट को ऊर्जा में परिवर्तित करने के लिए प्रायोगिक संयंत्रों को नई दिल्ली और जयपुर रेलवे स्टेशनों पर स्थापित किया जा रहा है। इस प्रकार के पांच और ठोस अपशिष्ट प्रबंधन संयंत्रों पर कार्य किया जा रहा है।

80. इस समय भारतीय रेल निजी क्षेत्र के वर्चस्व वाले परिवहन के अन्य साधनों से कठिन प्रतिस्पर्धा का सामना कर रही है। भारतीय रेलवे को प्रतिस्पर्धी बनाने के लिए इसके कार्यापलट के उपाय किए जाने होंगे ताकि यह अपनी पूर्व प्रतिष्ठा प्राप्त कर सके। अतः निम्नलिखित कदम उठाए जाएंगे :

(i) रेलवे लॉजिस्टिक क्षेत्र के उद्यमियों, जो फ्रंट और बैक एंड कनेक्टिविटी मुहैया कराएंगे, के साथ भागीदारी के माध्यम से चुनिंदा वस्तुओं के लिए एंड टू एंड एकीकृत परिवहन समाधान क्रियान्वित करेगा। नाशवान वस्तुओं, विशेषकर कृषि उत्पादों के परिवहन हेतु चल स्टॉक और प्रचालनात्मक पद्धतियों को कस्टमाइज्ड किया जाएगा।

(ii) रेलवे जनता के लिए प्रतिस्पर्धी टिकट बुकिंग सुविधा की पेशकश करेगा। आईआरसीटीसी के जरिए आरक्षित किए गए ई-टिकटों पर लगाए जाने वाला सेवा प्रभार समाप्त किया गया है। कैशलेस आरक्षण 58% से बढ़कर 68% हो गए हैं।

(iii) लेखांकन सुधारों के भाग के रूप में, मार्च 2019 तक प्रोद्भूत आधारित वित्तीय विवरणों की शुरुआत की जाएगी।

81. रेलवे के प्रचालन अनुपात को बेहतर करने के लिए हम निरंतर प्रयास करेंगे। लागत, सेवा की गुणवत्ता, सामाजिक दायित्वों और परिवहन के अन्य साधनों से प्रतिस्पर्धा पर विचार करते हुए रेलवे के टैरिफ को निर्धारित किया जाएगा।

82. मेट्रो रेल शहरी परिवहन के महत्वपूर्ण साधन के रूप में उभर रही है। क्रियान्वयन और वित्तपोषण के साथ-साथ हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के मानकीकरण और स्वदेशीकरण के नए मॉडल पर फोकस के साथ नई मेट्रो रेल नीति की घोषणा की जाएगी। इससे हमारे युवा वर्ग को नए रोजगार अवसर प्राप्त होंगे।

83. मौजूदा कानूनों को युक्तिसंगत बनाकर एक नया मेट्रो रेल अधिनियम अधिनियमित किया जाएगा। इससे निर्माण और संचालन में बेहतर निजी भागीदारी और निवेश का कार्य सुकर होगा।

84. सड़क क्षेत्र में, मैंने राजमार्गों के लिए बजट आवंटन को बजट अनुमान 2016-17 के ₹57,976 करोड़ से बढ़ाकर वर्ष 2017-18 में ₹64,900 करोड़ कर दिया है। तटीय क्षेत्रों को जोड़ने वाली 2000 किलोमीटर सड़कों को निर्माण और विकास के लिए चुना गया है। उससे बंदरगाहों और दूरदराज के गांवों को जोड़ने का कार्य और अधिक सुकर होगा। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत सड़कों को शामिल करते हुए वर्ष 2014-15 से चालू वर्ष तक बनाई गई सड़कों की कुल लंबाई लगभग 1,40,000 किलोमीटर है जो कि इससे पिछले तीन वर्षों की तुलना में काफी अधिक है।

85. एक प्रभावशाली बहु-रूपात्मक लोजिस्टिक्स और परिवहन क्षेत्र हमारी अर्थव्यवस्था को और अधिक प्रतिस्पर्द्धात्मक बनाएगा। बहु-रूपात्मक परिवहन सुविधाओं के साथ बहु-रूपात्मक लोजिस्टिक्स पार्कों के विकास के लिए एक विशिष्ट कार्यक्रम की रूपरेखा तैयार करके इसे शीघ्र कार्यान्वित किया जाएगा।

86. श्रेणी-2 के शहरों के चुनिंदा हवाई अड्डों के संचालन और रख-रखाव को सरकारी निजी भागीदारी के अंतर्गत लाया जाएगा। भू-संपत्तियों के प्रभावी मुद्रीकरण के लिए भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण अधिनियम को संशोधित किया जाएगा। इससे जुटाए जाने वाले संसाधनों को हवाई अड्डों के उन्नयन के लिए उपयोग में लाया जाएगा।

87. समूचे परिवहन क्षेत्र के लिए, जिसमें रेल, सड़कें और पोत परिवहन शामिल हैं, मैंने 2017-18 के लिए ₹2,41,387 करोड़ का प्रावधान किया है। निवेश की इतनी बड़ी राशि से देश भर में प्रचूर मात्रा में आर्थिक क्रियाकलापों का मार्ग प्रशस्त होगा और रोजगार के अधिक अवसर उत्पन्न होंगे।

88. दूरसंचार क्षेत्र हमारे ढांचागत ईको तंत्र का एक महत्वपूर्ण घटक है। हाल ही में हुई स्पेक्ट्रम की नीलामियों से देश में स्पेक्ट्रम का अभाव दूर हुआ है। इससे मोबाइल ब्रांडबैंड और डिजिटल भारत को काफी बढ़ावा मिलेगा और ग्रामीण व दूरदराज के क्षेत्रों में रह रहे लोग इससे लाभान्वित होंगे।

89. भारतनेट परियोजना के तहत 1,55,000 किलोमीटर लंबे क्षेत्र में ऑप्टिकल फाइबर केबल बिछाई गई है। मैंने भारतनेट परियोजना के लिए आवंटन को बढ़ाकर 2017-18 में ₹10,000 करोड़ कर दिया है। 2017-18 के अंत तक, 1,50,000 से भी अधिक ग्राम पंचायतों में ऑप्टिकल फाइबर पर हाई स्पीड ब्रांडबैंड कनेक्टिविटी उपलब्ध कराई जाएगी जिसमें वाई फाई हॉट स्पॉट्स और निम्न प्रशुल्कों पर डिजिटल सेवाओं तक पहुंच भी शामिल है। डिजिटल प्रौद्योगिकी के माध्यम से टेली-मेडिसिन, शिक्षा और कौशल विकास के प्रावधान के लिए 'डिजीगांव' नामक पहल शुरू की जाएगी।

90. हमारे ऊर्जा क्षेत्र को सुदृढ़ करने के लिए सरकार ने कच्चे तेल के सामरिक भंडार स्थापित करने का निर्णय लिया है। प्रथम चरण में, ऐसे तीन तेल भंडारों की सुविधाएं स्थापित की गई हैं। अब दूसरे चरण में, दो और स्थानों नामतः ओडिशा में चंडीखोले और राजस्थान में बीकानेर में कंदराएं स्थापित करने का प्रस्ताव है। इससे हमारी सामरिक तेल भंडार क्षमता 15.33 मिलियन मीट्रिक टन तक पहुंच जाएगी।

91. सौर ऊर्जा में, अब हमारा प्रस्ताव 20,000 मेगावाट की अतिरिक्त क्षमता के लिए सौर पार्क विकास के दूसरे चरण को प्रारंभ करने का है।

92. हम भारत को इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण का वैश्विक हब बनाने के लिए ईको सिस्टम भी तैयार कर रहे हैं। पिछले दो वर्षों में इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण के 250 से अधिक निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं जिनमें कुल ₹1.26 लाख करोड़ की निवेश राशि शामिल है। विश्व के अनेक अग्रणी निवेशकों और मोबाइल विनिर्माताओं ने भारत में उत्पादन सुविधाएं स्थापित की हैं। अतः मैंने एम-सिप्स और ईडीएफ जैसी प्रोत्साहन योजनाओं के लिए 2017-18 के आवंटन को पर्याप्त रूप से बढ़ाते हुए ₹745 करोड़ कर दिया है। यह इस क्षेत्र में अब तक का सर्वाधिक आवंटन है।

93. हमें इस प्रतिस्पर्धात्मक दुनिया में अपने निर्यात ढांचे पर विशेष तौर पर ध्यान देना होगा। 'निर्यात के लिए व्यापार अवसंरचना योजना (टाइज)' नामक एक नई और पुनः तैयार की गई केंद्रीय योजना 2017-18 में प्रारंभ की जाएगी।

94. वर्ष 2017-18 में अवसंरचनात्मक विकास के लिए किया गया कुल आवंटन ₹3,96,135 करोड़ है।

VI. वित्तीय क्षेत्र

95. अब मैं वित्तीय क्षेत्र पर लौटता हूं। इस क्षेत्र में टीईसी भारत एजेंडा में स्थिर और सुदृढ़ संस्थाओं के निर्माण पर विशेष बल दिया गया है। हम अनेक नए उपायों के जरिए अपने सुधारों का एजेंडा जारी रखेंगे।

96. हमारी सरकार ने पिछले दो वर्षों में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की नीति में पर्याप्त सुधार किए हैं। प्रत्यक्ष विदेशी निवेश में होने वाले कुल आगम का 90% से अधिक भाग स्वचालित मार्ग के माध्यम से आता है। विदेशी निवेश संवर्धन बोर्ड ने प्रत्यक्ष विदेशी निवेश संबंधी आवेदनों की ई-फाइलिंग और ऑनलाइन प्रोसेसिंग का कार्य सफलतापूर्वक कार्यान्वित किया है। अब हम ऐसी स्थिति में हैं कि विदेशी निवेश संवर्धन बोर्ड को चरणबद्ध तरीके से समाप्त किया जा सकता है। इसलिए हमने 2017-18 में इसे समाप्त करने का निर्णय लिया है। इसके लिए रोडमैप अगले कुछ महीनों में घोषित किया जाएगा। इस बीच, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश नीति को और अधिक उदार बनाने पर विचार किया जा रहा है और यथासमय आवश्यक घोषणाएं की जाएंगी।

97. वस्तु बाजारों में किसानों के लाभ के लिए और अधिक सुधार लाने की आवश्यकता है। वस्तुओं के व्यापार के लिए हाजिर बाजार और व्युत्पन्न बाजार को समेकित करने के लिए प्रचालन और विधायी ढांचे पर अध्ययन करने और इसके सृजन को बढ़ावा देने के लिए एक विशेषज्ञ समित गठित की जाएगी। ई-नाम इस ढांचे का एक अभिन्न अंग होगा।

98. अवैध जमा योजनाओं के संकट को कम करने के लिए मसौदा विधेयक को लोगों की जानकारी में लाया जाएगा और इसे अंतिम रूप दिए जाने के बाद शीघ्र ही लागू किया जाएगा। यहां गरीब और भोले-भाले निवेशकों को बहु राज्य सहकारी सोसायटी अधिनियम, 2002 के विनियामक दोषों का लाभ उठाने वाली बेइमानी कंपनियों द्वारा प्रचालित अनेक संदिग्ध योजनाओं से बचाने की तत्काल आवश्यकता है। हम 'स्वच्छ भारत' के अपने एजेंडे के रूप में विभिन्न हितधारकों के परामर्श से इस अधिनियम में संशोधन करेंगे।

99. वित्तीय फर्मों के समाधान से संबंधित विधेयक को संसद के वर्तमान बजट सत्र में पेश किया जाएगा। इससे हमारे वित्तीय तंत्र को स्थिरता और लचीलापन मिलेगा। इससे विभिन्न वित्तीय संस्थाओं के उपभोक्ताओं के हितों की भी रक्षा होगी। शोधन अक्षमता और दिवालियापन संहिता के साथ-साथ वित्तीय फर्मों के लिए समाधान तंत्र से हमारे देश में समाधान प्रणाली की व्यापकता सुनिश्चित होगी।

100. मैंने अपने पिछले बजट भाषण में कहा था कि निर्माण संविदाओं, सरकारी निजी भागीदारी और जनोपयोगी सुविधा संबंधी संविदाओं से संबंधित अवसंरचना में विवादों के समाधान के लिए संस्थागत व्यवस्थाओं को कारगर बनाने के लिए विधेयक पेश किया जाएगा। हितधारकों के साथ गहन परामर्श के बाद, हमने निर्णय लिया है कि अपेक्षित तंत्र को विवाचन और समाधान अधिनियम, 1996 के हिस्से के रूप में संस्थापित किया जाएगा। इस संबंध में संशोधन विधेयक लाया जाएगा।

101. हमारे वित्तीय क्षेत्र की सत्यनिष्ठा और स्थिरता को सुरक्षित रखने के लिए साइबर सुरक्षा अति महत्वपूर्ण है। हमारे वित्तीय क्षेत्र के लिए कम्प्यूटर एमरजेंसी रेस्पॉन्स टीम (सर्ट-फिन) स्थापित की जाएगी। यह निकाय सभी वित्तीय क्षेत्र के विनियामकों और अन्य हितधारकों के सन्निकट समन्वयन में कार्य करेगा।

102. मैंने वित्तीय सेक्टर में अनेक अन्य उपायों का भी प्रस्ताव रखा है, जिन्हें अनुबंध-1 में सूचीबद्ध किया गया है।

103. सरकारी क्षेत्र के उद्यमों को सूचीबद्ध करने से बेहतर सरकारी जवाबदेही को बढ़ावा मिलेगा और यह इन कंपनियों के वास्तविक मूल्य को उजागर करेगा। स्टॉक एक्सचेंजों में चिह्नित केंद्रीय सरकारी क्षेत्र के उद्यमों को समयबद्ध रूप से सूचीबद्ध करना सुनिश्चित करने के लिए सरकार संशोधित तंत्र और प्रक्रिया लागू करेगी। पिछले बजट में मेरे द्वारा घोषित विनिवेश नीति जारी रहेगी।

104. आईआरसीटीसी, आईआरएफसी और इरकोन जैसे सरकारी क्षेत्र के रेलवे उद्यमों के हिस्से को स्टॉक एक्सचेंजों में सूचीबद्ध किया जाएगा।

105. हम, समेकन विलय, और अधिग्रहणों के जरिए हमारे केंद्रीय सरकारी क्षेत्र के उद्यमों को सुदृढ़ करने का सुअवसर देख रहे हैं। इन विधियों के द्वारा उद्योग की मूल्य श्रृंखला में केंद्रीय सरकारी क्षेत्र के उद्यमों को एकीकृत किया जा सकता है। यह उन्हें अपेक्षाकृत अधिक जोखिम बर्दाश्त करने, उच्चतर किफायतें प्राप्त करने, अधिक निवेश के निर्णय लेने और पणधारकों के लिए अधिक मूल्य का सृजन करने की क्षमता प्रदान करेगा। तेल और गैस सेक्टर में ऐसी पुनर्संरचना की संभावना दिखाई दे रही है। हम, एकीकृत सरकारी क्षेत्र 'ऑयल मेजर' के सृजन का प्रस्ताव करते हैं, जो अंतरराष्ट्रीय और घरेलू निजी सेक्टर की तेल और गैस कंपनियों जैसा निष्पादन करने में सक्षम होगा।

106. हमारे ईटीएफ, जिसमें दस सीपीएसई के शेयर शामिल किए गए हैं, को हालिया और निधि की पेशकश में आश्चर्यजनक प्रतिक्रिया मिली है। हम शेयरों के और आगे विनिवेश के लिए माध्यम के रूप में ईटीएफ का उपयोग करते रहेंगे। तदनुसार, विविधीकृत सीपीएसई स्टॉकों और अन्य सरकारी धारिता के साथ एक नया ईटीएफ 2017-18 में शुरू किया जाएगा।

107. बैंकों के तनावग्रस्त धरोहर खातों के समाधान पर विशेष ध्यान केंद्रित करना जारी रहेगा। शोधन अक्षमता और दिवालियापन संहिता के अधिनियम और सरफेसी तथा ऋण वसूली अधिकरण अधिनियमों में संशोधन करके समाधान सुसाध्य बनाने हेतु कानूनी ढांचे को मजबूत बनाया गया है। 'इंद्रधनुष' कार्य योजना की तर्ज पर 2017-18 में बैंकों के पुनर्पूजीकरण के लिए मैंने ₹10,000 करोड़ का प्रावधान किया है। आवश्यकता पड़ने पर इसके लिए अतिरिक्त आवंटन किया जाएगा।

108. सरफेसी अधिनियम के तहत किसी प्रतिभूति कंपनी अथवा किसी पुनर्निर्माण कंपनी द्वारा निर्गमित प्रतिभूति प्राप्तियों की लिस्टिंग और व्यापार की सेबी में पंजीकृत स्टॉक एक्सचेंजों की अनुमति दी जाएगी। इससे प्रतिभूति उद्योग में पूंजी प्रवाह के लिए प्रोत्साहन मिलेगा और विशेष रूप से बैंकों की अनर्जक आस्तियों के निपटान में सहायता मिलेगी।

109. प्रधानमंत्री मुद्रा योजना का निधिपोषित न किए गए और कम निधिपोषित के निधियन के लिए उल्लेखनीय योगदान रहा। पिछले वर्ष, ₹1.22 लाख करोड़ का लक्ष्य पार हो गया था। 2017-18 के लिए मैं, 2015-16 के ऋण देने के लक्ष्य को दोगुना करके ₹2.44 लाख करोड़ करने का प्रस्ताव करता हूं। इसमें दलितों, जनजातियों, पिछड़े वर्गों, अल्पसंख्यकों और महिलाओं को प्राथमिकता दी जाएगी।

110. दलितों, जनजातियों और महिला उद्यमियों को हरित क्षेत्र उद्यम स्थापित करने तथा रोजगार सृजक बनने में सहायता करने के लिए हमारी सरकार द्वारा स्टैंड-अप इंडिया स्कीम का शुभारंभ अप्रैल, 2016 में किया गया था। इस स्कीम के जरिए 16,000 से अधिक नए उद्यमी खाद्य प्रसंस्करण, परिधान, नैदानिक केंद्र जैसे विविध क्रियाकलाप करने लगे।

VIII. डिजिटल अर्थव्यवस्था

111. तंत्र को स्वच्छ बनाने और भ्रष्टाचार तथा काले धन का खात्मा करने के लिए डिजिटल अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देना सरकार की कार्य नीति का अभिन्न अंग है। अर्थव्यवस्था को बेहतर रूप से औपचारिक बनाने और बैंकिंग पद्धति में वित्तीय बचतों को मुख्य धारा से जोड़ने के संदर्भ में, इसका परिवर्तनकारी प्रभाव पड़ता है। इससे, ऋण की कम लागत के द्वारा देश में निजी निवेश को शक्तिशाली बनाने की संभावना है। इस समय भारत में वृहत डिजिटल आन्दोलन शीर्ष पर है।

112. डिजिटल भुगतान की शुरुआत से आम आदमी को बहुत लाभ हुआ है। हमारी सरकार की वित्तीय समावेशन और जन धन आधार मोबाइल त्रिसूत्र को बढ़ावा देने के पहले के प्रयास डिजिटल लेन-देन को वर्तमान में आगे बढ़ाने के लिए महत्वपूर्ण प्रेरक थे।

113. बढ़े हुए डिजिटल लेन-देन के प्रमाण हैं। भीम ऐप शुरू किया गया है। यह डिजिटल भुगतान और वित्तीय समावेशन के लिए मोबाइल फोनों की शक्ति बढ़ाएगा। अब तक 125 लाख लोगों ने भीम ऐप को अपनाया है। भीम के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए सरकार दो नई स्कीमें शुरू करेगी; ये हैं व्यष्टियों के लिए रेफरल बोनस स्कीम और व्यापारियों के लिए कैशबैक स्कीम।

114. आधार भुगतान, आधार समर्थित भुगतान प्रणाली का व्यापारिक संस्करण, जल्द ही आरंभ किया जाएगा। यह उन लोगों के लिए विशेषरूप से फायदेमंद होगा, जिनके पास डेबिट कार्ड, मोबाइल वॉलेट और मोबाइल फोन नहीं हैं। यूपीआई, यूएसएसडी, आधार भुगतान, आईएमपीएस और डेबिट कार्डों के जरिए 2017-18 के लिए 2,500 करोड़ डिजिटल लेनदेन के लक्ष्य के साथ एक मिशन की स्थापना की जाएगी। बैंकों ने, मार्च, 2017 तक अतिरिक्त 10 लाख नए पीओएस टर्मिनल शुरू करने का लक्ष्य रखा है। उन्हें, सितम्बर, 2017 तक 20 लाख आधार पर आधारित पीओएस शुरू करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा।

115. बढ़े हुए डिजिटल लेनदेन, लघु और सूक्ष्म उद्यमों का औपचारिक ऋण सुलभता के लिए समर्थ बनाएगा। उधारकर्ताओं के लेनदेन संबंधी पूर्ववृत्त के आधार पर उन्हें उचित ब्याज दरों पर प्रतिभूति रहित ऋण प्रदान करने वाली क्रेडिट संस्थाओं को पुनर्वित्त प्रदान करने के लिए सिडबी को सरकार प्रोत्साहित करेगी।

116. डिजिटल भुगतान अवसंरचना और शिकायत निवारण तंत्रों को सुदृढ़ किया जाना चाहिए। डाक घरों, उचित मूल्य की दुकानों और बैंकिंग संपर्कों के माध्यम से ग्रामीण और अर्धशहरी क्षेत्रों पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। भीम ऐप सहित पेट्रोल पम्पों, उर्वरक डिपो, नगरपालिकाओं, ब्लॉक कार्यालयों, सड़क परिवहन कार्यालयों, विश्वविद्यालयों, महाविद्यालयों, अस्पतालों और अन्य संस्थाओं में डिजिटल भुगतान की सुविधाओं को बढ़ावा देने और संभवतः उन्हें अधिदेश देने के लिए कदम उठाए जाएंगे। प्राप्तियों को अधिदेशित करने के प्रस्ताव पर विचार किया जा रहा है।

117. इन पहलों को आगे बढ़ाने के लिए संसाधन बढ़ाने हेतु सरकार वित्तीय समावेशन निधि को सुदृढ़ करेगी।

118. डिजिटल लेनदेन संबंधी मुख्य मंत्रियों की समिति की अंतरिम सिफारिशों को शीघ्र कार्यान्वित करने के लिए सरकार विभिन्न पणधारकों के साथ विचार और काम करेगी।

119. आर्थिक कार्य विभाग द्वारा गठित डिजिटल भुगतान संबंधी समिति ने भुगतान और निपटान पद्धति अधिनियम, 2007 में संशोधन करने सहित भुगतान ईको प्रणाली में संरचनात्मक सुधारों की व्यापक समीक्षा करेगी और इसमें समुचित संशोधन करेगी। आरंभिक तौर पर, भुगतान तथा निपटान पद्धति के विनियमन और पर्यवेक्षण के लिए मौजूदा बोर्ड को प्रतिस्थापित करके भारतीय रिजर्व बैंक में भुगतान विनियामक बोर्ड का गठन करने का प्रस्ताव है। इसके लिए वित्त विधेयक, 2017 में आवश्यक संशोधन करने का प्रस्ताव है।

120. जैसे-जैसे हम डिजीटल लेनदेन और चैक भुगतान के पथ पर तेजी से बढ़ते हैं, हमें यह सुनिश्चित करने की जरूरत है कि बाउंडेड चैक को भुगतान प्राप्तकर्ता भुगतान लेने में समर्थ हो सकें इसलिए सरकार परक्राम्य लिखत अधिनियम में उपयुक्त संशोधन करने के लिए विकल्प पर विचार कर रही है।

VIII. सार्वजनिक सेवा

121. अब मैं सरकारी सेवा की ओर आता हूँ। यहां हमारा ध्यान प्रभावी सरकार और दक्ष सेवा अदायगी पर है।

122. हमने एलपीजी और केरोसीन उपभोक्ताओं को प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी) से संबंधित मजबूत शुरुआत की है। चंडीगढ़ और हरियाणा के आठ जिले केरोसीन मुक्त हो चुके हैं। 84 सरकारी योजनाओं पर भी डीबीटी प्लेटफार्म पर कार्य शुरू कर दिया गया है।

123. सरकारी ई-मार्केट स्थान, जो अब वस्तुओं और सेवाओं की खरीद के लिए कार्य कर रहा है, ने विश्व बैंक के साउथ एशिया प्राक्योरमेंट इन्नोवेशन अवार्ड्स के पुरस्कार विजेता के रूप में चुना गया है।

124. देश के दूर-दराज के क्षेत्रों में रहने वाले हमारे नागरिकों को पासपोर्ट बनवाने और इससे संबंधित शिकायतों का समाधान कराने में बड़ी कठिनाई उठानी पड़ती है। हमने मुख्य डाकघरों को, पासपोर्ट सेवाएं देने के लिए फ्रन्ट कार्यालयों के रूप में उपयोग करने का विनिश्चय किया है।

125. हमारे रक्षा बल देश को बाहरी और भीतरी दोनों प्रकार के खतरे से सुरक्षित रखते हैं। अब एक केंद्रीकृत रक्षा यात्रा प्रणाली विकसित की गई है, जिसके जरिए हमारे सैनिक और अधिकारी अपनी यात्रा टिकटें ऑनलाइन बुक कर सकते हैं। उन्हें रेलवे वारंट के साथ कतारों में खड़े होने की परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा।

126. रक्षा पेंशनरों के लिए वेब आधारित पारस्परिक पेंशन संवितरण प्रणाली स्थापित की जाएगी। इस प्रणाली से पेंशन संबंधी प्रस्ताव प्राप्त किए जाएंगे और केंद्रीकृत रूप से भुगतान किया जाएगा। इससे रक्षा पेंशनरों की शिकायतें कम होंगी।

127. इस समय हमारे नागरिकों, विशेषरूप से निर्धन और अभावग्रस्त वर्ग, को सरकारी भर्ती की बोझिल प्रक्रियाओं से गुजरना पड़ता है। इसमें एजेंसियों और परीक्षाओं की बहुलता है। हम एकल पंजीकरण प्रणाली और परीक्षा की द्विस्तरीय प्रणाली शुरू करने का प्रस्ताव करते हैं।

128. पिछले कुछ वर्षों से अधिकरणों की संख्या कई गुणा बढ़ जाने से कार्यों की अतिव्याप्ति हो गई है। हम इन अधिकरणों की संख्या को युक्तिसंगत बनाने और जहां-कहीं उचित हो, इन अधिकरणों को विलय करने का प्रस्ताव करते हैं।

129. पिछले कुछ समय में आर्थिक अपराधियों सहित, ऐसे कुछ बड़े अपराधियों, के मामले सामने आए हैं, जिनमें कानून की पकड़ से बचने के लिए कुछ लोग देश से पलायन कर गए हैं। हमें यह सुनिश्चित करना है कि कानून को अपना काम करने दिया जाए। अतः सरकार ऐसे व्यक्तियों की देश के भीतर स्थित संपत्तियों को तब तक जब्त करने के लिए विधायी परिवर्तन, या कोई नया कानून लाने पर भी विचार कर रही है जब तक वे समुचित विधिक मंच के क्षेत्राधिकार में उपस्थित न हो जाए। यह कहने की आवश्यकता नहीं है कि ऐसे मामलों में सभी आवश्यक सांविधानिक सुरक्षा उपायों का अनुसरण किया जाएगा।

130. हमारी सरकार, सरकारी सेवा के मानकों में सुधार लाने और पारदर्शी शासन के लिए प्रतिबद्धता बनाए रखेगी। जनता की सेवा करना राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की आजीवन प्रतिबद्धता थी। हम महात्मा की 150वीं जन्मशती की ओर बढ़ रहे हैं, हम इस समारोह को यथोचित ढंग से मनाने हेतु हरसंभव कदम उठाएंगे। इसके लिए माननीय प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय समिति बनाने का प्रस्ताव है। हम इस वर्ष चम्पारण सत्याग्रह के शताब्दी वर्ष को स्मरण उत्सव के रूप में मनाएंगे। भारत सरकार 2017 में साबरमती आश्रम की उपयुक्त तरीके से 100वीं वर्षगांठ मनाने के लिए गुजरात सरकार की सहायता करेगी। 200 वर्ष पूर्व 1817 में ओडिशा के खुर्दा में बक्शी जगबंधु के नेतृत्व में सैनिकों ने पराक्रमी विद्रोह किया था। हम इसका भी उपयुक्त ढंग से स्मरण उत्सव मनाएंगे।

IX. विवेकपूर्ण राजकोषीय प्रबंधन

131. अब मैं, 2017-18 के लिए बजट के संदर्भ में राजकोषीय स्थिति की ओर आता हूँ।

132. 2017-18 के बजट में ₹21.47 लाख करोड़ का कुल व्यय रखा गया है। व्यय के आयोजना-आयोजना भिन्न के वर्गीकरण को समाप्त करने से अब पूरा ध्यान राजस्व और पूंजी व्यय पर है। मैंने पूंजी व्यय के लिए आबंटन में पिछले वर्ष की तुलना में 25.4 प्रतिशत की बढ़ोतरी की है। इसके गुणात्मक प्रभाव होंगे और उच्चतर वृद्धि होगी। राज्यों और विधानसभा वाले संघ राज्य क्षेत्रों को बजट अनुमान 2016-17 में ₹3.60 लाख करोड़ की तुलना में कुल ₹4.11 लाख करोड़ के संसाधन अंतरित किए जा रहे हैं। महत्वपूर्ण क्षेत्रों और योजनाओं के लिए आबंटनों और राज्यों को संसाधनों के अंतरण का ब्यौरा मेरे भाषण के अनुबंध II में दिया गया है।

133. मैंने, 2017-18 में विभिन्न बजट घोषणाओं और अन्य नई योजनाओं को कार्यान्वित करने के लिए आर्थिक कार्य विभाग के अंतर्गत ₹3,000 करोड़ का प्रावधान किया है। पेंशनों को छोड़कर, रक्षा व्यय के लिए, मैंने रक्षा पूंजी हेतु ₹86,488 करोड़ सहित ₹2,74,114 करोड़ की राशि मुहैया कराई है। मैंने 2017-18 में वैज्ञानिक मंत्रालयों का आवंटन बढ़ाकर ₹37,435 करोड़ कर दिया है।

134. पहली बार, अन्य बजट दस्तावेजों के साथ, सभी मंत्रालयों और विभागों को शामिल करते हुए एक समेकित परिणाम बजट सभापटल पर रखा जा रहा है। इससे सरकारी व्यय की जवाबदेही में सुधार होगा।

135. एफआरबीएम समीक्षा समिति ने हाल ही में अपनी रिपोर्ट दे दी है। समिति ने विस्तृत कवायद की है और यह सिफारिश की है कि एक धारणीय ऋण पथ हमारी राजकोषीय नीति का मुख्य वृहत-आर्थिक एंकर होना चाहिए। समिति ने 2023 तक सामान्य सरकार के लिए 60 प्रतिशत के ऋण-सकल घरेलू उत्पाद का समर्थन किया है, जिसमें केंद्रीय सरकार के लिए 40 प्रतिशत और राज्य सरकारों के लिए 20 प्रतिशत का अंश शामिल है। समिति ने इस रूपरेखा के भीतर आगामी 3 वर्षों के लिए 3 प्रतिशत राजकोषीय घाटे को लिया है और अनुशंसा की है। समिति ने निर्धारित राजकोषीय घाटा लक्ष्य से स.घ.उ. के 0.5 प्रतिशत तक विचलन के लिए 'एस्केप क्लाजेज' की व्यवस्था भी की है। इन एस्केप क्लाजों का आश्रय लेने के लिए कार्रवाई के रूप में समिति ने "अप्रत्याशित राजकोषीय निहितार्थों के साथ अर्थव्यवस्था में 'दूरगामी संरचनात्मक सुधारों' को एक कारक के रूप में शामिल किया है। वर्तमान में इस एस्केप क्लाज का आह्वान करने का यह एक सुदृढ़ मामला है फिर भी मैं ऐसा करने से बच रहा हूँ। समिति की रिपोर्ट की ध्यानपूर्वक जांच की जाएगी और यथासमय समुचित निर्णय लिए जाएंगे।

136. तथापि, मैं आगामी तीन वर्षों के लिए समिति द्वारा अनुशंसित 3 प्रतिशत के राजकोषीय घाटे के रोडमैप की बात करता हूँ। मैंने सरकारी क्षेत्र में धीमे निवेश और मंद वैश्विक वृद्धि के संदर्भ में उच्चतर सरकारी व्यय की जरूरत पर विचार किया है। मैंने समिति की सिफारिश को ध्यान में रखा है कि विवेकपूर्ण राजकोषीय प्रबंधन के लिए स्थायी ऋण अंतर्निहित आधार होना चाहिए। इन सब पहलुओं पर विचार करते हुए, मैंने 2017-18 के लिए राजकोषीय घाटे को स.घ.उ. के 3.2 प्रतिशत पर रखा है और अगले वर्ष 3 प्रतिशत करने के लिए प्रतिबद्ध हूँ। इस क्रमिक दृष्टिकोण के साथ, मैंने सरकारी निवेश की आवश्यकताओं से समझौता किए बिना, राजकोषीय समेकन का अनुपालन सुनिश्चित किया है।

137. मैंने सरकार के निवल बाजार उधार को ₹3.48 लाख करोड़ तक पुनर्खरीद के पश्चात सीमित रखने के लिए पूरा ध्यान रखा है, जो पिछले वर्ष के 4.25 लाख करोड़ रुपए की तुलना में बहुत कम है। सबसे महत्वपूर्ण है कि बजट अनुमान 2016-17 में 2.3 प्रतिशत का राजस्व घाटा संशोधित अनुमान में 2.1 प्रतिशत तक कम हो गया है। अगले वर्ष के लिए राजस्व घाटा, एफआरबीएम अधिनियम द्वारा अधिदेशित 2 प्रतिशत की तुलना में 1.9 प्रतिशत तक रखा गया है।

138. अगले वर्ष में इन वित्तीय आंकड़ों, विशेष रूप से राजकोषीय घाटे में सुधार लाना हमारा प्रयास होगा जिसके लिए व्यय की गुणवत्ता और विमुद्रीकरण के कारण बैंकों में भारी नकद जमा राशि से उच्चतर कर वसूली पर अधिक ध्यान दिया जाएगा।

भाग-ख**अध्यक्ष महोदय,**

139. अब मैं अपने कर प्रस्ताव प्रस्तुत करता हूँ।

140. भारत का कर-सघट्ट अनुपात बेहद कम है, और प्रत्यक्ष कर-अप्रत्यक्ष कर अनुपात सामाजिक न्याय की दृष्टि से इष्टतम नहीं है। मैं आपके समक्ष कतिपय ऐसे आंकड़े प्रस्तुत करता हूँ जो यह इंगित करते हैं कि हमारा प्रत्यक्ष कर संग्रहण भारतीय अर्थव्यवस्था के आय और उपभोग पैटर्न के अनुरूप नहीं है। असंगठित क्षेत्र के रोजगार में लगे अनुमानित 4.2 करोड़ व्यक्तियों की तुलना में, वेतन से प्राप्त आय के संबंध में विवरणी प्रस्तुत करने वाले व्यक्तियों की संख्या केवल 1.74 करोड़ है। भारत में छोटे-मोटे कारोबार करने वाले अनौपचारिक क्षेत्र के व्यक्तिगत उद्यमों और फर्मों की संख्या 5.6 करोड़ होने के विपरीत, इस श्रेणी द्वारा प्रस्तुत विवरणियों की संख्या केवल 1.81 करोड़ है। भारत में 31 मार्च, 2014 तक पंजीकृत 13.94 लाख कंपनियों में से, 5.97 लाख कंपनियों ने निर्धारण वर्ष 2016-17 के लिए अपनी विवरणियां प्रस्तुत की हैं। निर्धारण वर्ष 2016-17 के लिए अब तक अपनी विवरणियां प्रस्तुत करने वाली 5.97 लाख कंपनियों में से, लगभग 2.76 लाख कंपनियों ने हानि अथवा शून्य आय दर्शाई है। 2.85 लाख कंपनियों ने कर पूर्व लाभ ₹1 करोड़ से कम दर्शाया है। 28,667 कंपनियों द्वारा लाभ की राशि ₹1 करोड़ से ₹10 करोड़ के बीच दर्शाई गई है और केवल 7781 कंपनियों को कर पूर्व लाभ ₹10 करोड़ से अधिक हुआ है।

141. 2015-16 में कर विवरणियां प्रस्तुत करने वाले 3.7 करोड़ व्यक्तियों में से, 99 लाख व्यक्ति, ₹2.5 लाख प्रतिवर्ष की छूट सीमा से कम आय दर्शाते हैं, 1.95 करोड़ व्यक्ति, ₹2.5 लाख से ₹5 लाख के बीच आय दर्शाते हैं, 52 लाख व्यक्ति, ₹5 लाख से ₹10 लाख के बीच आय दर्शाते हैं और केवल 24 लाख लोग, ₹10 लाख से अधिक आय दर्शाते हैं। 5 लाख रुपये से अधिक आय घोषित करने वाले 76 लाख व्यक्तिगत निर्धारितियों में से, 56 लाख वेतनभोगी वर्ग में हैं। पूरे देश में ₹50 लाख से अधिक आय दर्शाने वाले लोगों की संख्या केवल 1.72 लाख है। हम इसकी इस तथ्य से तुलना कर सकते हैं कि विगत पांच वर्षों में 1.25 करोड़ से अधिक कारें बेची गई हैं और व्यवसाय या पर्यटन के लिए विदेश जाने वाले भारतीय नागरिकों की संख्या वर्ष 2015 में 2 करोड़ है। इन सभी आंकड़ों से हम यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि हमारा समाज व्यापक रूप से कर अनुपालन न करने वाला समाज है। अर्थव्यवस्था में नकदी की प्रचुरता की वजह से लोगों के लिए अपने करों से बचना संभव होता है। जब बहुत ज्यादा लोग कर चोरी करते हैं तो इनके हिस्से का भार उन लोगों पर पड़ता है जो ईमानदार हैं और कर देते हैं।

142. विमुद्रीकरण के बाद, लोगों द्वारा पुरानी मुद्रा में जमा की गई राशियों के संबंध में प्राप्त आंकड़ों का प्रारम्भिक विश्लेषण एक सारगर्भित तस्वीर प्रस्तुत करता है। 8 नवम्बर से 30 दिसम्बर, 2016 तक की अवधि के दौरान, लगभग 1.09 करोड़ खातों में 2 लाख रुपये और 80 लाख रुपये के बीच राशियां जमा की गई थीं तथा औसत जमा आमाप ₹5.03 लाख था। ₹80 लाख से अधिक की राशियां ₹3.31 करोड़ के औसत जमा आमाप के साथ 1.48 लाख खातों में जमा कराई गई थीं। इन आंकड़ों की छानबीन से हमें कर के दायरे का विस्तार करने और राजस्व बढ़ाने में अत्यधिक सहायता प्राप्त होगी जो विमुद्रीकरण का एक उद्देश्य था।

143. अध्यक्ष महोदय, हमारी सरकार की प्राथमिकताओं में से एक प्राथमिकता अर्थव्यवस्था से काला धन को बाहर निकालना है। हम अपनी कराधान दरों को और अधिक तर्कसंगत बनाने, अपने कर प्रशासन को और अधिक उपयुक्त बनाने तथा देश में कर आधार का विस्तार करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। यह सोच धन का रंग बदल देगी।

नई दुनिया है, नया दौर है, नयी है उमंग

कुछ थे पहले के तरीके, तो हैं कुछ आज के ढंग

रोशनी आके अंधेरों से जो टकरायी है

काले धन को भी बदलना पड़ा, आज अपना रंग

144. वर्ष 2013-14 के दौरान निवल कर राजस्व ₹11.38 लाख करोड़ रुपये था। यह 2014-15 में 9.4 प्रतिशत और 2015-16 में 17% बढ़ गया। संशोधित अनुमान 2016-17 के अनुसार हम इस वर्ष का समापन दूसरे अनुवर्ती वर्ष के लिए 17% की उच्च वृद्धि दर के साथ करेंगे। सरकार द्वारा किए गए गंभीर प्रयासों के कारण, चालू वित्त वर्ष की प्रथम तीन तिमाहियों में व्यक्तिगत आयकर में अग्रिम कर की वृद्धि दर 34.8 प्रतिशत है।

145. अध्यक्ष महोदया, इस बजट में मेरे कर प्रस्तावों का जोर विकास की गति में तेजी लाने, मध्यम वर्ग को राहत प्रदान करने, सस्ते आवास, काले धन की रोकथाम, डिजिटल अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने, राजनीतिक वित्त पोषण की पारदर्शिता और कर व्यवस्था के सरलीकरण पर है।

सस्ते आवास और रियल एस्टेट सेक्टर को बढ़ावा देने के उपाय

146. विगत वर्ष, अपने बजट प्रस्तावों में, मैंने सस्ती आवास योजना के प्रवर्तकों हेतु लाभ-संबद्ध आयकर छूट की एक योजना की घोषणा की थी। इस योजना की बहुत अच्छी प्रतिक्रिया मिली है। तथापि, इस योजना को और अधिक आकर्षक बनाने के लिए, मेरा इस योजना में कतिपय परिवर्तनों का प्रस्ताव है। सर्वप्रथम, 30 और 60 वर्ग मीटर निर्मित क्षेत्र के बजाय, 30 और 60 वर्ग मीटर फर्श क्षेत्र की गणना की जाएगी। 30 वर्ग मीटर की सीमा भी केवल 4 मेट्रो शहरों की नगरपालिका सीमाओं के मामले में लागू होगी जबकि मेट्रो के बाह्य परिधीय क्षेत्रों सहित देश के शेष भागों के लिए 60 वर्ग मीटर की सीमा ही लागू होगी। पात्र बनने के उद्देश्य से यह योजना इसके प्रारम्भ के पश्चात 3 वर्षों में पूरी की जानी थी। मेरा इस अवधि को बढ़ाकर 5 वर्ष करने का प्रस्ताव है।

147. वर्तमान में, पूर्णता प्रमाणपत्र प्राप्त करने के पश्चात कब्जा न लिए गए मकान नेशनल किराया आय पर कर के अधधीन हैं। जिन बिल्डरों के लिए निर्मित मकान व्यवसाय में लगी पूंजी है, मेरा उनके लिए यह नियम पूर्णता प्रमाणपत्र प्राप्त होने वाले वर्ष के समाप्त होने के एक वर्ष बाद ही लागू करने का प्रस्ताव है ताकि उन्हें अपनी इन्वेंटरी के परिनिर्धारण हेतु कुछ समय मिल सके।

148. हम, भूमि और इमारत के संबंध में पूंजीगत लाभ कराधान उपबंधों में अनेक परिवर्तन करने का भी प्रस्ताव करते हैं। अचल संपत्ति से लाभ पर विचार करने हेतु धारण अवधि इस समय दीर्घावधिक 3 वर्ष है। इसे घटाकर 2 वर्ष किए जाने का प्रस्ताव है। अचल संपत्ति सहित आस्तियों की सभी श्रेणियों के लिए सूचीकरण के लिए आधार वर्ष भी 1.4.1981 से बदलकर 1.4.2001 किए जाने का प्रस्ताव है। इस कदम से पूंजीगत लाभ कर देयता काफी घटेगी जबकि आस्तियों की गतिशीलता को प्रोत्साहन मिलेगा। हमारी यह भी योजना है कि वितीय लिखतों के उस समूह का विस्तार किया जाए जिसमें कर की अदायगी किए बिना पूंजीगत लाभों का निवेश किया जा सके।

149. संपत्ति के विकास हेतु हस्ताक्षरित संयुक्त विकास करार के लिए, प्रतिफल प्राप्त होने वाले वर्ष में पूंजीगत लाभ कर अदा करने की बाध्यता उत्पन्न हो जाएगी।

150. आंध्र प्रदेश राज्य की नई राजधानी भूमि अधिग्रहण अधिनियम का प्रयोग किए बगैर नई भूमि पूर्लिंग व्यवस्था द्वारा बसाई जा रही है। मैं 2.6.2014 को, जिस दिन आंध्र प्रदेश राज्य का पुनर्गठन किया गया था, भूमि के धारक व्यक्तियों और जिनकी भूमि सरकारी योजना के अंतर्गत राजधानी शहर बसाने के लिए ली जा रही है, उनके लिए पूंजी लाभ कर से छूट देने का प्रस्ताव करता हूं।

विकास की गति को प्रेरित करने वाले उपाय

151. विदेशी वाणिज्यिक उधारों अथवा बांडों और सरकारी प्रतिभूतियों में विदेशी कंपनियों द्वारा उपार्जित ब्याज पर 5% रियायती विद-होल्लिंग दर प्रभारित की जा रही है। यह रियायत 30.6.2017 तक उपलब्ध है। मैं, इसे, 30.6.2020 तक बढ़ाने का प्रस्ताव करता हूं। यह लाभ रुपया मूल्यवर्गित (मसाला) बांडों को भी दिया जाता है।

152. सरकार ने पिछले साल कुछ शर्तों के साथ स्टार्ट-अप को आयकर रियायतें दी थी। ऐसे स्टार्ट-अप के संबंध में अगले लाभ से हानिपूर्ति के प्रयोजनार्थ मताधिकार के 51% की निरंतर शेयर धारिता की शर्त को इस बात के अधधीन शिथिल किया गया है कि मूल प्रमोटर/प्रमोटरर्स की शेयर धारिता जारी रहे। इसके अतिरिक्त, स्टार्ट-अप को 5 वर्ष में से 3 वर्ष के लिए उपलब्ध लाभ संबद्ध कटौती रियायत को बदलकर 7 वर्ष में से 3 वर्ष किया जा रहा है।

153. वर्तमान में न्यूनतम वैकल्पिक कर (मैट) अग्रिम कर के रूप में लगाया जाता है। मैट समाप्त करने की पुरजोर मांग है। यद्यपि, रियायतें चरणबद्ध ढंग से समाप्त करने की योजना 1.4.2017 से शुरू होगी और चरणबद्ध समाप्ति से राजस्व का पूरा लाभ सरकार को 7 से 10 वर्ष बाद में ही मिलेगा, जब वे सभी जो पहले ही इन रियायतों से लाभ ले रहे हैं, अपने लाभ लेने की अवधि पूरी कर लेंगे। इसलिए, वर्तमान में मैट समाप्त करना या कम करना व्यावहारिक नहीं है। तथापि, आगामी वर्षों में मैट क्रेडिट का प्रयोग करने के लिए कंपनियों को छूट देने के लिए मैं, मैट को वर्तमान में 10 वर्ष की बजाय 15 वर्ष की अवधि तक और चलाने का प्रस्ताव करता हूं।

154. मैंने, 2015 में अपने बजट प्रस्तावों में घोषणा की थी कि मैं कारपोरेट आय कर की दर धीरे-धीरे घटाकर 25% पर लाऊंगा। 2016 के बजट में, मैंने उन कंपनियों, जिनका कारोबार ₹5 करोड़ से कम है, के मामले में 1 प्रतिशत कटौती की घोषणा की थी। उसी बजट में मैंने यह घोषणा भी की थी कि वे नई विनिर्माण कंपनियां जो किसी छूट का लाभ नहीं लेती हैं, उन पर सिर्फ 25% आयकर प्रभारित किया जाएगा।

155. मध्यम और लघु उद्यम अधिकतर आर्थिक कार्यकलाप करते हैं और लोगों को अधिकतम रोजगार उपलब्ध कराने में भी सहायक हैं। तथापि, क्योंकि उन्हें अधिक रियायतें नहीं मिलतीं, वे बड़ी कंपनियों की तुलना में ज्यादा कर देते रहते हैं। वित्त वर्ष 2015-16 के डाटा के अनुसार ₹1 करोड़ से कम लाभ कमाने वाली 2.85 लाख कंपनियां 30.26% प्रभावी कर दर अदा करती हैं जबकि ₹500 करोड़ से अधिक लाभ कमाने वाली 298 कंपनियां 25.90% प्रभावी कर दर अदा करती हैं।

156. एमएसएमई कंपनियों को और व्यवहार्य बनाने के लिए और फर्मों को भी कंपनी में बदलने के लिए प्रोत्साहित करने हेतु मैं, ₹50 करोड़ तक का वार्षिक कारोबार करने वाली छोटी कंपनियों का आयकर घटाकर 25% करने का प्रस्ताव करता हूं। निर्धारण वर्ष 2015-16 के डाटा के अनुसार 6.94 लाख कंपनियां विवरणियां दायर कर रही हैं, जिनमें से 6.67 लाख कंपनियां इस श्रेणी में आती हैं और इसलिए प्रतिशत-वार 96% कंपनियां निम्न कराधान का लाभ उठाएंगी। यह हमारे एमएसएमई क्षेत्र को बड़ी कंपनियों की तुलना में और अधिक प्रतिस्पर्धी बना देगा। इस उपाय से परित्यक्त राजस्व का अनुमान ₹7,200 करोड़ प्रति वर्ष होने की आशा है।

157. बैंकिंग क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए अनर्जक परिसंपत्तियों हेतु अनुज्ञेय प्रावधान 7.5% से बढ़ाकर 8.5% करने का प्रस्ताव करता हूं। यह बैंकों की कर देनदारी कम कर देगा। मैं सभी गैर-अनुसूचित सहकारी बैंकों के एनपीए खातों के संबंध में प्रोद्भवन आधार की बजाय वास्तविक प्राप्ति पर प्राप्त ब्याज पर अनुसूचित बैंकों के समान ही कर लगाने का प्रस्ताव करता हूं। यह कर अदा करने, चाहे ब्याज आय वसूल न की गई हो, का कष्ट समाप्त कर देगा।

158. एलएनजी के ईंधन के साथ-साथ पेट्रो-रसायन सेक्टर के लिए फीड स्टॉक के प्रयोग की व्यापक श्रृंखला पर विचार करते हुए मैं एलएनजी पर बुनियादी सीमाशुल्क 5% से घटाकर 2.5% करने का प्रस्ताव करता हूं।

159. घरेलू मूल्य वर्धन प्रोत्साहित करने और मेक इन इंडिया को बढ़ावा देने के लिए मैं कुछ मदों, जो इस भाषण के अनुबंध-III में दी गई हैं, के संबंध में सीमाशुल्क और उत्पाद शुल्क में परिवर्तन करने का प्रस्ताव करता हूं। इनमें से कुछ प्रस्ताव शुल्क प्रतिलोमन समाप्त करने के लिए भी हैं।

डिजिटल अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देना

160. छोटे और मध्यम कर दाताओं, जिनकी कुल बिक्री ₹2 करोड़ तक है, के लिए अनुमानित आयकर योजना लागू की गई है। वर्तमान में उनकी कुल बिक्री के 8% को अनुमानित आय माना जाता है। मैं बिक्री, जो नकदी-भिन्न साधनों से की जाती है, के संबंध में इसे 6% करने का प्रस्ताव करता हूं। यह लाभ चालू वर्ष में किए गए लेनदेनों पर भी लागू होगा।

161. मैं कटौती, राजस्व के साथ-साथ पूंजी व्यय, के रूप में अनुज्ञेय नकदी व्यय की सीमा ₹10,000 करने का प्रस्ताव करता हूं। इसी तरह नकद दान की सीमा, जो किसी धर्मार्थ न्यास द्वारा प्राप्त की जा सकती है, ₹10,000 से घटाकर ₹2,000 की जा रही है।

162. सरकार द्वारा काले धन के लिए गठित की गई विशेष जांच दल (एसआईटी) ने सुझाव दिया है कि 3 लाख रुपए से अधिक का कोई भी लेनदेन नकदी में करने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। सरकार ने यह प्रस्ताव स्वीकार करने का निर्णय लिया है। इस निर्णय को लागू करने के लिए वित्त विधेयक में आयकर अधिनियम में समुचित संशोधन का प्रस्ताव किया गया है।

163. मैं, कैशलेस लेनदेनों को बढ़ावा देने के लिए एम-पीओएस हेतु मिनिएचर्ड पीओएस कार्ड रीडर, माइक्रो एटीएम स्टैंडर्ड्स वर्सन 1.5.1, फिंगर प्रिंट रीडर्स/स्कैनर्स और आयरिश स्कैनर्स पर बीसीडी, उत्पाद शुल्क/सीवी शुल्क और एसएडी से छूट का प्रस्ताव करता हूं। इसके साथ ही, मैं ऐसे साधनों के विनिर्माण हेतु कलपुर्जों पर छूट का भी प्रस्ताव करता हूं ताकि इन साधनों के देश में विनिर्माण को प्रोत्साहित किया जा सके।

चुनावी वित्तपोषण में पारदर्शिता

164. भारत विश्व में सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है। राजनीतिक पार्टियाँ एक बहु-पार्टी संसदीय लोकतंत्र के अनिवार्य अवयव हैं। स्वतंत्रता प्राप्ति के 70 वर्ष बाद भी, देश, राजनीतिक पार्टियों के वित्तपोषण की पारदर्शी कार्यपद्धति विकसित करने में समर्थ नहीं हुआ है, जो कि निष्पक्ष और स्पष्ट चुनाव प्रणाली के लिए अनिवार्य है। व्यष्टियों, साझेदारी फर्मों, हिंदू अविभाजित परिवारों और कंपनियों द्वारा राजनीतिक पार्टियों को प्रोत्साहन के रूप में चंदा देने के लिए विगत में जन प्रतिनिधि अधिनियम, कंपनी अधिनियम और आय कर अधिनियम के उपबंधों में संशोधन करके एक प्रयास किया गया था। दाता और आदाता दोनों को कर के भुगतान से छूट प्रदान की गई थी, यदि उनके लेखे पारदर्शी ढंग से रखे गए हों और सक्षम प्राधिकारियों को विवरणियाँ फाइल की गई हों। तदनुसार, उन दाताओं की सूची अलग-से तैयार करने की आवश्यकता है, जिन्होंने किसी भी पार्टी को ₹20,000/- अथवा उससे अधिक राशि का अंशदान नकद या चैक से दिया है। इन प्रावधानों को लागू किए जाने से स्थिति में केवल मामूली रूप से सुधार हुआ है। राजनीतिक पार्टियाँ अपनी अधिकांश निधि अज्ञात चंदे के जरिए प्राप्त कर रही हैं जो नकद में दिखाई जाती हैं।

165. इसलिए, भारत में राजनीतिक वित्तपोषण प्रणाली दुरुस्त करने के लिए प्रयास किए जाने की आवश्यकता है। दाताओं ने भी चैक या अन्य पारदर्शी पद्धतियों द्वारा चंदा देने में अरुचि दिखाई है क्योंकि इससे उनकी पहचान उजागर होती है तथा इसके प्रतिकूल परिणाम हो सकते हैं। इसलिए, मैं राजनीतिक पार्टियों की वित्तपोषण प्रणाली दुरुस्त करने के प्रयास के रूप में निम्नलिखित योजनाओं का प्रस्ताव रखता हूँ:

(क) निर्वाचन आयोग द्वारा दिए गए सुझाव के अनुपालन में, एक राजनीतिक पार्टी एक व्यक्ति से नकद चंदे के रूप में अधिकतम ₹2000/- की राशि प्राप्त कर सकती है।

(ख) राजनीतिक पार्टियाँ अपने दाताओं से चैक या डिजिटल माध्यम से चंदा प्राप्त करने के लिए पात्र होंगी।

(ग) अतिरिक्त उपाय के रूप में, भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम में संशोधन किए जाने का प्रस्ताव है, जिससे कि भारत सरकार द्वारा इस संबंध में बनाई जाने वाली किसी योजना के अनुसार चुनावी बांड जारी किए जा सकें। इस योजना के अंतर्गत, दाता केवल चैक और डिजिटल भुगतानों के तहत प्राधिकृत बैंकों से बांड खरीद सकता है। ये बांड पंजीकृत राजनीतिक पार्टी के निर्दिष्ट और पंजीकृत खाते में ही परिशोध्य होंगे। इन बांडों को बांड जारी करने से निर्धारित समय सीमा के भीतर ही परिशोध्य कराया जाएगा।

(घ) प्रत्येक राजनीतिक पार्टी को आय कर अधिनियम के उपबंधों के अनुपालन में निर्धारित समय-सीमा के भीतर अपनी विवरणी प्रस्तुत करनी होगी।

कहने की आवश्यकता नहीं है कि राजनीतिक पार्टियों को आय कर के भुगतान से मौजूदा छूट केवल इन शर्तों को पूरा करने के अध्वधीन ही मिलेगी। इस सुधार से भविष्य में काले धन के सृजन को रोकते हुए राजनीतिक वित्तपोषण में और अधिक पारदर्शिता और जवाबदेही आएगी।

ईज ऑफ ड्रइंग बिजनेस

166. कर वंचन रोधी उपाय के रूप में 2012 के वित्त अधिनियम में संबंधित उद्यमियों के संबंध में घरेलू अंतरण मूल्य निर्धारण के प्रावधान का उल्लेख किया गया था। तब से घरेलू मूल्य निर्धारण के अंतर्गत कवर किए गए उद्यमियों की संख्या में उल्लेखनीय ढंग से बढ़ोतरी हुई है, जिससे लंबी जांच पड़ताल की आवश्यकता हुई, जिससे घरेलू कंपनियों को कठिनाई हुई। घरेलू अंतरण मूल्य निर्धारण उपबंधों के कारण अनुपालन को कम करने के उद्देश्य से घरेलू अंतरण कीमत निर्धारण के कार्यक्षेत्र को सीमित करने का प्रस्ताव करता हूँ कि पार्टी लेनदेन से संबंधित उद्यमियों में से केवल एक उद्यमी ही विनिर्दिष्ट लाभ संबंधी कटौती प्राप्त कर सकता है।

167. मैं उन व्यावसायिक उद्यमियों की लेखा परीक्षा के लिए प्रारंभिक सीमा 1 करोड़ रुपए से बढ़ाकर ₹2 करोड़ तक करने का प्रस्ताव करता हूँ, जो अनुमानित आय योजना का विकल्प चुनते हैं। इसी प्रकार, व्यष्टियों और हिंदू अविभाजित परिवारों के लिए बहियों के रखरखाव की प्रारंभिक सीमा ₹10 लाख टर्नओवर से बढ़ाकर ₹25 लाख अथवा आय को ₹1.2 लाख से बढ़ाकर ₹2.5 लाख की जा रही है।

168. वर्ष 2012 में आय कर अधिनियम को भारतीय परिसंपत्तियों से अत्यधिक मूल्य प्राप्त करने वाली किसी विदेशी कंपनी में शेयरों या ब्याज के अंतरण संबंधी लेनदेनों पर कराधान का प्रावधान करने के लिए संशोधित किया गया था, विदेश में स्थित भारत-आधारित कंपनियों में निवेश करने वाले भारत-आधारित निधियों के निवेशकों के स्टैक के अंतरण के मामले में इस प्रावधान के कारण उत्पन्न कुछ कठिनाइयों के बारे में आशंकाएं व्यक्त की गई हैं।

169. इस कठिनाई को समाप्त करने के उद्देश्य से, मैं श्रेणी I एवं II के विदेशी पोर्टफोलियो निवेशक को अप्रत्यक्ष अंतरण उपबंध से छूट प्रदान करने का प्रस्ताव करता हूँ। हमारा यह स्पष्टीकरण जारी करने का भी प्रस्ताव है कि भारत में कर-प्रभार्य निवेश के शोधन या बिफ्री के परिणामस्वरूप या इससे उत्पन्न परंतु भारत से बाहर शेरों के शोधन या ब्याजों के मामले में अप्रत्यक्ष अंतरण प्रावधान लागू नहीं होंगे।

170. आज तक, व्यक्ति बीमा एजेंटों को देय कमीशन में 5 प्रतिशत टीडीएस की कटौती की जा रही है, चाहे उनमें से कुछ की आय ही कर योग्य सीमा से कम ही हो। हम उन्हें टीडीएस की आवश्यकता से छूट प्रदान करने का प्रस्ताव करते हैं, उन्हें इस शर्त के अध्यक्षीन स्वघोषणा करनी होगी कि उनकी आय कर योग्य सीमा से कम है।

171. पिछले वर्ष मैंने ₹50 लाख प्रति वर्ष की आय वाले व्यावसायियों के लिए अनुमानित कराधान की नई योजना की घोषणा की थी। ऐसे निर्धारण के संबंध में, अग्रिम कर के भुगतान के संबंध में उन्हें चार किस्तों के स्थान पर एक किस्त में भुगतान करने का लाभ दिया जा रहा है।

172. जनता के लिए धन वापसी दावे में तेजी लाने के लिए, संशोधित कर विवरणी के लिए समय सीमा को वित्त वर्ष पूरा होने से कम करके विवरणी फाइल करने की समयावधि के समान 12 माह तक किया जा रहा है। साथ ही, आकलन जांच के पूरा होने की समय सीमा भी निर्धारण वर्ष 2018-19 के लिए 21 माह से कम करके 18 माह और निर्धारण वर्ष 2019-20 एवं उससे आगे और कम करके 12 माह की जा रही है।

व्यक्तिगत आय-कर

173. जबकि सरकार कर अपवंचन करने वाले और अधिक लोगों को कर-नेट के दायरे में लाने की कोशिश कर रही है, कराधान का वर्तमान बोझ प्रमुखतः ईमानदार करदाताओं और वेतनभोगी कर्मचारियों पर है जो अपनी आय को सही रूप में दर्शाते हैं। अतः विमुद्रीकरण-पश्चात इस वर्ग के लोगों की यह आशा जायज़ है कि उनके कराधान के बोझ को कम किया जाए। इसके अतिरिक्त, यह भी तर्क दिया गया है कि यदि स्लैब के लिए कराधान की दर को नाममात्र रखा जाए, तो अनेक और लोग कर-नेट के अंतर्गत आना चाहेंगे।

174. इसलिए मैं, ₹2.5 लाख से ₹5 लाख तक की आय वाले व्यक्ति निर्धारितियों के लिए कराधान की मौजूदा दर को 10% से घटाकर 5% करने का प्रस्ताव करता हूँ। इससे ₹5 लाख से कम आय वाले सभी व्यक्तियों की कर देयता घट कर शून्य (छूट सहित) या इनकी मौजूदा देयता की 50% रह जाएगी। लाभ की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए, लाभार्थियों के उसी समूह को उपलब्ध छूट के मौजूदा लाभ को घटाकर ₹2500 किया जा रहा है जो ₹3.5 लाख तक की आय वाले निर्धारितियों के लिए ही उपलब्ध है। इन दोनों उपायों का संयुक्त प्रभाव यह होगा कि प्रति वर्ष ₹3 लाख तक की आय वाले व्यक्तियों के लिए कर देयता शून्य होगी और ₹3 लाख से ₹3.5 लाख तक की आय वाले व्यक्तियों के लिए कर देयता मात्र ₹2,500 होगी। यदि धारा 80G के तहत ₹1.5 लाख की सीमा निवेश के लिए पूर्णतः प्रयोग किया जाता है तो ₹4.5 लाख की आय वाले लोगों के लिए कर शून्य होगा। चूँकि ₹5 लाख तक की आय वाले लोगों की कराधान देयता को घटाकर आधा किया जा रहा है, बाद की स्लैबों में अन्य श्रेणियों के सभी करदाताओं को भी प्रति व्यक्ति ₹12,500/- का एक समान लाभ मिलेगा। इस उपाय के चलते परित्यक्त कर की कुल राशि ₹15,500 करोड़ बनती है।

175. इस राहत के कारण होने वाली राजस्व हानि के कुछ भाग की प्रतिपूर्ति के लिए, मैं उन व्यक्तियों पर देय कर का 10% अधिभार के रूप में लगाने का प्रस्ताव करता हूँ जिनकी वार्षिक कर योग्य आय ₹50 लाख और ₹1 करोड़ के बीच में है। ₹1 करोड़ से अधिक अर्जित करने वाले व्यक्तियों पर कर का 15% का मौजूदा अधिभार जारी रहेगा। इससे ₹2,700 करोड़ का अतिरिक्त राजस्व प्राप्त होने की संभावना है।

176. कर-नेट को और व्यापक बनाने के लिए, व्यावसायिक आय से इतर ₹5 लाख तक की कर योग्य आय वाले व्यक्तियों के लिए आयकर विवरणी के रूप में भरे जाने के लिए एक-पृष्ठीय फॉर्म लाने की भी हमारी योजना है। इसके अतिरिक्त, इस श्रेणी का कोई भी व्यक्ति जो प्रथम बार आय कर विवरणी भरता है, प्रथम वर्ष में किसी जांच के अध्यक्षीन तब तक नहीं होगा जब तक कि उसके उच्च मूल्य के लेन-देन के बारे में विभाग के पास विशिष्ट सूचना उपलब्ध न हो। मैं, भारत के सभी नागरिकों से अपील करता हूँ कि यदि उनकी आय ₹2.5 लाख से ₹5 लाख तक के सबसे निचले स्लैब के अंतर्गत आती है तो 5% कर की छोटी सी अदायगी करते हुए राष्ट्र निर्माण में भागीदार बनें।

177. कर कानूनों में संशोधन के लिए कुछ अन्य महत्वपूर्ण प्रस्ताव, जिनका मेरे भाषण में उल्लेख नहीं हुआ है, इस भाषण के अनुबंध-III में दिए गए हैं।

वस्तु एवं सेवा कर

178. जीएसटी को लागू करने की दिशा में पर्याप्त प्रगति हुई है, जोकि स्वतंत्रता के बाद अब तक का सर्वाधिक बड़ा कर सुधार है। संविधान (एक सौ एकवां संशोधन) अधिनियम, 2016 के अधिनियमों से लेकर, अब तक, इस अभूतपूर्व सुधार के लिए प्रारंभिक कार्य सरकार की सर्वोच्च वरीयता रही है। इस संदर्भ में, राज्यों और केंद्रीय उत्पाद शुल्क और सीमा शुल्क बोर्ड दोनों की ओर से अधिकारियों की अनेक टीमों मॉडल जीएसटी कानून और नियमों तथा अन्य ब्यौरों को अंतिम रूप देने के लिए अथक रूप से कार्य कर रही हैं। सरकार ने अपनी ओर से संवैधानिक संशोधन अधिनियम के विभिन्न उपबंधों को तुरंत प्रभाव से लागू किया है, जिसमें जीएसटी परिषद का गठन भी शामिल है। अब तक, जीएसटी परिषद ने जीएसटी दर ढांचे की व्यापक रूपरेखा, समझौता योजना के लिए न्यूनतम छूट और मानदंड, जीएसटी को लागू करने के कारण राज्यों को दी जाने वाली प्रतिपूर्ति संबंधी विवरण, नमूना जीएसटी कानून के मसौदे के परीक्षण, एकीकृत जीएसटी कानून और प्रतिपूर्ति कानून तथा जीएसटी के लिए प्रशासनिक तंत्र सहित जीएसटी से संबंधित विभिन्न मुद्दों पर चर्चा करने के लिए 9 बैठकें आयोजित की हैं। इस महान सदन में यह सूचित करना मेरा सौभाग्य है कि जीएसटी परिषद ने उत्साहवर्धक बहस और चर्चाओं के बाद लगभग सभी सहमति आधारित मुद्दों पर अपनी सिफारिशों को अंतिम रूप दे दिया है। जीएसटी के लिए सूचना प्रौद्योगिकी प्रणाली की तैयारी भी निर्धारित समयानुसार चल रही है। जीएसटी के लिए व्यापार और उद्योग तक पहुँच बनाने के व्यापक प्रयास 1 अप्रैल, 2017 से प्रारंभ होंगे ताकि व्यापार और उद्योग जगत को नई कराधान प्रणाली के प्रति जागरूक किया जा सके।

179. केंद्रीय उत्पाद शुल्क और सीमा शुल्क बोर्ड के माध्यम से, केंद्र सहकारी संघवाद के मूल-मंत्र से समझौता किए बिना निर्धारित समयानुसार जीएसटी के क्रियान्वयन के लक्ष्य को हासिल करने के लिए निरंतर प्रयासरत रहेगा। जीएसटी को लागू करने से कर-नेट के विस्तार के कारण केंद्र और राज्यों दोनों को और अधिक कर प्राप्त होने की संभावना है। हमने उत्पाद शुल्क और सेवा कर की वर्तमान व्यवस्था में अधिक परिवर्तन नहीं करने का निर्णय लिया है क्योंकि इन्हें शीघ्र ही जीएसटी द्वारा प्रतिस्थापित किया जाना है।

रैपिड

180. जून 2016 में आयोजित अधिकारियों की 'राजस्व ज्ञान संगम' नामक वार्षिक सभा में प्रधान मंत्री ने रैपिड जिसका अर्थ है - राजस्व, उत्तरदायित्व, सत्यनिष्ठा, सूचना और डिजीटाइजेशन, के प्रस्ताव के रूप में कर प्रशासन में सुधार लाने की इच्छा जाहिर की थी। यह उस प्रस्ताव से कर विभाग की कार्यनीति सूक्ष्मरूप से प्रतिबिंबित होती है जो अब निर्धारित कर दी गई है। चूंकि राजस्व विभाग हमेशा एकाग्र रहा है, हम कर-निर्धारण में मानव हस्तक्षेप को दूर करने के साथ-साथ कर अपवंचन को रोकने के लिए सूचना प्रौद्योगिकी को अधिकतम प्रयोग में लाने का प्रयास कर रहे हैं। हम आने वाले वर्षों में ई-निर्धारण के लिए अपने प्रयासों में और तेज़ी लाएंगे। हम इन-हाउस और आउटसोर्स दोनों तरीके से डाटा जुटाने की क्षमता का अधिकाधिक प्रयोग भी कर रहे हैं। भूल-चूक के विशिष्ट कार्य के प्रति कर विभाग के अधिकारियों में अधिक उत्तरदायित्व को प्रवर्तित करने की भी हमारी योजना है। मैं प्रत्येक को आश्वस्त करना चाहूंगा कि ईमानदार, कर-अनुपालक व्यक्ति के साथ गरिमापूर्ण और भद्र व्यवहार किया जाएगा।

181. अध्यक्ष महोदया, छूटों इत्यादि के लिए मेरे प्रत्यक्ष कर प्रस्तावों के परिणामस्वरूप ₹22,700 करोड़ की राजस्व हानि होगी, परन्तु अतिरिक्त संसाधन जुटाने के प्रस्ताव के लिए ₹2,700 करोड़ के राजस्व लाभ की गणना करने के पश्चात प्रत्यक्ष कर में निवल राजस्व हानि ₹20,000 करोड़ की होगी। मेरे अप्रत्यक्ष कर प्रस्तावों में कोई विशेष हानि या लाभ नहीं है।

निष्कर्ष

182. अध्यक्ष महोदया, मैंने अपने विस्तृत एजेंडा: "भारत में आमूल परिवर्तन लाने, शक्ति का संचार करने तथा स्वच्छ भारत बनाने" के तहत बजट प्रस्तावों की रूपरेखा प्रस्तुत कर दी है। अब हमारा जोर किसानों, निर्धनों और समाज के अभावग्रस्त वर्गों के लाभ के लिए इन सभी प्रस्तावों को कार्यान्वित कराने पर रहेगा।

183. अध्यक्ष महोदया, यह कहा जाता है कि: 'जब मेरा उद्देश्य सही हो, जब मेरा लक्ष्य मेरे सामने हो, माहौल मेरे पक्ष में हो और मैं उड़ान भरूँ'। इसके लिए आज के दिन से बेहतर कोई और दिन नहीं होगा।

184. अध्यक्ष महोदया, इन्हीं शब्दों के साथ मैं सदन के समक्ष बजट प्रस्तुत करता हूँ।

भाग क का अनुबंध I

वित्तीय क्षेत्र में अन्य उपाय

1. भागीदारों, ब्रोकरों और प्रचालनात्मक रूपरेखा को एकीकृत करते हुए पण्यों और प्रतिभूति व्युत्पन्न बाजारों को और भी एकीकृत किया जाएगा।
2. सेबी द्वारा म्युचुअल फंडों, ब्रोकरों, पोर्टफोलियो प्रबंधकों आदि जैसे वित्तीय बाजार के मध्यस्थों के पंजीकरण की प्रक्रिया पूरी तरह से ऑनलाइन बनाई जाएगी। इससे आसानी से कारोबार करने में सुधार होगा।
3. विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों के लिए पंजीकरण, बैंक खाता और डीमैट खाता खोलने तथा पैन कार्ड जारी करने के लिए एक कॉमन आवेदन फार्म बनाया जाएगा। इसके लिए सेबी, आरबीआई और सीबीडीटी संयुक्त रूप से आवश्यक प्रणालियां और कार्यविधियां तैयार करेंगे। इससे प्रचालनात्मक लोचशीलता बढ़ेगी और भारतीय पूंजी बाजार में पहुंच सुगम होगी।
4. व्यष्टि डीमैट खातों को आधार के साथ लिंक करने के लिए कदम उठाए जाएंगे।
5. फिलहाल बैंकों और बीमा कंपनियों जैसी संस्थाओं को सेबी द्वारा अर्हक संस्थागत क्रेताओं (क्यूआईबी) के रूप में वर्गीकृत किया गया है। ये संस्थाएं विशेषरूप से निर्धारित आबंटनों सहित आईपीओ में भागीदारी के लिए पात्र हैं। अब भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा विनियमित व्यवस्थित रूप से महत्वपूर्ण और एक कतिपय निवल मूल्य से ऊपर की एनबीएफसी को अर्हक संस्थागत क्रेता के रूप में वर्गीकृत किए जाने का प्रस्ताव है। इससे आईपीओ बाजार सुदृढ़ होगा और अधिक निवेश का मार्ग प्रशस्त होगा।
6. सरफेसी अधिनियम के अंतर्गत प्रतिभूतिकरण कंपनी अथवा पुनर्निर्माण कंपनी द्वारा निर्गमित प्रतिभूति प्राप्तियों के सूचीयन और व्यापार की सेबी द्वारा पंजीकृत स्टॉक एक्सचेंजों में अनुमति दी जाएगी। इससे प्रतिभूतिकरण उद्योग में पूंजी प्रवाह में बढ़ोतरी होगी और इससे विशेषरूप से बैंकों को अनर्जक आस्तियों (एनपीए) से निपटने में सहायता मिलेगी।

भाग क का अनुबंध II-क

महत्वपूर्ण मंत्रालयों, क्षेत्रों और कमजोर वर्गों के लिए आवंटन				
		(करोड़ रुपए)		
क्रम सं.	मंत्रालय का नाम	ब.अ. 2016- 2017	सं.अ. 2016-2017	ब.अ. 2017- 2018
1	कृषि और कृषक कल्याण मंत्रालय	44485	48072	51026
2	पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय	2430	2524	2682
3	पेयजल और स्वच्छता मंत्रालय	14010	16512	20011
4	स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय	38206	39688	48853
5	आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय	5411	5285	6406
6	मानव संसाधन विकास मंत्रालय	72394	73599	79686
7	सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय	3465	5463	6482
8	अल्पसंख्यक मामले मंत्रालय	3827	3827	4195
9	नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय	5036	4360	5473
10	रेल मंत्रालय	45000	46155	55000
11	सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय	57976	52447	64900
12	ग्रामीण विकास मंत्रालय	87765	97760	107758

13	कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय	1804	2173	3016
14	सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय	7350	7353	7763
15	जनजातीय मामले मंत्रालय	4827	4827	5329
16	शहरी विकास मंत्रालय	24523	32550	34212
17	जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय	6201	4756	6887
18	महिला और बाल विकास मंत्रालय	17408	17640	22095
अनु.जाति, अनु.जनजाति, अन्य कमजोर वर्गों, महिलाओं, बच्चों और पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए आवंटन				
	आवंटन का वर्णन	ब.अ. 2016- 2017	सं.अ. 2016- 2017	ब.अ. 2017- 2018
I	सभी मंत्रालयों में अनु.जनजातियों के कल्याण के लिए आवंटन	24005	25602	31920
II	सभी मंत्रालयों में अनु.जातियों के कल्याण के लिए आवंटन	38833	40920	52393
III	अन्य कमजोर वर्गों के कल्याण के लिए आवंटन	1873	1892	1976
IV	सभी मंत्रालयों में पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए आवंटन	29125	32180	43245
V	सभी मंत्रालयों में महिला कल्याण के लिए विभिन्न स्कीमों के अंतर्गत आवंटन	90770	96332	113327
VI	सभी मंत्रालयों में बाल कल्याण हेतु विभिन्न स्कीमों के अंतर्गत आवंटन	65758	66249	71305

क्षेत्र जोड़				
क्रम सं.	क्षेत्र	ब.अ. 2016-2017	सं.अ. 2016-2017	ब.अ. 2017-2018
		(करोड़ रुपए)		
1	कृषि और संबद्ध क्षेत्र	48572	52821	58663
2	ग्रामीण विकास	102543	114947	128560
3	अवसंरचना	348952	358634	396135
3क	जिसमें से परिवहन	216268	216903	241387
4	सामाजिक क्षेत्र	168100	176225	195473
4क	शिक्षा और स्वास्थ्य	112138	114806	130215
4ख	कल्याण अभिमुखीकरण सहित सामाजिक क्षेत्र	55962	61419	65258
5	रोजगार सृजन, कौशल और आजीविका	12141	14870	17273
6	वैज्ञानिक मंत्रालय	33467	34359	37435

स्रोत : व्यय की रूपरेखा और व्यय बजट 2017-18

भाग क का अनुबंध II-ख

महत्वपूर्ण योजनाओं के लिए आवंटन

क्रम सं.	योजना का नाम	(करोड़ रुपए)		
		ब.अ. 2016-2017	सं.अ. 2016-2017	ब.अ. 2017-2018
1	महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी कार्यक्रम	38500	47499	48000
2	प्रधानमंत्री आवास योजना	20075	20936	29043
3	राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल मिशन	5000	6000	6050
4	राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम	9500	9500	9500
5	प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना	19000	19000	19000
6	सर्व शिक्षा अभियान सहित राष्ट्रीय शिक्षा मिशन	28330	28251	29556
7	स्कूलों में मध्याह्न भोजन का राष्ट्रीय कार्यक्रम	9700	9700	10000
8	एकीकृत बाल विकास सेवाएं	16260	16580	20755
9	राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन	20762	22598	27131
10	स्वच्छ भारत मिशन	11300	12800	16248
11	स्वच्छ आजीविका मिशन-आजीविका	3325	3334	4849
12	शहरी पुनरुद्धार मिशन: अमृत तथा स्मार्ट सिटी मिशन	7296	9559	9000
13	हरित क्रांति	12560	10360	13741
14	श्वेत क्रांति	1138	1312	1634
15	नीली क्रांति	247	392	401
16	प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना (पीएमकेएसवाई) तीन मंत्रालयों से संबद्ध	5767	5189	7377
17	महिला सशक्तिकरण एवं संरक्षण मिशन	907	821	1089
18	पर्यावरण, वानिकी और वन्य जीव	850	819	962
19	प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, एटीयूएफएस, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, पीएमईजीपी और एसपीआईआईआई सहित मनरेगा से इतर रोजगार सृजन कार्यक्रम	8133	10682	11640
20	प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना	5500	13240	9000
21	रक्षा सेवाओं के लिए ऑप्टिकल फाइबर केबल आधारित नेटवर्क	2710	3210	3000
22	दालों के लिए मूल्य स्थिरीकरण निधि	900	3400	3500
23	भारतनेट	0	6000	10000

क्रम सं.	योजना का नाम	(करोड़ रुपए)		
		ब.अ. 2016-2017	सं.अ. 2016-2017	ब.अ. 2017-2018
24	मैट्रो परियोजनाएं	10000	15700	18000
25	इंद्रधनुष योजना के अनुसार सरकारी क्षेत्र के बैंकों का पुनः पूंजीकरण	25000	25000	10000
26	एकीकृत विद्युत विकास स्कीम और दीन दयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना	8500	7874	10635
27	नमामी गंगे-राष्ट्रीय गंगा योजना	2150	1441	2250
28	सागरमाला	450	406	600
29	निर्धन परिवारों को एलपीजी कनेक्शन	2000	2500	2500

भाग क का अनुबंध II -ग

राज्यों और विधानमंडल वाले संघ राज्य क्षेत्रों को अंतरित संसाधन					
क्रम सं.		(करोड़ रुपए)			
		वास्तविक 2015-16	ब.अ. 2016-17	सं.अ. 2016-17	ब.अ. 2017-18
1	करों में राज्यों के हिस्से का अंतरण	506193	570337	608000	674565
2	वित्त आयोग के अंतरण	84579	100646	99115	103101
3	राज्यों को अन्य केंद्रीय अंतरण	238572	254371	277649	303412
4	राज्यों को कुल केंद्रीय अंतरण (सकल) (1+2+3)	829344	925354	984764	1081078
5	विधानमंडल वाले संघ राज्य क्षेत्रों को कुल केंद्रीय अंतरण (सकल)	5139	5320	5547	3996
6	कुल अंतरण (सकल) (4+5)	834483	930674	990311	1085074
7	ऋणों और अग्रिमों की वसूली (क+ख)	11513	9473	9163	9516
क	राज्य	11454	9028	8730	9083
ख	संघ राज्य क्षेत्र	59	445	433	433
8	राज्यों को कुल केंद्रीय अंतरण (निवल) (4-7क)	817890	916326	976034	1071995
9	विधान मंडल वाले संघ राज्य क्षेत्रों को कुल केंद्रीय अंतरण (निवल) (5-7ख)	5080	4875	5114	3563
10	केंद्र से कुल अंतरण (निवल) (8+9)	822970	921201	981148	1075558
	इसके अतिरिक्त				
11	राष्ट्रीय लघु बचत निधि (एनएसएसएफ) * से निर्गमित विशेष राज्य सरकार की प्रतिभूतियां	58750	26375	13000	15000

* केवल मध्य प्रदेश, केरल, अरुणाचल प्रदेश और दिल्ली ने 2016-17 से शुरू करके एनएसएसएफ से ऋण प्राप्त करने का चयन किया है।

स्रोत : बजट का सार 2017-18.

बजट भाषण के भाग - ख का अनुबंध III

प्रत्यक्ष कर**1. अतिरिक्त राजस्व जुटाने (एआरएम) संबंधी और दुरुपयोग-रोधी उपाय**

1.1 आयकर अधिनियम की धारा 115खखघक के प्रावधानों को विस्तृत किए जाने का प्रस्ताव है जिनमें धारा 12कक अथवा धारा 10(23ग) में उल्लिखित के अंतर्गत पंजीकृत घरेलू कंपनियों अथवा न्यास अथवा संस्था अथवा निधि को छोड़कर सभी निवासी व्यक्तियों के लिए लाभांश आय ₹10 लाख से अधिक होने पर 10 प्रतिशत की दर से कर लगाने का प्रावधान है। इस समय, ये प्रावधान केवल व्यष्टियों, हिंदु अविभक्त परिवार और फर्मों पर लागू हैं।

1.2 आयकर की धारा 56 के कार्यक्षेत्र को व्यापक बनाने का प्रस्ताव है ताकि यह व्यवस्था की जा सके कि किसी व्यक्ति द्वारा विचार किए बिना अथवा अपर्याप्त विचार करके प्राप्त किया गया कोई धन, अचल संपत्ति और विनिर्दिष्ट चल संपत्ति कतिपय छूट और अपवादों के अध्यधीन कर योग्य होगी यदि इसका मूल्य पचास हजार रुपये से अधिक हो।

1.3 यह प्रस्ताव है कि सूची से इतर इक्विटी शेयरों के अंतरण के मामले में, जहां विहित तरीके से निर्धारित उचित बाजार मूल्य प्रतिफल से कम हो, ऐसे उचित बाजार मूल्य को पूंजी लाभों की गणना के प्रयोजनार्थ प्रतिफल का मूल्य माना जाएगा।

1.4 यह व्यवस्था करके सूचीबद्ध शेयरों के अंतरण के मामलों में दीर्घावधिक पूंजी लाभों से प्राप्त छूट को सीमित किए जाने का प्रस्ताव है कि कतिपय अपवादों की अधिसूचना के अध्यधीन छूट उपलब्ध होगी यदि प्रतिभूति लेनदेन कर का ऐसे शेयरों के अधिग्रहण के समय समय भुगतान किया गया हो जहां इन्हे 1 अक्टूबर, 2004 के बाद अधिग्रहित किया गया हो।

1.5 आयकर अधिनियम में नए प्रावधान लाए जाने का प्रस्ताव है ताकि जिनके बही खातों की लेखापरीक्षा किया जाना अपेक्षित है, उनको छोड़कर व्यष्टि अथवा हिंदु अविभक्त परिवार द्वारा प्रतिमाह ₹50,000 से अधिक राशि के किराया भुगतान करते समय 5 प्रतिशत की दर से स्रोत पर कटौती की जा सके। यह भी प्रस्ताव है कि ऐसे कर की चालान-सह-विवरणी के माध्यम से वित्त वर्ष में केवल एक बार कटौती किए जाने और जमा किए जाने की व्यवस्था की जा सके। इसके अतिरिक्त, कटौतीकर्ता को इस प्रयोजनार्थ टैन प्राप्त करने अथवा पृथक टीडीएस विवरण प्रस्तुत करने की आवश्यकता नहीं होगी।

1.6 अंतरण मूल्य निर्धारण प्रावधानों को ओईसीडी अंतरण मूल्य निर्धारण दिशानिर्देशों और अंतरराष्ट्रीय सर्वोत्तम व्यवहार के अनुरूप बनाने के लिए नई धारा सम्मिलित करने का प्रस्ताव है ताकि यह व्यवस्था की जा सके कि निर्धारित वित्तीय समायोजन करेगा जहां कतिपय मामलों में अंतरण मूल्य का आरंभिक समायोजन किया गया हो। यह प्रावधान तभी प्रयोज्य होगा यदि आरंभिक समायोजन एक करोड़ रुपये से अधिक हो और समायोजन से संबंधित अतिरिक्त राशि निर्धारित समय में भारत में न लाई गई हो।

1.7 विरल पूंजीकरण के मुद्दे के समाधान के लिए यह प्रस्ताव किया जाता है कि यदि किसी भारतीय कंपनी अथवा किसी विदेशी कंपनी की स्थायी स्थापना द्वारा ब्याज, कर, मूल्यहास और परिशोधन (ईबीआईटीडीए) से पहले अर्जन के तीस प्रतिशत से अधिक अदा किया गया ब्याज अथवा अपने सहयोगी उद्यम को प्रदत्त ब्याज, जो भी कम हो, की उसके कर योग्य लाभ परिकलन में कटौती के रूप में अनुमति नहीं होगी। यह भी प्रस्ताव है कि आठ निर्धारण वर्षों के लिए प्रतिबंधित अग्रेनय और ब्याज संमजन की अनुमति दी जाए।

1.8 स्व-स्वमित्ववाली संपत्ति की तुलना में किराए पर दी गई संपत्ति के संबंध में ब्याज कटौती की मौजूदा विसंगति का समाधान करने के लिए, चालू वर्ष के दौरान किसी अन्य शीर्ष के अंतर्गत आय के मुकाबले आवास संपत्ति से हुई हानि के समंजन को दो लाख रुपये तक सीमित रखने का प्रस्ताव किया जाता है। ऐसी असंमजित हानि को आठ निर्धारण वर्षों के लिए आवास संपत्ति के प्रति समंजन के लिए अग्रेनीत किए जाने की अनुमति दी जाएगी।

1.9 प्रस्ताव किया जाता है कि धारा 12क के अंतर्गत पंजीकृत अथवा धारा 10(23ग) के अंतर्गत अनुमोदित किसी कंपनी द्वारा धारा 12क के अंतर्गत पंजीकृत अन्य कंपनी को किया गया दान इस निदेश के साथ किया गया हो कि ऐसा दान निधि का हिस्सा होगा, को धर्मार्थ प्रयोजनों के लिए आय का अनुप्रयोग नहीं माना जाएगा।

2. युक्तिकरण के उपाय

2.1 यह प्रस्ताव किया जाता है कि विदेशी कंपनी के मामले में, करार अथवा व्यवस्था की समाप्ति के पश्चात् रणनीतिक पेट्रोलियम भंडार के मामले में, कच्चे तेल के शेष स्टॉक की बिक्री कतिपय शर्तों को पूरा करने के अध्यक्षीन भारत में कर योग्य नहीं होगी।

2.2 कार्बन क्रेडिट की बिक्री से उत्पन्न आय के मामले में 10 प्रतिशत रियायती कर देने का प्रस्ताव किया जाता है।

2.3 यात्रियों के परिवहन का व्यवसाय करने वाले सरकारी, विदेशी मिशनों और राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों को वाहनों की खरीद से संबंधित स्रोत पर संग्रहित कर (टीसीएस) के प्रावधानों से छूट देने का प्रस्ताव है।

2.4 यह प्रस्ताव किया जाता है कि परिसंपत्ति का उचित बाजार मूल्य जिस पर कि अधिमाम्य आय की गणना के प्रयोजनार्थ विचार किया गया हो, जिस पर आयकर अधिनियम के अध्याय XII डख के प्रावधानों के अनुसार कर का भुगतान किया गया हो, को उस परिसंपत्ति के अधिग्रहण की लागत माना जाएगा।

2.5 आयकर अधिनियम की धारा 9क के अंतर्गत अपतटीय निधियों की विशेष कराधान प्रणाली की शर्तों में संशोधन करने का प्रस्ताव किया जाता है ताकि यह व्यवस्था की जा सके कि उस वर्ष में न्यूनतम निधि आकार को बनाए रखना अनिवार्य नहीं होगा जिसमें निधि का समापन किया जा रहा हो।

2.6 प्रधानमंत्री राहत कोष और अन्य कतिपय निधियों के लिए उपलब्ध छूट की तर्ज पर यह प्रस्ताव है कि मुख्यमंत्री राहत कोष और उप राज्यपाल राहत कोष की आय कर से मुक्त की जाए।

2.7 उन प्रावधानों को समाप्त किए जाने का प्रस्ताव है जिनके अंतर्गत कर निर्धारक अधिकारी को उन मामलों, जिनमें संवीक्षा हेतु विवरणी का चयन किया गया हो, में विवरण की प्रक्रिया न करके निर्धारण के समय तक विवरण को रोकने की शक्ति प्रदान की गई है। तथापि, यह प्रस्ताव किया जाता है कि जिन मामलों में कर वापसी की मंजूरी से राजस्व पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना है, उन कारणों को लिखित में दर्ज करने के पश्चात् उच्चाधिकारी के अनुमोदन से इसे रोका जा सकता है।

2.8 यह प्रस्ताव किया जाता है कि कतिपय प्रतिष्ठानों जैसे निवेशक संरक्षण निधि, कोर निपटान गारंटी कोष, चाय/कॉफी/रबड़ बोर्ड, एमपीईडीए अथवा एपीडीईए जो आयकर अधिनियम की धारा 10 के अंतर्गत आयकर से छूट का लाभ प्राप्त कर रहे हैं, को अपनी आय विवरण प्रस्तुत करना अपेक्षित है।

- 2.9 आय विवरण समय पर प्रस्तुत हो, यह सुनिश्चित करने के लिए, विवरणी प्रस्तुति में विलम्ब के मामले में शुल्क लगाने का प्रस्ताव किया जाता है।
- 2.10 यह प्रस्ताव किया जाता है कि यदि लेखाकार अथवा मर्चेन्ट बैंकर अथवा पंजीकृत मूल्यांकन रिपोर्ट अथवा प्रमाणपत्र में गलत सूचना देता है, तो उस पर ऐसी प्रत्येक चूक के लिए दस हजार रुपये का आर्थिक दंड लगाया जाएगा।
- 2.11 यह प्रस्ताव किया जाता है कि जहां आयकर अधिनियम की धारा 115जख अथवा 115जग के अंतर्गत प्रदत्त कर के लिए विदेशी कर क्रेडिट (एफटीसी) की राशि अधिनियम के अन्य प्रावधानों के अनुसार निर्धारिती द्वारा उसकी आय पर देय कर के लिए स्वीकार्य एफटीसी की राशि से अधिक हो, तो धारा 115जकक अथवा धारा 115जघ के अंतर्गत क्रेडिट राशि की गणना करते समय ऐसे अतिरिक्त क्रेडिट को नजरअंदाज किया जाएगा।
- 2.12 उस मामले में जहां ऐसे कर के भुगतान में विवाद होने के कारण विदेशी कर क्रेडिट निर्धारिती को नहीं दी गई हो, कतिपय शर्तों के अध्यधीन ऐसे विवाद का निपटारा हो जाने के बाद उक्त कर क्रेडिट को अनुमत करने के लिए निर्धारक अधिकारी को अतिरिक्त समय देने का प्रस्ताव है।
- 2.13 यह प्रस्ताव है कि एक दिन में एक लेन देन या एक ही अवसर से संबंधित लेनदेन में कोई भी व्यक्ति तीन लाख रुपये की राशि का भुगतान या कुल भुगतान प्राप्त नहीं करेगा परन्तु खाते में भुगतान चैक के द्वारा या खाते में भुगतान वाले बैंक ड्राफ्ट या बैंक खाते के जरिए इलेक्ट्रॉनिक क्लीयरिंग सिस्टम के उपयोग से वह प्राप्त कर सकता है। ऐसा प्रतिबंध सरकारी बैंकों या ऐसा अन्य व्यक्तियों या व्यक्तियों के वर्ग या केन्द्रीय सरकार द्वारा अधिसूचित प्राप्ति के लिए लागू नहीं होगा। यदि इस प्रावधान का उल्लंघन होता है तो इसके लिए दण्ड का प्रावधान करने का भी प्रस्ताव है।
- 2.14 यह स्पष्ट करने का प्रस्ताव है कि स्रोत पर कर कटौती से संबंधित प्रावधान भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास और पुनः बंदोबस्ती अधिनियम, 2013 में उचित समुचित क्षतिपूर्ति और पारदर्शिता के अधिकार के तहत प्राप्त क्षतिपूर्ति में छूट देने के लिए लागू नहीं होगा।
- 2.15 केवल कॉल सेन्टर के कारोबार में लगे व्यक्ति को किए गए भुगतान के मामले में कर कटौती की दर कम करने का प्रस्ताव है।
- 2.16 प्रस्ताव है कि कंपनी के अधिमान शेयरों को उसी कंपनी के इक्विटी में परिवर्तित करने के मामले में कर तटस्थता प्रदान की जाए।
- 2.17 प्रस्ताव है कि कर तटस्थ अविलयन में प्राप्त भारतीय कंपनी के शेयर की खरीद की लागत को परिणामी विदेशी कंपनी के हाथ में खरीद की लागत के रूप में लिया जाएगा।
- 2.18 टीडीएस के अधिभुगतान की वापसी के मामले में ब्याज देने का प्रस्ताव है।
- 2.19 सीमा शुल्क के लिए एएआर, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और सेवा कर के साथ आय के लिए एडवांस रूलिंग प्राधिकरण का विलय करने और सामान्य एएआर बनाने का प्रस्ताव है। अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति के लिए योग्यताओं में संशोधन करने का भी प्रस्ताव है।
- 2.20 न्यायाधिकरण के समक्ष अपील योग्य आयकर अधिनियम की धारा 10(23ग) के तहत प्रधिकरण द्वारा आदेश पारित कराने का प्रस्ताव है।

- 2.21 केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड को स्रोत पर कर कटौती और संग्रहण से संबंधित शास्ति अधिरोपित करने के संबंध में करदाताओं द्वारा सामना की जाने वाली कठिनाइयों को हटाने के लिए निदेशन या अनुदेशन जारी करने हेतु प्राधिकृत करने का प्रस्ताव है।
- 2.22 न्यूनतम वैकल्पिक कर लगाने के प्रयोजन से बुक प्रोफिट की संगणना से संबंधित उपबंधों में संशोधन लाने का प्रस्ताव है ताकि इसे भारतीय लेखाकरण मानकों के समरूप बनाया जा सके।
- 2.23 यह स्पष्ट करने का प्रस्ताव है कि निजी लिमिटेड कंपनी के शेयर के अंतरण के संबंध में कर की रियायती दर की व्यवस्था वाले आय कर अधिनियम की धारा 112 में वित्त अधिनियम, 2016 द्वारा किया गया संशोधन निर्धारण वर्ष 2013-14 से भूतलक्षी प्रभाव से लागू होगा।
- 2.24 आय कर अधिनियम की धारा 10कक में संशोधन लाने का प्रस्ताव है ताकि यह व्यवस्था की जा सके कि इसके अंतर्गत उल्लिखित कटौती की राशि को उक्त धारा के उपबंधों को लागू करने के पहले अधिनियम के उपबंधों के अनुसार संगणित कुल आय से अनुमत की जाएगी और यह कि उक्त कटौती कुल आय से अधिक नहीं होगी।
- 2.25 यह स्पष्ट करने का प्रस्ताव है कि चाहे कर में प्रभार योग्य हो या न हो किसी राशि का भुगतान अनिवासी को करने से संबंधित सूचना देने के मामले में "भुगतान करने के लिए उत्तरदायी व्यक्ति" अपने आप भुगतानकर्ता होगा या यदि भुगतान करता कंपनी हो, तो वह उसके मुख्य अधिकारी सहित कंपनी ही होगी।
- 2.26 यह प्रावधान करने का प्रस्ताव है कि जहां आय कर अधिनियम की धारा 90 की उप-धारा (1) और 90क के तहत किए गए करार में प्रयुक्त कोई 'शब्द' उक्त करार के तहत परिभाषित किया जाता है, तो उस शब्द का वही अर्थ होगा जैसाकि उक्त करार में दिया गया है और जहां करार में शब्द परिभाषित नहीं है, परन्तु अधिनियम में परिभाषित है, तो इसका वही अर्थ होगा जो अधिनियम या केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किसी तकनीकी स्पष्टीकरण में दिया गया है।
- 2.27 यह प्रावधान करने का प्रस्ताव है कि जहां आयकर अधिनियम की धारा 35कघ में उल्लिखित पूंजी आस्ति अर्हक कारोबार में प्रयुक्त होती है, और उक्त धारा का लाभ समाप्त किया जाए, तो ऐसी आस्ति के संबंध में निर्धारित के लिए वास्तविक लागत, निर्धारित की वास्तविक लागत होगी, क्योंकि लागू दर पर परिकलित मूल्यहास की राशि के समतुल्य राशि द्वारा घटाई जाती है, वह अनुमेय हो सकती थी, यदि अपनी अधिप्राप्ति की तारीख से उस राशि का उपयोग कारोबार के प्रयोजनों से किया गया होता।
- 2.28 यह प्रावधान करने का प्रस्ताव है कि एक न्यास या संस्था, जिसका पंजीकरण किया गया है, और बाद में उद्देश्यों को अपनाया या आशोधित किया है जो पंजीकरण की शर्तों के अनुरूप नहीं है, तो उसे नया पंजीकरण प्राप्त करने की आवश्यकता होगी।
- 2.29 टीसीएस के क्षेत्र को सुदृढ़ करने के लिए यह प्रावधान करने का प्रस्ताव है कि कर जमा करने वाला संग्रहणकर्ता के समक्ष अपना पैन (स्थायी खाता संख्या) प्रस्तुत करेगा, ऐसा न करने पर उच्च दर पर कर संग्रहण किया जाएगा।
- 2.30 कर्मचारी और स्वरोजगार व्यष्टि के बीच संगतता लाने के लिए यह व्यवस्था करने का प्रस्ताव है कि स्वरोजगार व्यष्टि राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली न्यास में किए गए अंशदान के संबंध में, अपनी सकल कुल आय का बीस प्रतिशत तक कटौती के लिए अर्हक होगा।

- 2.31 यह प्रावधान करने का प्रस्ताव है कि प्राधिकृत अधिकारी, विनिर्दिष्ट शर्तों के अध्वधीन राजस्व के हित का संरक्षण करने के लिए छह माह की अवधि के लिए अनंतिम रूप से सम्पत्ति की कुर्की कर सकता है। यह प्रावधान करने का भी प्रस्ताव है कि सम्पत्ति के एफएमवी के अनुमान के प्रयोजन से मूल्यांकन अधिकारी को भेज सकता है।
- 2.32 आयकर के संयुक्त निदेशक, उप निदेशक या सहायक निदेशक को उच्चतर अधिकारी का अनुमोदन लिए बगैर किसी पूछ-ताछ के प्रयोजन से सूचना मांगने हेतु प्राधिकृत करने का प्रस्ताव है।
- 2.33 आयकर अधिनियम की धारा 133क के उपबंधों का विस्तार करने का प्रस्ताव है ताकि किसी स्थान को शामिल किया जा सके जहां धर्मार्थ प्रयोजन से क्रियाकलाप किए जा सकें।
- 2.34 सीबीडीटी को, अपने पास उपलब्ध सूचना के सत्यापन, ऐसे दस्तावेजों के प्रक्रियान्वयन और उसके परिणाम निर्धारण अधिकारी को उपलब्ध कराने के प्रयोजन से सूचना और दस्तावेज मांगने के लिए केन्द्रीकृत नोटिस जारी करने के लिए स्कीम बनाने हेतु प्राधिकृत करने का प्रस्ताव है।
- 2.35 कठिनाइयों को दूर करने के लिए वित्त अधिनियम 2016 की धारा 197(ग) को हटाने का प्रस्ताव है, जिसमें आय प्रकटीकरण स्कीम, 2016 के शुरू होने से पहले किसी अवधि से संबंधित अप्रकट आय के निर्धारण के लिए व्यवस्था की गई है। तथापि, तलाशी मामलों में, यह उपबंध किए जाने का प्रस्ताव है कि यदि तलाशी के दौरान कोई स्पष्ट साक्ष्य पाया जाता है, तो निर्धारक अधिकारी जिस वर्ष में तलाशी ली गई थी उससे पूर्ववर्ती दस वर्षों तक आय का निर्धारण कर सकता है।
- 2.36 स्रोत पर कर कटौती उपबंधों को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से, यह उपबंधित किए जाने का प्रस्ताव है कि अन्य स्रोतों से आय में से किए गए किसी व्यय के संबंध में तब तक किसी कटौती की अनुमति नहीं होगी जब तक उस पर लागू दरों पर कर की कटौती न की गई हो।
- 2.37 सूचना के स्रोत और सूचना प्रदाता की पहचान की गोपनीयता बनाए रखने के लिए, यह स्पष्ट किए जाने का प्रस्ताव है कि आयकर प्राधिकारी द्वारा किसी तलाशी अभियान को प्राधिकृत करने या लेखा बाहियों या आस्ति के उपार्जन के रूप में रिकार्ड किए जाने वाले विश्वास के कारणों को किसी व्यक्ति, प्राधिकरण या अपीलीय अधिकरण को प्रकटित नहीं किया जाएगा।
- 2.38 यह उपबंधित किए जाने का प्रस्ताव है कि समेकित योजना में इकाई के बदले में प्राप्त म्युचुअल फंड योजना की समेकित योजना में इकाई के मामले में, धारिता की वास्तविक लागत और अवधि समेकन योजना में इकाई की धारिता और अवधि होगी।
- 2.39 आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 10 के खंड 4 के उपबंध को संशोधित किए जाने का प्रस्ताव है ताकि विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम (फेमा) को सही संदर्भ दिया जा सके।
- 2.40 सूचीबद्ध इक्विटी शेयरों और इक्विटी अभिमुख निधि की सूचीबद्ध इकाईयों में निवेश के संबंध में कतिपय व्यक्तियों को अनुमत कटौती के संबंध में समापन खंड का उपबंध करने का प्रस्ताव है।
- 2.41 किसी गैर निवासी द्वारा गैर निवासी को रुपया मुद्रांकित बांड के अंतरण से अर्जित होने वाले पूंजीगत लाभों को छूट प्रदान करने का प्रस्ताव है।

अप्रत्यक्ष कर

I. शुल्क/कर दरों में परिवर्तन वाले प्रस्ताव:

सीमा शुल्क :

		पण्य	शुल्क दर	
			से	तक
I.	घरेलू मूल्य वर्धन "मेक इन इंडिया" को सुग्राही बनाना			
क.	लागत में कमी लाने के लिए इनपुट और कच्चे माल पर सीमा शुल्क ड्यूटी कम करना			
		खनिज ईंधन और खनिज तेल		
	1.	तरल प्राकृतिक गैस	बीसीडी 5%	बीसीडी 2.5%
		रसायन और पेट्रो रसायन		
	2.	मध्यम क्वालिटी टेरिफ्थेलिक एसिड (एमटीए) और क्वालिफाइड टेरिफ्थेलिक एसिड (क्यूटीए)	बीसीडी 7.5%	बीसीडी 5%
		धातुएं		
	3.	निकल	बीसीडी.2.5%	बीसीडी-शून्य
		तैयार चर्म		
	4.	वनस्पतिक रंगाई एक्सट्रेक्ट्स, नामतः वैटल एक्सट्रेक्ट और मिरोबालन फ्रूट एक्सट्रेक्ट	बीसीडी 7.5%	बीसीडी 2.5%
		पूंजीगत सामान		
	5.	बाल स्कू, लिनियर मोशन गाइड्स एन्ड सीएनजी सिस्टम-सीएनसी मशीन उपकरणों के विनिर्माण में प्रयोग हेतु, वास्तविक प्रयोक्ता शर्त के अध्वधीन	बाल स्कू एवं रैखिक गति गाइड्स बीसीडी 7.5% सीएनसी सिस्टम बीसीडी 10%	बीसीडी 2.5%
		नवीकरणीय ऊर्जा		
	6.	देश में स्थापित किए जाने वाली या प्रदर्शन के प्रयोजनार्थ ईंधन प्रकोष्ठ आधारित विद्युत उत्पादन प्रणालियों हेतु अपेक्षित सभी मर्दे, कतिपय विनिर्दिष्ट शर्तों के अध्वधीन	बीसीडी 10% / 7.5% सीवीडी - 12.5%	बीसीडी 5% सीवीडी 6%
	7.	बायोगैस/बायो-मिथेन/बाइ-प्रोजेक्ट हाइड्रोजन पर संचालित संतुलन प्रणालियों हेतु अपेक्षित अन्य मर्दे, कतिपय विनिर्दिष्ट शर्तों के अध्वधीन	बीसीडी 10% / 7.5% सीवीडी 12.5%	बीसीडी 5% सीवीडी 6%
		विविध		
	8.	एलईडी लाइटों या फिक्सचरों, एलईडी बल्बों सहित, के विनिर्माण में उपयोग हेतु सभी पुर्जे, वास्तविक प्रयोक्ता शर्त के अध्वधीन	प्रयोज्य बीसीडी, सीवीडी	बीसीडी 5% सीवीडी 6%
	9.	एलईडी लाइटों या फिक्सचरों, एलईडी बल्बों सहित, के लिए एलईडी ड्राइवर तथा एमसीपीसीबी में उपयोग हेतु सभी इनपुट	प्रयोज्य बीसीडी	5%

		पण्य	शुल्क दर	
			से	तक
ख.	कतिपय क्षेत्रों में शुल्क इन्वर्जन की समस्या से निपटने के लिए सीमा शुल्क और उत्पाद शुल्क/सीवी ड्यूटी में परिवर्तन			
		रसायन और पेट्रोरसायन		
	10.	ओ-जाइलीन	बीसीडी 2.5%	बीसीडी शून्य
	11.	हाइड्रोजन पेरोक्साइड ईथर के विनिर्माण में उपयोग हेतु 2-इथेलेन्थाक्विलोन (29146990), वास्तविक प्रयोक्ता शर्त के अध्यक्षीन	बीसीडी 7.5%	बीसीडी 2.5%
	12.	पोली कार्बोजिलेट ईथर के विनिर्माण में उपयोग हेतु विनाइल पोलिथिलीन ग्लोकोल (वीपीईजी), वास्तविक प्रयोक्ता शर्त के अध्यक्षीन	बीसीडी 10%	बीसीडी 7.5%
		कपड़ा		
	13.	ट्यूना फिशिंग के लिए मोनोफिलामेंट लांग लाइन सिस्टम में उपयोग हेतु नाइलॉन मोनो फिलामेंट यार्न	बीसीडी 7.5%	बीसीडी 5%
		धातुएं		
	14.	वास्तविक प्रयोक्ता की शर्त के अध्यक्षीन निर्दिष्ट टेलीकाम ग्रेड आप्टीकल फाइबर केबल्स के विनिर्माण हेतु को-पॉलीमर कोटेड एमएसटेप्स/ स्टेनलैस स्टील टेप्स	बीसीडी शून्य	बीसीडी 10%
	15.	वास्तविक प्रयोक्ता की शर्त के अध्यक्षीन सीआरजीओ स्टील के विनिर्माण में प्रयोग के लिए एमजीओ कोटेड कोल्ड रोल्ड स्टील कायल्स (7225 19 90)	बीसीडी 10%	बीसीडी 5%
	16.	वास्तविक प्रयोक्ता की शर्त पर हेडिंग 7305 और 7306 के अंतर्गत आने वाले वेल्डिड ट्यूब्स और पाइप्स के विनिर्माण में प्रयोग के लिए हॉट रोल्ड कायल्स (7208)	बीसीडी 12.5%	बीसीडी 10%
		आटोमोबाइल्स		
	17.	कैटालाइटिक कन्वर्टर्स के लिए सिरैमिक सबस्ट्रेट के विनिर्माण में प्रयोग हेतु क्ले 2 पावडर (एलुमैक्स)	बीसीडी 7.5%	बीसीडी 5%
		नवीकरणीय ऊर्जा		
	18.	सोलर सेल्स/पैनल्स/माड्यूल्स के विनिर्माण में प्रयोग हेतु सोलर टेम्पर्ड ग्लास	बीसीडी 5%	बीसीडी शून्य
	19.	वास्तविक प्रयोक्ता शर्त के अध्यक्षीन सोलर फोटोवाल्टिक सेल्स/माड्यूल्स, सोलर पावर जनरेटिंग इक्विपमेंट अथवा प्रणालियों, फ्लैट प्लेट सोलर कलेक्टर, सोलर फोटोवाल्टिक माड्यूल और वाटर पंपिंग और अन्य प्रयोगों हेतु पैनल के लिए पार्ट्स/कच्चा माल	सीवीडी 12.5%	सीवीडी 6%
	20.	वास्तविक प्रयोक्ता शर्त के अध्यक्षीन विंड आपरेडिट एनर्जी जनरेटर्स (डब्ल्यूओइजी) के लिए कास्ट कंपोनेंट्स के विनिर्माण में प्रयोग हेतु रेसिन और केटालिस्ट	बीसीडी 7.5% सीवीडी 12.5% एसएडी 4%	बीसीडी 5% सीवीडी शून्य एसएडी शून्य
		विविध		
	21.	वास्तविक प्रयोक्ता शर्त के अध्यक्षीन हाउसहोल्ड टाइप फिल्टर्स हेतु आरओ मेंबरेन एलीमेंट के विनिर्माण में प्रयोग हेतु मेंबरेन शीट और ट्राइकोट/स्पेसर	सीवीडी 12.5%	सीवीडी 6%

		पण्य	शुल्क दर	
			से	तक
ग.	घरेलू उद्योग को समुचित संरक्षण देने के लिए सीमाशुल्क में परिवर्तन			
		खाद्य प्रसंस्करण		
	22.	काजू, भुना नमकीन अथवा भुना और नमकीन	बीसीडी 30%	बीसीडी 45%
		इलेक्ट्रानिक्स / हार्डवेयर		
	23.	वास्तविक प्रयोक्ता शर्त के अध्यक्षीन, मोबाइल फोनों के विनिर्माण हेतु पापुलेटिड प्रिंटेड सर्किट बोर्ड	एसएडी शून्य	एसएडी 2%
		विविध		
	24.	घरेलू टाइप के फिल्टर्स हेतु आरओ मेंबरेन एलीमेंट	बीसीडी 7.5%	बीसीडी 10%
घ.	कैशलेस लेनदेनों को बढ़ावा देना और उनके लिए प्रयोग होने वाले साधनों के घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देना			
	25.	क) एम-पीओएस हेतु मिनिचराइज्ड पीओएस कार्ड रीडर (मोबाइल फोन अथवा अन्य मोबाइल साधन शामिल नहीं) ख) मानक वर्जन 1.5.1 के अनुसार माइक्रो एटीएम ग) फिंगर प्रिंट रीडर/स्केनर, और घ) आइरस स्केनर	प्रयोज्य बीसीडी, सीवीडी, एसएडी	बीसीडी शून्य सीवीडी शून्य एसएडी शून्य
	26.	निम्न के विनिर्माण हेतु कलपुर्जे : क)एम-पीओएस हेतु मिनिचराइज्ड पीओएस कार्ड रीडर (मोबाइल फोन अथवा अन्य मोबाइल साधन शामिल नहीं) ख) मानक वर्जन 1.5.1 के अनुसार माइक्रो एटीएम ग) फिंगर प्रिंट रीडर/स्केनर, और घ) आइरस स्केनर	प्रयोज्य बीसीडी, सीवीडी, एसएडी	बीसीडी शून्य सीवीडी शून्य एसएडी शून्य
II.	घरेलू संसाधनों के परिरक्षण हेतु निर्यात शुल्क लगाना			
	27.	लेटराइट सहित अन्य एल्युमिनियम अयस्क	शून्य	15%
III.	ईज आफ डुइंग बिजनेस में सुधार करना और निर्यात संवर्धन			
	28.	पार्सलों, पैकेटों और पत्रों के जरिए आयातित वस्तुओं के लिए डी-मिनिमिस सीमाशुल्क छूट	प्रति सामान 100 रुपए से अधिक शुल्क देय नहीं	प्रति सामान 1000 रुपए से अधिक सीआईएफ मूल्य नहीं
	29.	निर्यात के लिए कथित माल के विनिर्माण में प्रयोग हेतु चमड़े के जूते अथवा सिथेंटिक फुटवियर अथवा अन्य चमड़ा उत्पादों के विनिर्माण हेतु पात्र मदों के शुल्क मुक्त आयात की सीमा	पिछले वित्त वर्ष के दौरान निर्यात की गई कथित वस्तुओं के एफओबी मूल्य का 3%	पिछले वित्त वर्ष के दौरान निर्यात की गई कथित वस्तुओं के एफओबी मूल्य

		पण्य	शुल्क दर	
			से	तक
				का 5%
IV.	करवंचन-रोधी उपाय			
	30.	99.9% से नीचे नहीं के सिल्वर कंटेनर वाले सिल्वर मेडल, सिल्वर के सिक्के और सिल्वर का अर्ध-निर्मित रूप	सीवीडी शून्य	सीवीडी 12.5%

- टिप्पणी:** (क) "बुनियादी सीमा शुल्क" का अर्थ है सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 के अंतर्गत लगाया गया सीमाशुल्क।
- (ख) "सीवीडी" का अर्थ है सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम 1975 की धारा 3 की उप-धारा (1) के अंतर्गत लगाया गया अतिरिक्त सीमा शुल्क।
- (ग) "एसएडी" का अर्थ है सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम 1975 की धारा 3 की उप-धारा (5) के अंतर्गत लगाया गया सीमा शुल्क का विशेष अतिरिक्त शुल्क।
- (घ) "निर्यात शुल्क" का अर्थ है सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम 1975 की दूसरी अनुसूची में निर्दिष्ट वस्तुओं पर प्रभावी सीमा शुल्क।

उत्पाद शुल्क

		पण्य	शुल्क की दर	
			से	तक
I.	जन स्वास्थ्य			
क.	तंबाकू और तंबाकू उत्पाद			
	1.	सिगार और चिरुट	12.5% अथवा 3755 रुपए प्रति हजार जो भी अधिक हो	12.5% अथवा 4006 रुपए प्रति हजार, जो भी अधिक हो
	2.	सिगारिलोस	12.5% अथवा 3755 रुपए प्रति हजार जो भी अधिक हो	12.5% अथवा 4006 रुपए प्रति हजार, जो भी अधिक हो
	3.	तंबाकू रहित सिगरेट	प्रति हजार 3755 हजार रुपये	प्रति हजार 4006 हजार रुपये
	4.	तंबाकू रहित सिगारिल्लो	12.5% अथवा 3755 रुपए प्रति हजार जो भी अधिक हो	12.5% अथवा 4006 रुपए प्रति हजार, जो भी अधिक हो
	5.	तंबाकू रहित अन्य	12.5% अथवा 3755 रुपए प्रति हजार जो भी अधिक हो	12.5% अथवा 4006 रुपए प्रति हजार, जो भी अधिक हो
	6.	पेपर रोल बीड़ी - हस्त निर्मित	प्रति हजार 21 रुपये	प्रति हजार 28 रुपये
	7.	पेपर रोल बीड़ी - मशीन निर्मित	प्रति हजार 21 रुपये	प्रति हजार 78 रुपये
II.	घरेलू मूल्य वर्धन को प्रोत्साहन, "मेक इन इंडिया"			
क.	नवीकरणीय ऊर्जा			
	8.	बायोगैस/बायोमिथेन/उप-उत्पादक हायड्रोजन पर सिस्टम आपरेटिंग के संतुलन के लिए अपेक्षित सभी वस्तुएं	12.5%	6%
ख. विविध				
	9.	घरेलू फिल्टरों के लिए आरओ मेम्ब्रेन तत्व के विनिर्माण में प्रयोग के लिए मेम्ब्रेन शीट और ट्राइकोट/स्पेसर वास्तविक प्रयोक्ता शर्त के अध्याधीन	12.5 प्रतिशत	6 प्रतिशत

		पण्य	शुल्क की दर	
			से	तक
	10.	वास्तविक प्रयोक्ता शर्त के अधधीन एलईडी लैम्पों सहित एलईएडी लाइट अथवा फिक्स्चर के विनिर्माण के लिए सभी पुर्जें	प्रयोज्य शुल्क	6 प्रतिशत
	11.	क. अध्याय 71 में आने वाली वस्तुओं के विनिर्माण के दौरान उत्पन्न कीमती धातुओं के कबाड़ अथवा कीमती धातुओं में लिपटी धातुएं ख. स्ट्रिप्स, वायर, प्लेट्स और सिल्वर फॉयल ग. हीरा, माणिक्य, पन्ना अथवा नीलम जड़े के अलावा सिल्वर आभूषणों के सामान घ. 99.9% और इससे अधिक शुद्धता वाले चांदी के सिक्के जिनका ब्रांड नाम है और चांदी से निर्मित हैं, जिन पर सीमा शुल्क अथवा उत्पाद शुल्क अदा किया गया है।	शून्य	शून्य, इस शर्त के अधधीन कि ऐसी वस्तुओं के विनिर्माता द्वारा निविष्टियों अथवा निविष्टि सेवाओं या पूंजीगत वस्तुओं पर कोई शुल्क क्रेडिट नहीं किया है।
III. कैशलेस लेनदेनों को प्रोत्साहन और इसके लिए प्रयुक्त उपकरणों के घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देना				
	12.	क) एम-पीओएस हेतु मिनिचराइज्ड पीओएस कार्ड रीडर (मोबाइल फोन अथवा अन्य मोबाइल साधन शामिल नहीं) ख) मानक वर्जन 1.5.1 के अनुसार माइक्रो एटीएम ग) फिगर प्रिंट रीडर/ स्केनर, और घ) आइरस स्केनर	प्रयोज्य शुल्क	शून्य
	13.	निम्न के विनिर्माण हेतु कलपुर्जे: क) एम-पीओएस हेतु मिनिचराइज्ड पीओएस कार्ड रीडर (मोबाइल फोन अथवा अन्य मोबाइल साधन शामिल नहीं) ख) मानक वर्जन 1.5.1 के अनुसार माइक्रो एटीएम ग) फिगर प्रिंट रीडर/ स्केनर, और घ) आइरस स्केनर	प्रयोज्य शुल्क	शून्य

टिप्पणी: "बुनियादी उत्पाद शुल्क" का अर्थ केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1985 की प्रथम अनुसूची में दिया गया उत्पाद शुल्क है।

वित्त अधिनियम, 2005 की धारा 85 के अंतर्गत लगाए गए अतिरिक्त शुल्क की दर में परिवर्तन

		पण्य	शुल्क दर	
			से	तक
क.	पान मसाला			
	1.	पान मसाला	6%	9%
ख.	तंबाकू और तंबाकू के उत्पाद			
	2.	अविनिर्मित तंबाकू	4.2%	8.3%
	3.	65 मि.मी. से अनधिक लम्बाई वाले फिल्टर रहित सिगरेट	प्रति हजार 215 रुपये	प्रति हजार 311 रुपये
	4.	65 मि.मी. से अधिक किन्तु 70 मि.मी. से अधिक लम्बाई वाले फिल्टर रहित सिगरेट	प्रति हजार 370 रुपये	प्रति हजार 541 रुपये
	5.	65 मि.मी. से अनधिक लम्बाई के फिल्टर सिगरेट	प्रति हजार 215 रुपये	प्रति हजार 311 रुपये
	6.	65 मि.मी. से अधिक किन्तु 70 मि.मी. से अनधिक लम्बाई वाले फिल्टर रहित सिगरेट	प्रति हजार 260 रुपये	प्रति हजार 386 रुपये
	7.	70 मि.मी. से अधिक किन्तु 75 मि.मी. से अनधिक लम्बाई वाले फिल्टर रहित सिगरेट	प्रति हजार 370 रुपये	प्रति हजार 541 रुपये
	8.	अन्य सिगरेट	प्रति हजार 560 रुपये	प्रति हजार 811 रुपये
	9.	चबाने वाला तंबाकू (फिल्टर खैनी सहित)	6%	12%
	10.	जर्दा की खुशबूवाला तंबाकू	6%	12%
	11.	तंबाकू वाला पान मसाला (गुटखा))	6%	12%

सेवा कर

	क्र.सं.	परिवर्तन	मौसूदा	प्रस्तावित
क.	संघ के सशस्त्र बलों को सेवा कर से राहत			
	1.	केंद्र सरकार की समूह बीमा योजनाओं के तहत थल सेना, नौसेना और वायु सेना के सदस्यों को जीवन बीमा के माध्यम से थल सेना, नौसेना और वायुसेना समूह बीमा निधियों द्वारा प्रदत्त या प्रदान किए जाने के लिए सहमत सेवाओं को 10 सितंबर, 2004 (वह तारीख जब जीवन बीमा की सेवाएं कर योग्य हुई) से सेवा कर से छूट दी जा रही है।	14%	शून्य

ख.	विवाद समाधान, कराधान की निश्चितता और अभियोजन का परिहार			
	1.	अधिसूचना सं.41/2016-एसटी दिनांक 22.09.2016, जिसमें राज्य सरकार औद्योगिक विकास निगमों/उपक्रमों द्वारा औद्योगिक इकाइयों को औद्योगिक प्लाटों का दीर्घावधिक पट्टा (30 वर्ष या अधिक) प्रदान करने के लिए देय सेवा कर, एक बारगी अपफ्रंट राशि (जिसे प्रीमियम, सलामी, लागत, कीमत, विकास प्रभार या किसी भी नाम से पुकारा जाए, कहा जाता है) से छूट दी गई है, को 1.6.2007 (वह तारीख जब अचल संपत्ति को किराये पर देने संबंधी सेवाएं कर योग्य हुई) से प्रभावी करने का प्रस्ताव है।	14%	शून्य
	2.	सेवा कर (मूल का निर्धारण) नियम 2006 के नियम 2क को 01.07.2010 से संशोधित किए जाने का प्रस्ताव है ताकि यह स्पष्ट किया जा सके कि वस्तुओं और भूमि या भूमि के अविभाजित हिस्से जैसा भी मामला हो, के अंतरण को समाहित करने वाली निर्माण-कार्य संबंधी संविदा के निष्पादन में सेवा के हिस्से के मूल्य में ऐसी भूमि में संपत्ति या भूमि के अविभाजित हिस्से का मूल्य शामिल नहीं होगा।	4.2%	4.2%
ग.	नागरिक उड्डयन मंत्रालय की क्षेत्रीय कनेक्टिविटी योजना का संवर्द्धन			
	1.	क्षेत्रीय कनेक्टिविटी योजना (आसीएस) के तहत, नागरिक उड्डयन मंत्रालय द्वारा यथा अधिसूचित क्षेत्रीय कनेक्टिविटी स्कीम एयरपोर्ट के प्रचालनों को प्रारंभ करने की तारीख से एक वर्ष की अवधि के लिए आरसीएस एयरपोर्ट से प्रारंभ या समाप्त होने वाली वायु मार्ग द्वारा यात्रियों के परिवहन की सेवाएं प्रदान करने के लिए एयरलाइन प्रचालन को देय अर्थक्षमता अंतर विधियन (वीजीएफ) की राशि के संबंध में प्रदान किए जा रहे सेवा कर से छूट।	14%	शून्य
घ.	उपायों का यौक्तिकीकरण			
	1.	प्रबंधन में स्नातकोत्तर डिप्लोमा हेतु प्रबंधन में दो पूर्ण वर्षीय आवासीय स्नातकोत्तर कार्यक्रमों के माध्यम से भारतीय प्रबंधन संस्थानों, जिनमें दाखिले आईआईएम द्वारा आयोजित कॉमन एडमिशन टेस्ट (कैट) के आधार पर किए जाते हैं, द्वारा प्रदत्त सेवाओं के संबंध में छूट को गैर-आवासीय कार्यक्रमों को भी शामिल करते हुए इन तक विस्तारित किया जा रहा है।	14%	शून्य
	2.	सेनवैट क्रेडिट नियमावली, 2004 के नियम 6 के स्पष्टीकरण-1(ड) को संशोधित किया जा रहा है ताकि जमाराशियां, ऋण और अग्रिम के माध्यम से सेवाएं मुहैया कराने वाली गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों सहित बैंकों और वित्तीय संस्थाओं को इसकी परिधि से बाहर रखा जा सके।		

	3.	वित्त अधिनियम, 1994 में "मानव उपभोग के लिए एल्कोहॉलिक शराब को छोड़ते हुए वस्तुओं के विनिर्माण या उत्पादन के समतुल्य किसी प्रक्रिया के निष्पादन के माध्यम से उत्पन्न सेवाओं" के संबंध में नकारात्मक सूची संबंधी प्रविष्टि को हटाए जाने और इसके बदले छूट अधिसूचना में रखे जाने का प्रस्ताव है। परिणामतः वित्त अधिनियम की धारा 65ख के खंड (40), जिसमें "विनिर्माण के समतुल्य प्रक्रिया" को परिभाषित किया गया है, को भी हटाए जाने और इसके बदले छूट अधिसूचना में रखे जाने का भी प्रस्ताव है।	शून्य	शून्य
--	----	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------	-------

सीमा शुल्क प्रशुल्क अधिनियम, 1975 की प्रथम अनुसूची में संशोधन

क्र. सं.	संशोधन
क.	संशोधन जिनसे शुल्क की दरें प्रभावित नहीं हैं:-
1.	<p>निम्नलिखित संशोधन निष्पादित किए गए:</p> <p>(i) गुआर मील और इसके उत्पादों के संबंध में प्रशुल्क मर्दें 1302 32 10 और 1302 32 20 और इससे संबंध प्रविष्टियों को हटाएं और नई प्रशुल्क मर्दों 1106 10 10 और 1106 10 90, को सृजित करें ताकि सीमा शुल्क प्रशुल्क को एचएस नामावली से सुमेलित किया जा सके।</p> <p>(ii) परिशोधित विरंजित (ब्लीचड) निर्गंधीकृत पाम स्टीयरिन के लिए नई प्रशुल्क मद 1511 90 30 को सृजित करें ताकि सीमा शुल्क प्रशुल्क को डब्ल्यूसीओ वर्गीकरण निर्णय के अनुसार सुमेलित किया जा सके।</p> <p>(iii) प्रशुल्क मर्दों 3823 11 11 से 3823 11 90 तक और इससे संबंध प्रविष्टियों को प्रशुल्क मद 3823 11 00 से प्रतिस्थापित करें।</p> <p>(iv) प्रशुल्क मर्दों 3904 10 10 से 3904 22 90 तक प्रशुल्क मर्दें 3904 10 10 से 3904 22 00 के स्थान पर पीवीसी रेसिन के संबंध में प्रतिस्थापित करें।</p>
2.	अध्याय 98 का अध्याय नोट(4) को संशोधित किया जा रहा है ताकि कूरियर सेवा के माध्यम से आयातित वस्तुओं पर 9803 और 9804 शीर्षों की गैर-प्रयोज्यता को समाप्त किया जा सके। इसके अतिरिक्त, 9804 शीर्ष को संशोधित किया जा रहा है ताकि इस शीर्ष के तहत कूरियर, समुद्र या भूमि के माध्यम से व्यक्तिगत आयातों के वर्गीकरण को बढ़ाया जा सके।

प्रशांत गोयल, संयुक्त सचिव (बजट)

MINISTRY OF FINANCE
(Department of Economic Affairs)
(BUDGET DIVISION)

NOTIFICATION

New Delhi, the 1 st February, 2017

F. No. 2(9)-B(D)/2017.—The following is issued for general information :—

Budget 2017-2018

Speech of

Arun Jaitley

Minister of Finance

February 1, 2017

Madam Speaker,

On this auspicious day of *Vasant Panchami*, I rise to present the Budget for 2017-18. Spring is a season of optimism. I extend my warm greetings to everyone on this occasion.

2. Madam Speaker, our Government was elected amidst huge expectations of the people. The underlying theme of countless expectations was good governance. The expectations included burning issues like inflation and price rise, corruption in day to day transactions and crony capitalism. There was also expectation for a major change in the way the country's natural resources were allocated, processed and deployed.

3. In the last two and half years, it has been our mission to bring a Transformative Shift in the way our country is governed. We have moved

- from a discretionary administration to a policy and system based administration;
- from favouritism to transparency and objectivity in decision making;
- from blanket and loose entitlements to targeted delivery; and
- from informal economy to formal economy.

Inflation, which was in double digits, has been controlled; sluggish growth has been replaced by high growth; and a massive war against black money has been launched. We have worked tirelessly on all these fronts and feel encouraged by the unstinted support of the people to our initiatives. The Government is now seen as a trusted custodian of public money. I take this opportunity to express our gratitude to the people of India for their strong support.

4. We shall continue to undertake many more measures to ensure that the fruits of growth reach the farmers, the workers, the poor, the scheduled castes and scheduled tribes, women and other vulnerable sections of our society. Our focus will be on energising our youth to reap the benefits of growth and employment.

5. Madam Speaker, I am presenting this Budget when the world economy faces considerable uncertainty, in the aftermath of major economic and political developments during the last one year. Nevertheless, the International Monetary Fund (IMF) estimates that world GDP will grow by 3.1% in 2016 and 3.4% in 2017. The advanced economies are expected to increase their growth from 1.6% to 1.9% and the emerging economies from 4.1% to 4.5%. As per current indications, macro-economic policy is expected to be more expansionary in certain large

economies. Growth in a number of emerging economies is expected to recover in 2017, after relatively poor performance in 2016. These are positive signs and point to an optimistic outlook for the next year.

6. There are, however, three major challenges for emerging economies. First, the current monetary policy stance of the US Federal Reserve, to increase the policy rates more than once in 2017, may lead to lower capital inflows and higher outflows from the emerging economies. Second, the uncertainty around commodity prices, especially that of crude oil, has implications for the fiscal situation of emerging economies. It is however expected that increase, if any, in oil prices would get tempered by quick response from producers of shale gas and oil. This would have a sobering impact on prices of crude and petroleum. Third, in several parts of the world, there are signs of increasing retreat from globalisation of goods, services and people, as pressures for protectionism are building up. These developments have the potential to affect exports from a number of emerging markets, including India.

7. Amidst all these developments, India stands out as a bright spot in the world economic landscape. India's macro-economic stability continues to be the foundation of economic success. CPI inflation declined from 6% in July 2016 to 3.4% in December, 2016 and is expected to remain within RBI's mandated range of 2% to 6%. Favourable price developments reflect prudent macro-economic management, resulting in higher agricultural production, especially in pulses. India's Current Account Deficit declined from about 1% of GDP last year to 0.3% of GDP in the first half of 2016-17. Foreign Direct Investment (FDI) increased from ₹ 1,07,000 crores in the first half of last year to ₹ 1,45,000 crores in the first half of 2016-17. This marks an increase by 36%, despite 5% reduction in global FDI inflows. Foreign exchange reserves have reached 361 billion US Dollars as on 20th January, 2017, which represents a comfortable cover for about 12 months of imports.

8. The Government has also continued on the steady path of fiscal consolidation, without compromising on the public investment requirements of the economy. Externally, the economy successfully weathered a number of shocks, the redemption of FCNR deposits, volatility from the US elections and the Fed rate hike. According to IMF forecast, India is expected to be one of the fastest growing major economies in 2017.

9. A number of global reports and assessments, over the last two years, have shown that India has considerably improved its policies, practices and economic profile. These are reflected in Doing Business Report of the World Bank; World Investment Report 2016 of UNCTAD; Global Competitiveness Report of 2015-16 and 2016-17 of the World Economic Forum; and several other Reports. India has become the sixth largest manufacturing country in the world, up from ninth previously. We are seen as an engine of global growth.

10. In the last one year, our country has witnessed historic and impactful economic reforms and policy making. In fact, India was one of the very few economies undertaking transformational reforms. There were two tectonic policy initiatives, namely, passage of the Constitution Amendment Bill for GST and the progress for its implementation ; and demonetisation of high denomination bank notes. The advantages of GST for our economy in terms of spurring growth, competitiveness, indirect tax simplification and greater transparency have already been extensively discussed in both Houses of Parliament. I thank all Members of both the Houses for having passed the Constitution Amendment unanimously. I also thank the State Governments for resolving all relevant issues in the GST Council.

11. Demonetisation of high denomination bank notes was in continuation of a series of measures taken by our Government during the last two years. It is a bold and decisive measure. For several decades, tax evasion for many has become a way of life. This compromises the larger

public interest and creates unjust enrichment in favour of the tax evader, to the detriment of the poor and deprived. This has bred a parallel economy which is unacceptable for an inclusive society. Demonetisation seeks to create a new 'normal' wherein the GDP would be bigger, cleaner and real. This exercise is part of our Government's resolve to eliminate corruption, black money, counterfeit currency and terror funding. Like all reforms, this measure is obviously disruptive, as it seeks to change the retrograde status quo. Drop in economic activity, if any, on account of the currency squeeze during the remonetisation period is expected to have only a transient impact on the economy. I am reminded here of what the Father of the Nation, Mahatma Gandhi, had said: "A right cause never fails".

12. Demonetisation has strong potential to generate long-term benefits in terms of reduced corruption, greater digitisation of the economy, increased flow of financial savings and greater formalisation of the economy, all of which would eventually lead to higher GDP growth and tax revenues. Demonetisation helps to transfer resources from the tax evaders to the Government, which can use these resources for the welfare of the poor and the deprived. There is early evidence of an increased capacity of Banks to lend at reduced interest rates and a huge shift towards digitisation among all sections of society. We firmly believe that demonetisation and GST which were built on the third transformational achievement of our Government, namely, the JAM vision, will have an epoch making impact on our economy and the lives of our people.

13. **Madam Speaker,** we are at an important turning point in the path of our growth and development.

इस मोड़ पर घबरा के न थम जाइए आप
जो बात नयी है उसे अपनाइए आप
डरते हैं नयी राह पे क्यों चलने से
हम आगे-आगे चलते हैं आजाइए आप

14. The pace of remonetisation has picked up and will soon reach comfortable levels. The effects of demonetisation are not expected to spill over into the next year. Thus IMF, even while revising India's GDP forecast for 2016 downwards, has projected a GDP growth of 7.2% and 7.7% in 2017 and 2018 respectively. The World Bank, however, is more optimistic and has projected a GDP growth of 7% in 2016-17, 7.6% in 2017-18 and 7.8% in 2018-19. This pick up in our economy is premised upon our policy and determination to continue with economic reforms; increase in public investment in infrastructure and development projects; and export growth in the context of the expected rebound in world economy. The surplus liquidity in the banking system, created by demonetisation, will lower borrowing costs and increase the access to credit. This will boost economic activity, with multiplier effects.

15. The announcements made by Honourable Prime Minister on 31st December, 2016 address many of the key concerns of our economy at this juncture, such as, housing for the poor; relief to farmers; credit support to MSMEs; encouragement to digital transactions; assistance to pregnant women and senior citizens; and priority to dalits, tribals, backward classes and women under the Mudra Yojana.

16. My overall approach, while preparing this Budget, has been to spend more in rural areas, infrastructure and poverty alleviation and yet maintain the best standards of fiscal prudence. I have also kept in mind the need to continue with economic reforms, promote higher investments and accelerate growth.

17. The last one year was a witness to other major reforms, namely, enactment of the Insolvency and Bankruptcy Code; amendment to the RBI Act for inflation targeting; enactment of the *Aadhar* bill for disbursement of financial subsidies and benefits; significant reforms in FDI policy; the job creating package for textile sector; and several other measures. We will continue the process of economic reforms for the benefit of the poor and the underprivileged.

18. **Madam Speaker**, the Budget for 2017-18 contains three major reforms. First, the presentation of the Budget has been advanced to 1st February to enable the Parliament to avoid a Vote on Account and pass a single Appropriation Bill for 2017-18, before the close of the current financial year. This would enable the Ministries and Departments to operationalise all schemes and projects, including the new schemes, right from the commencement of the next financial year. They would be able to fully utilise the available working season before the onset of the monsoon. Second, the merger of the Railways Budget with the General Budget is a historic step. We have discontinued the colonial practice prevalent since 1924. This decision brings the Railways to the centre stage of Government's fiscal policy and would facilitate multi modal transport planning between railways, highways and inland waterways. The functional autonomy of Railways will, however, continue. Third, we have done away with the plan and non-plan classification of expenditure. This will give us a holistic view of allocations for sectors and ministries. This would facilitate optimal allocation of resources.

19. **Madam Speaker**, we are aware that we need to do more for our people. Continuing with the task of fulfilling the people's expectations, our agenda for the next year is : "Transform, Energise and Clean India", that is, TEC India. This agenda of TEC India seeks to

- Transform the quality of governance and quality of life of our people;
- Energise various sections of society, especially the youth and the vulnerable, and enable them to unleash their true potential; and
- Clean the country from the evils of corruption, black money and non-transparent political funding.

I propose to present my Budget proposals under ten distinct themes to foster this broad agenda. The themes are :

- (i) **Farmers** : for whom we have committed to double the income in 5 years;
- (ii) **Rural Population** : providing employment and basic infrastructure;
- (iii) **Youth** : energising them through education, skills and jobs;
- (iv) **Poor and the Underprivileged** : strengthening the systems of social security, health care and affordable housing;
- (v) **Infrastructure** : for efficiency, productivity and quality of life;
- (vi) **Financial Sector** : growth and stability through stronger institutions;
- (vii) **Digital Economy** : for speed, accountability and transparency;
- (viii) **Public Service** : effective governance and efficient service delivery through people's participation;
- (ix) **Prudent Fiscal Management** : to ensure optimal deployment of resources and preserve fiscal stability; and
- (x) **Tax Administration** : honouring the honest.

I. FARMERS

20. The Indian farmer has once again shown his commitment and resilience in the current year. The total area sown under kharif and rabi seasons are higher than the previous year. With a better monsoon, agriculture is expected to grow at 4.1% in the current year.

21. In last year's Budget speech, I focused on 'income security' of farmers to double their income in 5 years. I had also announced a number of measures. We have to take more steps and enable the farmers to increase their production and productivity; and to deal with post-harvest challenges.

22. For a good crop, adequate credit should be available to farmers in time. The target for agricultural credit in 2017-18 has been fixed at a record level of ₹ 10 lakh crores. We will take special efforts to ensure adequate flow of credit to the under serviced areas, the Eastern States and Jammu & Kashmir. The farmers will also benefit from 60 days' interest waiver announced by Honourable Prime Minister in respect of their loans from the cooperative credit structure.

23. About 40% of the small and marginal farmers avail credit from the cooperative structure. The Primary Agriculture Credit Societies (PACS) act as the front end for loan disbursements. We will support NABARD for computerisation and integration of all 63,000 functional PACS with the Core Banking System of District Central Cooperative Banks. This will be done in 3 years at an estimated cost of ₹ 1,900 crores, with financial participation from State Governments. This will ensure seamless flow of credit to small and marginal farmers.

24. At the time of sowing, farmers should feel secure against natural calamities. The *Fasal Bima Yojana* launched by our Government is a major step in this direction. The coverage of this scheme will be increased from 30% of cropped area in 2016-17 to 40% in 2017-18 and 50% in 2018-19. The Budget provision of ₹ 5,500 crores for this Yojana in BE 2016-17 was increased to ₹ 13,240 crores in RE 2016-17 to settle the arrear claims. For 2017-18, I have provided a sum of ₹9,000 crores. The sum insured under this Yojana has more than doubled from ₹ 69,000 crores in Kharif 2015 to ₹ 1,41,625 crores in Kharif 2016.

25. Issuance of Soil Health Cards has gathered momentum. The real benefit to farmers would be available only when the soil samples are tested quickly and nutrient level of the soil is known. Government will therefore set up new mini labs in *Krishi Vigyan Kendras* (KVKs) and ensure 100% coverage of all 648 KVKs in the country. In addition, 1000 mini labs will be set up by qualified local entrepreneurs. Government will provide credit linked subsidy to these entrepreneurs.

26. A Long Term Irrigation Fund has already been set up in NABARD. Honourable Prime Minister has announced an addition of ₹ 20,000 crores to its corpus. This will take the total corpus of this Fund to ₹ 40,000 crores.

27. A dedicated Micro Irrigation Fund will be set up in NABARD to achieve the goal, 'per drop more crop'. The Fund will have an initial corpus of ₹5,000 crores.

28. For the post-harvest phase, we will take steps to enable farmers to get better prices for their produce in the markets. The coverage of National Agricultural Market (e-NAM) will be expanded from the current 250 markets to 585 APMCs. Assistance up to a ceiling of ₹ 75 lakhs will be provided to every e-NAM market for establishment of cleaning, grading and packaging facilities. This will lead to value addition of farmers' produce.

29. Market reforms will be undertaken and the States would be urged to denotify perishables from APMC. This will give opportunity to farmers to sell their produce and get better prices.

30. We also propose to integrate farmers who grow fruits and vegetables with agro processing units for better price realisation and reduction of post-harvest losses. A model law on contract farming would therefore be prepared and circulated among the States for adoption.

31. Dairy is an important source of additional income for the farmers. Availability of milk processing facility and other infrastructure will benefit the farmers through value addition. A large number of milk processing units set up under the Operation Flood Programme has since become old and obsolete. A Dairy Processing and Infrastructure Development Fund would be set up in NABARD with a corpus of ₹ 8,000 crores over 3 years. Initially, the Fund will start with a corpus of ₹ 2,000 crores.

II. RURAL POPULATION

32. I now turn to the Rural Sector, which was so dear to the heart of Mahatma Gandhi.

33. Over ₹ 3 lakh crores are spent in rural areas every year, if we add up all the programmes meant for rural poor from the Central Budget, State Budgets, Bank linkage for self-help groups, etc. With a clear focus on improving accountability, outcomes and convergence, we will undertake a Mission Antyodaya to bring one crore households out of poverty and to make 50,000 gram panchayats poverty free by 2019, the 150th birth anniversary of Gandhiji. We will utilise the existing resources more effectively along with annual increases. This mission will work with a focused micro plan for sustainable livelihood for every deprived household. A composite index for poverty free gram panchayats would be developed to monitor the progress from the baseline.

34. Our Government has made a conscious effort to reorient MGNREGA to support our resolve to double farmers' income. While providing at least 100 days employment to every rural household, MGNREGA should create productive assets to improve farm productivity and incomes. The target of 5 lakh farm ponds and 10 lakh compost pits announced in the last Budget from MGNREGA funds will be fully achieved. In fact, against 5 lakh farm ponds, it is expected that about 10 lakh farm ponds would be completed by March 2017. During 2017-18, another 5 lakh farm ponds will be taken up. This single measure will contribute greatly to drought proofing of gram panchayats.

35. Participation of women in MGNREGA has increased to 55% from less than 48% in the past.

36. Honourable Members would be happy to note that the budget provision of ₹38,500 crores under MGNREGA in 2016-17 has been increased to ₹48,000 crores in 2017-18. This is the highest ever allocation for MGNREGA. The initiative to geo-tag all MGNREGA assets and putting them in public domain has established greater transparency. We are also using space technology in a big way to plan MGNREGA works.

37. The *Pradhan Mantri Gram Sadak Yojana* (PMGSY) is now being implemented as never before. The pace of construction of PMGSY roads has accelerated to reach 133 km roads per day in 2016-17, as against an average of 73 km during the period 2011-2014. We have also taken up the task of connecting habitations with more than 100 persons in left wing extremism affected Blocks. We have committed to complete the current target under PMGSY by 2019. I have provided a sum of ₹ 19,000 crores in 2017-18 for this scheme. Together with the contribution of States, an amount of ₹ 27,000 crores will be spent on PMGSY in 2017-18.

38. We propose to complete 1 crore houses by 2019 for the houseless and those living in kutchha houses. I have stepped up the allocation for Pradhan Mantri Awaas Yojana – Gramin from ₹ 15,000 crores in BE 2016-17 to ₹23,000 crores in 2017-18.

39. We are well on our way to achieving 100% village electrification by 1st May 2018. An increased allocation of ₹4,814 crores has been proposed under the Deendayal Upadhyaya Gram Jyoti Yojana in 2017-18.

40. I have also proposed to increase the allocations for Deendayal Antyodaya Yojana-National Rural Livelihood Mission for promotion of skill development and livelihood opportunities for people in rural areas to ₹4,500 in 2017-18. The allocation for Prime Minister's Employment Generation Programme (PMEGP) and credit support schemes has been increased more than 3 times.

41. Swachh Bharat Mission (Gramin) has made tremendous progress in promoting safe sanitation and ending open defecation. Sanitation coverage in rural India has gone up from 42% in October 2014 to about 60%. Open Defecation Free villages are now being given priority for piped water supply.

42. We propose to provide safe drinking water to over 28,000 arsenic and fluoride affected habitations in the next four years. This will be a sub mission of the National Rural Drinking Water Programme (NRDWP).

43. For imparting new skills to the people in the rural areas, mason training will be provided to 5 lakh persons by 2022, with an immediate target of training at least 20,000 persons by 2017-18.

44. Panchayati raj institutions still lack human resources for implementing development programmes. A programme of "human resource reforms for results" will be launched during 2017-18 for this purpose.

45. The Government will continue to work closely with the farmers and the people in the rural areas to improve their life and environment. This is a non-negotiable agenda for our Government. The total allocation for the rural, agriculture and allied sectors in 2017-18 is ₹ 1,87,223 crores, which is 24% higher than the previous year.

III. YOUTH

46. Let me now focus on my proposals for the youth.

47. Quality education will energise our youth. In the words of Swami Vivekananda, "The education which does not help the common mass of people to equip themselves for the struggle for life is it worth the name?"

48. We have proposed to introduce a system of measuring annual learning outcomes in our schools. Emphasis will be given on science education and flexibility in curriculum to promote creativity through local innovative content.

49. An Innovation Fund for Secondary Education will be created to encourage local innovation for ensuring universal access, gender parity and quality improvement. This will include ICT enabled learning transformation. The focus will be on 3479 educationally backward blocks.

50. In higher education, we will undertake reforms in the UGC. Good quality institutions would be enabled to have greater administrative and academic autonomy. Colleges will be identified based on accreditation and ranking, and given autonomous status. A revised framework will be put in place for outcome based accreditation and credit based programmes.

51. We propose to leverage information technology and launch SWAYAM platform with at least 350 online courses. This would enable students to virtually attend the courses taught by the best faculty; access high quality reading resources; participate in discussion forums; take tests and

earn academic grades. Access to SWAYAM would be widened by linkage with DTH channels, dedicated to education.

52. We propose to establish a National Testing Agency as an autonomous and self-sustained premier testing organisation to conduct all entrance examinations for higher education institutions. This would free CBSE, AICTE and other premier institutions from these administrative responsibilities so that they can focus more on academics.

53. We have a huge demographic advantage. Skill India mission was launched in July 2015 to maximise the potential of our youth.

54. *Pradhan Mantri Kaushal Kendras* (PMKK) have already been promoted in more than 60 districts. We now propose to extend these *Kendras* to more than 600 districts across the country. 100 India International Skills Centres will be established across the country. These Centres would offer advanced training and also courses in foreign languages. This will help those of our youth who seek job opportunities outside the country.

55. In 2017-18, we also propose to launch the Skill Acquisition and Knowledge Awareness for Livelihood Promotion programme (SANKALP) at a cost of ₹ 4,000 crores. SANKALP will provide market relevant training to 3.5 crore youth.

56. The next phase of Skill Strengthening for Industrial Value Enhancement (STRIVE) will also be launched in 2017-18 at a cost of ₹ 2,200 crores. STRIVE will focus on improving the quality and market relevance of vocational training provided in ITIs and strengthen the apprenticeship programmes through industry cluster approach.

57. A special scheme for creating employment in the textile sector has already been launched. A similar scheme will be implemented for the leather and footwear industries.

58. Tourism is a big employment generator and has a multiplier impact on the economy. Five Special Tourism Zones, anchored on SPVs, will be set up in partnership with the States. Incredible India 2.0 Campaign will be launched across the world.

IV. THE POOR AND THE UNDERPRIVILEGED

59. Madam Speaker, I now turn to my proposals for the poor and the underprivileged.

60. *Sabka Saath Sabka Vikas* begins with the girl child and women. *Mahila Shakti Kendra* will be set up at village level with an allocation of ₹ 500 crores in 14 lakh ICDS *Anganwadi* Centres. This will provide one stop convergent support services for empowering rural women with opportunities for skill development, employment, digital literacy, health and nutrition. A nationwide scheme for financial assistance to pregnant women has already been announced by Honourable Prime Minister on 31st December, 2016. Under this scheme, ₹ 6,000 each will be transferred directly to the bank accounts of pregnant women who undergo institutional delivery and vaccinate their children.

61. For the welfare of Women and Children under various schemes across all Ministries, I have stepped up the allocation from ₹1,56,528 crores in BE 2016-17 to ₹1,84,632 crores in 2017-18.

62. We propose to facilitate higher investment in affordable housing. Affordable housing will now be given infrastructure status, which will enable these projects to avail the associated benefits.

63. The National Housing Bank will refinance individual housing loans of about ₹20,000 crore in 2017-18. Thanks to the surplus liquidity created by demonetisation, the Banks have already

started reducing their lending rates, including those for housing. In addition, interest subvention for housing loans has also been announced by the Honourable Prime Minister.

64. Poverty is usually associated with poor health. It is the poor who suffer the maximum from various chronic diseases. Government has therefore prepared an action plan to eliminate Kala-Azar and Filariasis by 2017, Leprosy by 2018 and Measles by 2020. Elimination of tuberculosis by 2025 is also targeted. Similarly, action plan has been prepared to reduce IMR from 39 in 2014 to 28 by 2019 and MMR from 167 in 2011-13 to 100 by 2018-2020. 1.5 lakh Health Sub Centres will be transformed into Health and Wellness Centres.

65. We need to ensure adequate availability of specialist doctors to strengthen Secondary and Tertiary levels of health care. We have therefore decided to take steps to create additional 5,000 Post Graduate seats per annum. In addition, steps will be taken to roll out DNB courses in big District Hospitals; strengthen PG teaching in select ESI and Municipal Corporation Hospitals; and encourage reputed Private Hospitals to start DNB courses. We will work with the State Governments to take these tasks forward. The Government is committed to take necessary steps for structural transformation of the Regulatory framework of Medical Education and Practice in India.

66. Two new All India Institutes of Medical Sciences will be set up in the States of Jharkhand and Gujarat.

67. We propose to amend the Drugs and Cosmetics Rules to ensure availability of drugs at reasonable prices and promote use of generic medicines. New rules for regulating medical devices will also be formulated. These rules will be internationally harmonised and attract investment into this sector. This will reduce the cost of such devices.

68. We are keen on fostering a conducive labour environment wherein labour rights are protected and harmonious labour relations lead to higher productivity. Legislative reforms will be undertaken to simplify, rationalise and amalgamate the existing labour laws into 4 Codes on (i) wages; (ii) industrial relations; (iii) social security and welfare; and (iv) safety and working conditions. The Model Shops and Establishment Bill 2016 has been circulated to all States for consideration and adoption. This would open up additional avenues for employment of women. The amendment made to the Payment of Wages Act, is another initiative of our Government for the benefit of the labour and ease of doing business.

69. Our Government is giving special importance to implementation of the schemes for welfare of Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Minorities. The allocation for the welfare of Scheduled Castes has been stepped up from ₹38,833 crores in BE 2016-17 to ₹52,393 crores in 2017-18, representing an increase of about 35%. The allocation for Scheduled Tribes has been increased to ₹31,920 crores and for Minority Affairs to ₹4,195 crores. The Government will introduce outcome based monitoring of expenditure in these sectors by the NITI Aayog.

70. For senior citizens, *Aadhar* based Smart Cards containing their health details will be introduced. A beginning will be made through a pilot in 15 districts during 2017-18. The LIC will implement a scheme for senior citizens to provide assured pension, with a guaranteed return of 8% per annum for 10 years.

V. INFRASTRUCTURE

71. The fifth component of TEC India agenda is Infrastructure.

72. Railways, roads and rivers are the lifeline of our country. I feel privileged to present the first combined Budget of independent India that includes the Railways also. We are now in a

position to synergise the investments in railways, roads, waterways and civil aviation. For 2017-18, the total capital and development expenditure of Railways has been pegged at ₹1,31,000 crores. This includes ₹55,000 crores provided by the Government.

73. Among other things, the Railways will focus on four major areas, namely :

- (i) Passenger safety;
- (ii) Capital and development works;
- (iii) Cleanliness; and
- (iv) Finance and accounting reforms.

74. For passenger safety, a *Rashtriya Rail Sanraksha Kosh* will be created with a corpus of ₹1 lakh crores over a period of 5 years. Besides seed capital from the Government, the Railways will arrange the balance resources from their own revenues and other sources. Government will lay down clear cut guidelines and timeline for implementing various safety works to be funded from this *Kosh*. Unmanned level crossings on Broad Gauge lines will be eliminated by 2020. Expert international assistance will be harnessed to improve safety preparedness and maintenance practices.

75. In the next 3 years, the throughput is proposed to be enhanced by 10%. This will be done through modernisation and upgradation of identified corridors. Railway lines of 3,500 kms will be commissioned in 2017-18, as against 2,800 kms in 2016-17. Steps will be taken to launch dedicated trains for tourism and pilgrimage.

76. Railways have set up joint ventures with 9 State Governments. 70 projects have been identified for construction and development.

77. A beginning has been made with regard to station redevelopment. At least 25 stations are expected to be awarded during 2017-18 for station redevelopment. 500 stations will be made differently abled friendly by providing lifts and escalators.

78. It is proposed to feed about 7,000 stations with solar power in the medium term. A beginning has already been made in 300 stations. Works will be taken up for 2,000 railway stations as part of 1000 MW solar mission.

79. Our focus is on swachh rail. SMS based *Clean My Coach Service* has been started. It is now proposed to introduce 'Coach Mitra' facility, a single window interface, to register all coach related complaints and requirements. By 2019, all coaches of Indian Railways will be fitted with bio toilets. Pilot plants for environment friendly disposal of solid waste and conversion of biodegradable waste to energy are being set up at New Delhi and Jaipur railway stations. Five more such solid waste management plants are now being taken up.

80. Today Indian Railways face stiff competition from other modes of transportation which are dominated by the private sector. Transformative measures have to be undertaken to make Indian Railways competitive to retain their position of pre-eminence. The following steps will therefore be taken :

- (i) Railways will implement end to end integrated transport solutions for select commodities through partnership with logistics players, who would provide both front and back end connectivity. Rolling stocks and practices will be customised to transport perishable goods, especially agricultural products.

- (ii) Railways will offer competitive ticket booking facility to the public at large. Service charge on e-tickets booked through IRCTC has been withdrawn. Cashless reservations have gone up from 58% to 68%.
- (iii) As part of accounting reforms, accrual based financial statements will be rolled out by March 2019.

81. It will be our continuous endeavour to improve the Operating Ratio of the Railways. The tariffs of Railways would be fixed, taking into consideration costs, quality of service, social obligations and competition from other forms of transport.

82. Metro rail is emerging as an important mode of urban transportation. A new Metro Rail Policy will be announced with focus on innovative models of implementation and financing, as well as standardisation and indigenisation of hardware and software. This will open up new job opportunities for our youth.

83. A new Metro Rail Act will be enacted by rationalising the existing laws. This will facilitate greater private participation and investment in construction and operation.

84. In the road sector, I have stepped up the Budget allocation for highways from ₹57,976 crores in BE 2016-17 to ₹64,900 crores in 2017-18. 2,000 kms of coastal connectivity roads have been identified for construction and development. This will facilitate better connectivity with ports and remote villages. The total length of roads, including those under PMGSY, built from 2014-15 till the current year is about 1,40,000 kms which is significantly higher than previous three years.

85. An effective multi modal logistics and transport sector will make our economy more competitive. A specific programme for development of multi-modal logistics parks, together with multi modal transport facilities, will be drawn up and implemented.

86. Select airports in Tier 2 cities will be taken up for operation and maintenance in the PPP mode. Airport Authority of India Act will be amended to enable effective monetisation of land assets. The resources, so raised, will be utilised for airport upgradation.

87. For transportation sector as a whole, including rail, roads, shipping, I have provided ₹2,41,387 crores in 2017-18. This magnitude of investment will spur a huge amount of economic activity across the country and create more job opportunities.

88. Telecom sector is an important component of our infrastructure eco system. The recent spectrum auctions have removed spectrum scarcity in the country. This will give a major fillip to mobile broadband and Digital India for the benefit of people living in rural and remote areas.

89. Under the Bharat Net Project, OFC has been laid in 1,55,000 kms. I have stepped up the allocation for BharatNet Project to ₹10,000 crores in 2017-18. By the end of 2017-18, high speed broadband connectivity on optical fibre will be available in more than 1,50,000 *gram panchayats*, with wifi hot spots and access to digital services at low tariffs. A DigiGaon initiative will be launched to provide tele-medicine, education and skills through digital technology.

90. For strengthening our Energy sector, Government has decided to set up Strategic Crude Oil Reserves. In the first phase, 3 such Reserves facilities have been set up. Now in the second phase, it is proposed to set up caverns at 2 more locations, namely, Chandikhole in Odisha and Bikaner in Rajasthan. This will take our strategic reserve capacity to 15.33 MMT.

91. In solar energy, we now propose to take up the second phase of Solar Park development for additional 20,000 MW capacity.

92. We are also creating an eco-system to make India a global hub for electronics manufacturing. Over 250 investment proposals for electronics manufacturing have been received in the last 2 years, totalling an investment of ₹1.26 lakh crores. A number of global leaders and mobile manufacturers have set up production facilities in India. I have therefore exponentially increased the allocation for incentive schemes like M-SIPS and EDF to ₹745 crores in 2017-18. This is an all-time high.

93. We have to focus on our export infrastructure in a competitive world. A new and restructured Central scheme, namely, Trade Infrastructure for Export Scheme (TIES) will be launched in 2017-18.

94. The total allocation for infrastructure development in 2017-18 stands at ₹3,96,135 crores.

VI. FINANCIAL SECTOR

95. I now turn to the Financial Sector. The focus of TEC India agenda in this sector is on building stable and stronger institutions. We will continue with our reform agenda with several new measures.

96. Our Government has already undertaken substantive reforms in FDI policy in the last two years. More than 90% of the total FDI inflows are now through the automatic route. The Foreign Investment Promotion Board (FIPB) has successfully implemented e-filing and online processing of FDI applications. We have now reached a stage where FIPB can be phased out. We have therefore decided to abolish the FIPB in 2017-18. A roadmap for the same will be announced in the next few months. In the meantime, further liberalisation of FDI policy is under consideration and necessary announcements will be made in due course.

97. The Commodities markets require further reforms for the benefits of farmers. An expert committee will be constituted to study and promote creation of an operational and legal framework to integrate spot market and derivatives market for commodities trading. e-NAM would be an integral part of such framework.

98. The draft bill to curtail the menace of illicit deposit schemes has been placed in the public domain and will be introduced shortly after its finalisation. There is an urgent need to protect the poor and gullible investors from another set of dubious schemes, operated by unscrupulous entities who exploit the regulatory gaps in the Multi State Cooperative Societies Act, 2002. We will amend this Act in consultation with various stakeholders, as part of our 'Clean India' agenda.

99. The bill relating to resolution of financial firms will be introduced in the current Budget Session of Parliament. This will contribute to stability and resilience of our financial system. It will also protect the consumers of various financial institutions. Together with the Insolvency and Bankruptcy Code, a resolution mechanism for financial firms will ensure comprehensiveness of the resolution system in our country.

100. I had stated in my last Budget speech that a Bill will be introduced to streamline institutional arrangements for resolution of disputes in infrastructure related construction contracts, PPP and public utility contracts. After extensive stakeholders' consultations, we have decided that the required mechanism would be instituted as part of the Arbitration and Conciliation Act 1996. An amendment Bill will be introduced in this regard.

101. Cyber security is critical for safeguarding the integrity and stability of our financial sector. A Computer Emergency Response Team for our Financial Sector (CERT-Fin) will be established. This entity will work in close coordination with all financial sector regulators and other stakeholders.

102. I have also proposed several other measures in the financial sector which are listed in **Annex I.**

103. Listing of Public Sector enterprises will foster greater public accountability and unlock the true value of these companies. The Government will put in place a revised mechanism and procedure to ensure time bound listing of identified CPSEs on stock exchanges. The disinvestment policy announced by me in the last budget will continue.

104. The shares of Railway PSEs like IRCTC, IRFC and IRCON will be listed in stock exchanges.

105. We see opportunities to strengthen our CPSEs through consolidation, mergers and acquisitions. By these methods, the CPSEs can be integrated across the value chain of an industry. It will give them capacity to bear higher risks, avail economies of scale, take higher investment decisions and create more value for the stakeholders. Possibilities of such restructuring are visible in the oil and gas sector. We propose to create an integrated public sector 'oil major' which will be able to match the performance of international and domestic private sector oil and gas companies.

106. Our ETF, comprising shares of ten CPSEs, has received overwhelming response in the recent Further Fund Offering (FFO). We will continue to use ETF as a vehicle for further disinvestment of shares. Accordingly, a new ETF with diversified CPSE stocks and other Government holdings will be launched in 2017-18.

107. The focus on resolution of stressed legacy accounts of Banks continues. The legal framework has been strengthened to facilitate resolution, through the enactment of the Insolvency and Bankruptcy Code and the amendments to the SARFAESI and Debt Recovery Tribunal Acts. In line with the '*Indradhanush*' roadmap, I have provided ₹10,000 crores for recapitalisation of Banks in 2017-18. Additional allocation will be provided, as may be required.

108. Listing and trading of Security Receipts issued by a securitization company or a reconstruction company under the SARFAESI Act will be permitted in SEBI registered stock exchanges. This will enhance capital flows into the securitization industry and will particularly be helpful to deal with bank NPAs.

109. The *Pradhan Mantri Mudra Yojana* has contributed significantly to funding the unfunded and the underfunded. Last year, the target of ₹1.22 lakh crores was exceeded. For 2017-18, I propose to double the lending target of 2015-16 and set it at ₹2.44 lakh crores. Priority will be given to Dalits, Tribals, Backward Classes, Minorities and Women.

110. The Stand Up India scheme was launched by our Government in April 2016 to support Dalit, Tribal and Women entrepreneurs to set up greenfield enterprises and become job creators. Over 16,000 new enterprises have come up through this scheme in activities, as diverse as food processing, garments, diagnostic centres, etc.

VII. DIGITAL ECONOMY

111. Promotion of a digital economy is an integral part of Government's strategy to clean the system and weed out corruption and black money. It has a transformative impact in terms of greater formalisation of the economy and mainstreaming of financial savings into the banking system. This, in turn, is expected to energise private investment in the country through lower cost of credit. India is now on the cusp of a massive digital revolution.

112. A shift to digital payments has huge benefits for the common man. The earlier initiative of our Government to promote financial inclusion and the JAM trinity were important precursors to our current push for digital transactions.

113. Already there is evidence of increased digital transactions. The BHIM app has been launched. It will unleash the power of mobile phones for digital payments and financial inclusion. 125 lakh people have adopted the BHIM app so far. The Government will launch two new schemes to promote the usage of BHIM; these are, Referral Bonus Scheme for individuals and a Cashback Scheme for merchants.

114. Aadhar Pay, a merchant version of Aadhar Enabled Payment System, will be launched shortly. This will be specifically beneficial for those who do not have debit cards, mobile wallets and mobile phones. A Mission will be set up with a target of 2,500 crore digital transactions for 2017-18 through UPI, USSD, Aadhar Pay, IMPS and debit cards. Banks have targeted to introduce additional 10 lakh new PoS terminals by March 2017. They will be encouraged to introduce 20 lakh Aadhar based PoS by September 2017.

115. Increased digital transactions will enable small and micro enterprises to access formal credit. Government will encourage SIDBI to refinance credit institutions which provide unsecured loans, at reasonable interest rates, to borrowers based on their transaction history.

116. The digital payment infrastructure and grievance handling mechanisms shall be strengthened. The focus would be on rural and semi urban areas through Post Offices, Fair Price Shops and Banking Correspondents. Steps would be taken to promote and possibly mandate petrol pumps, fertilizer depots, municipalities, Block offices, road transport offices, universities, colleges, hospitals and other institutions to have facilities for digital payments, including BHIM App. A proposal to mandate all Government receipts through digital means, beyond a prescribed limit, is under consideration.

117. Government will strengthen the Financial Inclusion Fund to augment resources for taking up these initiatives.

118. Government will consider and work with various stakeholders for early implementation of the interim recommendations of the Committee of Chief Ministers on digital transactions.

119. The Committee on Digital Payments constituted by Department of Economic Affairs has recommended structural reforms in the payment eco system, including amendments to the Payment and Settlement Systems Act, 2007. Government will undertake a comprehensive review of this Act and bring about appropriate amendments. To begin with, it is proposed to create a Payments Regulatory Board in the Reserve Bank of India by replacing the existing Board for Regulation and Supervision of Payment and Settlement Systems. Necessary amendments are proposed to this effect in the Finance Bill 2017.

120. As we move faster on the path of digital transactions and cheque payments, we need to ensure that the payees of dishonoured cheques are able to realise the payments. Government is therefore considering the option of amending the Negotiable Instruments Act suitably.

VIII. PUBLIC SERVICE

121. I now turn to Public Service. Our focus here is on effective government and efficient service delivery.

122. We have made a strong beginning with regard to Direct Benefit Transfer (DBT) to LPG and kerosene consumers. Chandigarh and eight districts of Haryana have become kerosene free. 84 Government schemes have also boarded on the DBT platform.

123. The Government e-market place which is now functional for procurement of goods and services, has been selected as one of the winners of the South Asia Procurement Innovation Awards of the World Bank.

124. Our citizens in far flung regions of the country find it difficult to obtain passports and redress passport related grievances. We have decided to utilise the Head Post Offices as front offices for rendering passport services.

125. Our defence forces keep the country safe from both external and internal threats. A Centralised Defence Travel System has now been developed through which travel tickets can be booked online by our soldiers and officers. They do not have to face the hassle of standing in queues with railway warrants.

126. A comprehensive web based interactive Pension Disbursement System for Defence Pensioners will be established. This system will receive pension proposals and make payments centrally. This will reduce the grievances of defence pensioners.

127. At present our citizens, especially those belonging to the poor and unprivileged sections, go through cumbersome procedures of Government recruitment. There are multiplicity of agencies and examinations. We propose to introduce a system of single registration and two tier system of examination.

128. Over the years, the number of tribunals have multiplied with overlapping functions. We propose to rationalise the number of tribunals and merge tribunals wherever appropriate.

129. In the recent past, there have been instances of big time offenders, including economic offenders, fleeing the country to escape the reach of law. We have to ensure that the law is allowed to take its own course. Government is therefore considering introduction of legislative changes, or even a new law, to confiscate the assets of such persons located within the country, till they submit to the jurisdiction of the appropriate legal forum. Needless to say that all necessary constitutional safeguards will be followed in such cases.

130. Our Government will continue to remain committed to improve the standards of public service and transparent governance. Service to the people was the life-long commitment of the Father of the Nation, Mahatma Gandhi. As we approach, the 150th Birth Anniversary of the Mahatma, we will take all steps to celebrate it in a befitting manner. A High Level Committee under the Chairmanship of Honourable Prime Minister is proposed to be set up for the same. We will also commemorate the centenary year of *Champaran Satyagrah* this year. Government of India will support Government of Gujarat to commemorate 100 years of Sabarmati Ashram in 2017, in a befitting manner. 200 years ago in 1817, a valiant uprising of soldiers led by Buxi Jagabandhu took place in Khordha of Odisha. We will commemorate the same appropriately.

IX. PRUDENT FISCAL MANAGEMENT

131. I now turn to the fiscal situation in the context of the Budget for 2017-18.

132. The total expenditure in Budget for 2017-18 has been placed at ₹21.47 lakh crores. With the abolition of Plan-Non Plan classification of expenditure, the focus is now on Revenue and Capital expenditure. I have stepped up the allocation for Capital expenditure by 25.4% over the

previous year. This will have multiplier effects and lead to higher growth. The total resources being transferred to the States and the Union Territories with Legislatures is ₹4.11 lakh crores, against ₹3.60 lakh crores in BE 2016-17. Details of allocations for important sectors and schemes and transfer of resources to States are given in **Annex II** of my Speech.

133. I have made a provision of ₹3,000 crores under the Department of Economic Affairs to implement various Budget announcements and other new schemes in 2017-18. For Defence expenditure excluding pensions, I have provided a sum of ₹2,74,114 crores including ₹86,488 crores for Defence capital. I have increased the allocation for Scientific Ministries to ₹37,435 crore in 2017-18.

134. For the first time, a consolidated Outcome Budget, covering all Ministries and Departments, is being laid along with the other Budget documents. This will improve accountability of Government expenditure.

135. The FRBM Review Committee has given its report recently. The Committee has done an elaborate exercise and has recommended that a sustainable debt path must be the principal macro-economic anchor of our fiscal policy. The Committee has favoured Debt to GDP of 60% for the General Government by 2023, consisting of 40% for Central Government and 20% for State Governments. Within this framework, the Committee has derived and recommended 3% fiscal deficit for the next three years. The Committee has also provided for 'Escape Clauses', for deviations upto 0.5% of GDP, from the stipulated fiscal deficit target. Among the triggers for taking recourse to these Escape Clauses, the Committee has included "far-reaching structural reforms in the economy with unanticipated fiscal implications" as one of the factors. Although there is a strong case now to invoke this Escape Clause, I am refraining from doing so. The Report of the Committee will be carefully examined and appropriate decisions taken in due course.

136. Nevertheless, I take note of the fiscal deficit roadmap of 3% recommended by the Committee for the next three years. I have taken into consideration the need for higher public expenditure in the context of sluggish private sector investment and slow global growth. I have kept in mind the recommendation of the Committee that a sustainable debt should be the underlying basis of prudent fiscal management. Considering all these aspects, I have pegged the fiscal deficit for 2017-18 at 3.2% of GDP and remain committed to achieve 3% in the following year. With this gradual approach, I have ensured adherence to fiscal consolidation, without compromising the requirements of public investment.

137. I have taken due care to limit the net market borrowing of Government to ₹3.48 lakh crores after buyback, much lower than ₹4.25 lakh crores of the previous year. More importantly, the Revenue Deficit of 2.3% in BE 2016-17 stands reduced to 2.1% in the Revised Estimates. The Revenue Deficit for next year is pegged at 1.9% , against 2% mandated by the FRBM Act.

138. It will be our endeavour to improve upon these fiscal numbers, especially the fiscal deficit, in the next year, through greater focus on quality of expenditure and higher tax realisation from the huge cash deposits in Banks, triggered by demonetisation.

PART B

Madam Speaker,

139. I shall now present my tax proposals:

140. India's tax to GDP ratio is very low, and the proportion of direct tax to indirect tax is not optimal from the view point of social justice. I place before you certain data to indicate that our direct tax collection is not commensurate with the income and consumption pattern of Indian economy. As against estimated 4.2 crore persons engaged in organised sector employment, the number of individuals filing return for salary income are only 1.74 crore. As against 5.6 crore informal sector individual enterprises and firms doing small business in India, the number of returns filed by this category are only 1.81 crore. Out of the 13.94 lakh companies registered in India upto 31st March, 2014, 5.97 lakh companies have filed their returns for Assessment Year 2016-17. Of the 5.97 lakh companies which have filed their returns for Assessment Year 2016-17 so far, as many as 2.76 lakh companies have shown losses or zero income. 2.85 lakh companies have shown profit before tax of less than ₹ 1 crore. 28,667 companies have shown profit between ₹ 1 crore to ₹ 10 crore, and only 7781 companies have profit before tax of more than ₹ 10 crores.

141. Among the 3.7 crore individuals who filed the tax returns in 2015-16, 99 lakh show income below the exemption limit of ₹ 2.5 lakh p.a., 1.95 crore show income between ₹ 2.5 to ₹ 5 lakh, 52 lakh show income between ₹ 5 to ₹ 10 lakhs and only 24 lakh people show income above ₹ 10 lakhs. Of the 76 lakh individual assesses who declare income above ₹ 5 lakh, 56 lakh are in the salaried class. The number of people showing income more than ₹ 50 lakh in the entire country is only 1.72 lakh. We can contrast this with the fact that in the last five years, more than 1.25 crore cars have been sold, and number of Indian citizens who flew abroad, either for business or tourism, is 2 crore in the year 2015. From all these figures we can conclude that we are largely a tax non-compliant society. The predominance of cash in the economy makes it possible for the people to evade their taxes. When too many people evade taxes, the burden of their share falls on those who are honest and compliant.

142. After the demonetisation, the preliminary analysis of data received in respect of deposits made by people in old currency presents a revealing picture. During the period 8th November to 30th December 2016, deposits between ₹ 2 lakh and ₹ 80 lakh were made in about 1.09 crore accounts with an average deposit size of ₹ 5.03 lakh. Deposits of more than 80 lakh were made in 1.48 lakh accounts with average deposit size of ₹ 3.31 crores. This data mining will help us immensely in expanding the tax net as well as increasing the revenues, which was one of the objectives of demonetisation.

143. Madam Speaker, one of the main priorities of our Government is to eliminate the black money component from the economy. We are committed to make our taxation rates more reasonable, our tax administration more fair and expand the tax base in the country. This approach will change the colour of money.

नई दुनिया है, नया दौर है, नयी है उमंग
कुछ थे पहले के तरीके, तो हैं कुछ आज के ढंग
रोशनी आके अंधेरों से जो टकरायी है
काले धन को भी बदलना पड़ा, आज अपना रंग

144. The net tax revenue of 2013-14 was ₹ 11.38 lakh crores. This grew by 9.4% in 2014-15 and 17% in 2015-16. As per the RE of 2016-17, we will end the year with a high growth rate of 17% for the second year in a row. Because of the serious efforts made by the Government, the rate of growth of advance tax in personal income tax in the first three quarters of the current financial is 34.8%.

145. Madam Speaker, the thrust of my tax proposals in this Budget is stimulating growth, relief to middle class, affordable housing, curbing black money, promoting digital economy, transparency of political funding and simplification of tax administration.

Measures for Promoting Affordable Housing and Real Estate Sector

146. In my budget proposals last year, I had announced a scheme for profit-linked income tax exemption for promoters of affordable housing scheme which has received a very good response. However, in order to make this scheme more attractive, I propose certain changes in the scheme. First of all, instead of built up area of 30 and 60 sq.mtr., the carpet area of 30 and 60 sq.mtr. will be counted. Also the 30 sq.mtr. limit will apply only in case of municipal limits of 4 metropolitan cities while for the rest of the country including in the peripheral areas of metros, limit of 60 sq.mtr. will apply. In order to be eligible, the scheme was to be completed in 3 years after commencement. I propose to extend this period to 5 years.

147. At present, the houses which are unoccupied after getting completion certificates are subjected to tax on notional rental income. For builders for whom constructed buildings are stock-in-trade, I propose to apply this rule only after one year of the end of the year in which completion certificate is received so that they get some breathing time for liquidating their inventory.

148. We also propose to make a number of changes in the capital gain taxation provisions in respect of land and building. The holding period for considering gain from immovable property to be long term is 3 years now. This is proposed to be reduced to 2 years. Also, the base year for indexation is proposed to be shifted from 1.4.1981 to 1.4.2001 for all classes of assets including immovable property. This move will significantly reduce the capital gain tax liability while encouraging the mobility of assets. We also plan to extend the basket of financial instruments in which the capital gains can be invested without payment of tax.

149. For Joint Development Agreement signed for development of property, the liability to pay capital gain tax will arise in the year the project is completed.

150. The new capital for State of Andhra Pradesh is being constructed by innovative land-pooling mechanism without use of the Land Acquisition Act. I propose to exempt from capital gain tax, persons holding land on 2.6.2014, the date on which the State of Andhra Pradesh was reorganised, and whose land is being pooled for creation of capital city under the Government scheme.

Measures for Stimulating Growth

151. A concessional with-holding rate of 5% is being charged on interest earned by foreign entities in external commercial borrowings or in bonds and Government securities. This concession is available till 30.6.2017. I propose to extend it to 30.6.2020. This benefit is also extended to Rupee Denominated (Masala) Bonds.

152. The Government gave income tax exemptions to start-ups with certain conditions last year. For the purpose of carry forward of losses in respect of such start-ups, the condition of continuous holding of 51% of voting rights has been relaxed subject to the condition that the holding of the original promoter/promoters continues. Also the profit linked deduction available to the start-ups for 3 years out of 5 years is being changed to 3 years out of 7 years.

153. Minimum Alternate Tax is at present levied as an advance tax. There is a strong demand for abolition of MAT. Although the plan for phasing out of exemptions will kick in from 1.4.2017, the full benefit of revenue out of phase-out will be available to Government only after 7 to 10 years when all those who are already availing exemptions at present complete their period of availment.

Therefore, it is not practical to remove or reduce MAT at present. However, in order to allow companies to use MAT credit in future years, I propose to allow carry forward of MAT upto a period of 15 years instead of 10 years at present.

154. In my Budget proposals in 2015, I had announced that I would be bringing the corporate income tax rate down to 25% gradually. In 2016 Budget, I had announced a reduction by 1% in case of those companies whose turnover is less than ₹ 5 crore. In the same Budget, I had also announced that new manufacturing companies who do not avail of any exemption would be charged only 25% income tax.

155. Medium and Small Enterprises occupy bulk of economic activities and are also instrumental in providing maximum employment to people. However, since they do not get many exemptions, they end up paying more taxes as compared to large companies. As per data of financial year 2015-16, 2.85 lakh companies making profit of less than ₹ 1 crore pay effective tax rate of 30.26% while 298 companies making profit above ₹ 500 crores pay effective tax rate of 25.90%.

156. In order to make MSME companies more viable and also to encourage firms to migrate to company format, I propose to reduce the income tax for smaller companies with annual turnover upto ₹ 50 crore to 25%. As per data of Assessment Year 2015-16, there are 6.94 lakh companies filing returns of which 6.67 lakh companies fall in this category and, therefore, percentage-wise 96% of companies will get this benefit of lower taxation. This will make our MSME sector more competitive as compared to large companies. The revenue forgone estimate for this measure is expected to be ₹ 7,200 crore per annum.

157. In order to give a boost to banking sector, I propose to increase allowable provision for Non-Performing Asset from 7.5% to 8.5%. This will reduce the tax liability of banks. I also propose to tax interest receivable on actual receipt instead of accrual basis in respect of NPA accounts of all non-scheduled cooperative banks also at par with scheduled banks. This will remove hardship of having to pay tax even when interest income is not realised.

158. Considering the wide range of use of LNG as fuel as well as feed stock for petro-chemicals sector, I propose to reduce the basic customs duty on LNG from 5% to 2.5%.

159. In order to incentivise domestic value addition and to promote Make in India, I propose to make changes in Customs & Central Excise duties in respect of certain items which are given in the **Annex III** of this speech. Some of these proposals are also for addressing duty inversion.

Promoting Digital Economy

160. There is a scheme of presumptive income tax for small and medium tax payers whose turnover is upto ₹ 2 crores. At present, 8% of their turnover is counted as presumptive income. I propose to make this 6% in respect of turnover which is received by non-cash means. This benefit will be applicable for transactions undertaken in the current year also.

161. I propose to limit the cash expenditure allowable as deduction, both for revenue as well as capital expenditure, to ₹ 10,000. Similarly, the limit of cash donation which can be received by a charitable trust is being reduced from ₹ 10,000/- to ₹ 2000/-.

162. The Special Investigation Team (SIT) set up by the Government for black money has suggested that no transaction above ₹ 3 lakh should be permitted in cash. The Government has decided to accept this proposal. Suitable amendment to the Income-tax Act is proposed in the Finance Bill for enforcing this decision.

163. To promote cashless transactions, I propose to exempt BCD, Excise/CV duty and SAD on miniaturised POS card reader for m-POS, micro ATM standards version 1.5.1, Finger Print Readers/Scanners and Iris Scanners. Simultaneously, I also propose to exempt parts and components for manufacture of such devices, so as to encourage domestic manufacturing of these devices.

Transparency in Electoral Funding

164. India is the world's largest democracy. Political parties are an essential ingredient of a multi-party Parliamentary democracy. Even 70 years after Independence, the country has not been able to evolve a transparent method of funding political parties which is vital to the system of free and fair elections. An attempt was made in the past by amending the provisions of the Representation of Peoples Act, the Companies Act and the Income Tax Act to incentivise donations by individuals, partnership firms, HUFs and companies to political parties. Both the donor and the donee were granted exemption from payment of tax if the accounts were transparently maintained and returns were filed with the competent authorities. Additionally, a list of donors who contributed more than ₹20,000/- to any party in cash or cheque is required to be maintained. The situation has only marginally improved since these provisions were brought into force. Political parties continue to receive most of their funds through anonymous donations which are shown in cash.

165. An effort, therefore, requires to be made to cleanse the system of political funding in India. Donors have also expressed reluctance in donating by cheque or other transparent methods as it would disclose their identity and entail adverse consequences. I, therefore, propose the following scheme as an effort to cleanse the system of funding of political parties:

- a) In accordance with the suggestion made by the Election Commission, the maximum amount of cash donation that a political party can receive will be ₹2000/- from one person.
- b) Political parties will be entitled to receive donations by cheque or digital mode from their donors.
- c) As an additional step, an amendment is being proposed to the Reserve Bank of India Act to enable the issuance of electoral bonds in accordance with a scheme that the Government of India would frame in this regard. Under this scheme, a donor could purchase bonds from authorised banks against cheque and digital payments only. They shall be redeemable only in the designated account of a registered political party. These bonds will be redeemable within the prescribed time limit from issuance of bond.
- d) Every political party would have to file its return within the time prescribed in accordance with the provision of the Income-tax Act.

Needless to say that the existing exemption to the political parties from payment of income-tax would be available only subject to the fulfilment of these conditions. This reform will bring about greater transparency and accountability in political funding, while preventing future generation of black money.

Ease of Doing Business

166. As an anti-avoidance measure, the provision of domestic transfer pricing in respect of related entities was brought in the Finance Act of 2012. Since then the number of entities being covered under domestic pricing has gone up substantially necessitating a longer scrutiny, which causes hardship to domestic companies. In order to reduce the compliance burden due to domestic transfer pricing provisions, I propose to restrict the scope of domestic transfer pricing only if one of the entities involved in related party transaction enjoys specified profit-linked deduction.

167. I propose to increase the threshold limit for audit of business entities who opt for presumptive income scheme from ₹1 crore to ₹2 crores. Similarly, the threshold for maintenance of books for individuals and HUF is being increased from turnover of ₹10 lakhs to ₹25 lakhs or income from ₹1.2 lakhs to ₹2.5 lakhs.

168. In 2012, Income-tax Act was amended to provide for taxation of those transactions of transfer of shares or interest in a foreign entity deriving its value substantially from Indian assets. Apprehensions have been raised about some difficulties which arise because of this provision in case of transfer of stake of investors of India-based funds located abroad but investing in India-based companies.

169. In order to remove this difficulty, I propose to exempt Foreign Portfolio Investor (FPI) Category I & II from indirect transfer provision. I also propose to issue a clarification that indirect transfer provision shall not apply in case of redemption of shares or interests outside India as a result of or arising out of redemption or sale of investment in India which is chargeable to tax in India.

170. As on today, a TDS of 5% is being deducted from commission payable to individual insurance agents even if the income of some of them may be below taxable limit. I propose to exempt them from the requirement of TDS subject to their filing a self-declaration that their income is below taxable limit.

171. Last year, I had announced a new scheme for presumptive taxation for professionals with receipt upto ₹50 lakhs p.a. In respect of such assesses, they are being given further benefit in terms of paying advance tax in one instalment instead of four.

172. In order to allow the people to claim the refund expeditiously, the time period for revising a tax return is being reduced to 12 months from completion of financial year, at par with the time period for filing of return. Also the time for completion of scrutiny assessments is being compressed further from 21 months to 18 months for Assessment Year 2018-19 and further to 12 months for Assessment Year 2019-20 and thereafter.

Personal Income-Tax

173. While the Government is trying to bring within tax-net more people who are evading taxes, the present burden of taxation is mainly on honest tax payers and salaried employees who are showing their income correctly. Therefore, post-demonetisation, there is a legitimate expectation of this class of people to reduce their burden of taxation. Also an argument is made that if a nominal rate of taxation is kept for lower slab, many more people will prefer to come within the tax net.

174. I, therefore, propose to reduce the existing rate of taxation for individual assesses between income of ₹2.5 lakhs to ₹5 lakhs to 5% from the present rate of 10%. This would reduce the tax liability of all persons below ₹5 lakh income either to zero (with rebate) or 50% of their existing liability. In order not to have duplication of benefit, the existing benefit of rebate available to the same group of beneficiaries is being reduced to ₹2500 available only to assessee upto income of ₹3.5 lakhs. The combined effect of both these measures will mean that there would be zero tax liability for people getting income upto ₹3 lakhs p.a. and the tax liability will only be ₹2,500 for people with income between ₹3 and ₹3.5 lakhs. If the limit of ₹1.5 lakh under Section 80C for investment is used fully the tax would be zero for people with income of ₹4.5 lakhs. While the taxation liability of people with income upto ₹5 lakhs is being reduced to half, all the other categories of tax payers in the subsequent slabs will also get a uniform benefit of ₹12,500/- per person. The total amount of tax foregone on account of this measure is ₹15,500 crores.

175. In order to make good some of this revenue loss on account of this relief, I propose to levy a surcharge of 10% of tax payable on categories of individuals whose annual taxable income is between ₹50 lakhs and ₹1 crore. The existing surcharge of 15% of Tax on people earning more than ₹1 crore will continue. This is likely to give additional revenue of ₹2,700 crores.

176. In order to expand tax net, I also plan to have a simple one-page form to be filed as Income Tax Return for the category of individuals having taxable income upto ₹5 lakhs other than business income. Also a person of this category who files income tax return for the first time would not be subjected to any scrutiny in the first year unless there is specific information available with the Department regarding his high value transaction. I appeal to all citizens of India to contribute to Nation Building by making a small payment of 5% tax if their income is falling in the lowest slab of ₹2.5 lakhs to ₹5 lakhs.

177. Some other important proposals for amendment in Tax Laws which are not covered by me in my speech are given in **Annex III** of this speech.

Goods and Services Tax

178. There has been substantial progress towards ushering in GST, by far, the biggest tax reform since independence. Since the enactment of the Constitution (One Hundred and First Amendment) Act, 2016, the preparatory work for this path-breaking reform has been a top priority for the Government. In this context, several teams of officers both from the States and Central Board of Excise and Customs have been working tirelessly to give finishing touch to the Model GST law and rules and other details. Government on its part has promptly given effect to various provisions of the Constitutional Amendment Act, including constitution of the GST Council. Since then, the GST Council held 9 meetings to discuss various issues relating to GST, including broad contours of the GST rate structure, threshold exemption and parameters for composition scheme, details for compensation to States due to implementation of GST, examination of draft model GST law, draft IGST law and the Compensation Law and administrative mechanism for GST. It is my privilege to inform this august house that the GST Council has finalised its recommendations on almost all the issues based on consensus and after spirited debate and discussions. The preparation of IT system for GST is also on schedule. The extensive reach-out efforts to trade and industry for GST will start from 1st April, 2017 to make them aware of the new taxation system.

179. Centre, through the Central Board of Excise & Customs, shall continue to strive to achieve the goal of implementation of GST as per schedule without compromising the spirit of co-operative federalism. Implementation of GST is likely to bring more taxes both to Central and State Governments because of widening of tax net. I have preferred not to make many changes in current regime of Excise & Service Tax because the same are to be replaced by GST soon.

RAPID

180. In the Annual Conclave of Tax officers called '**Rajaswa Gyan Sangam**' held in June 2016, the Prime Minister had expressed his desire to bring reforms in tax administration in the form of an approach of **RAPID** which stands for Revenue, Accountability, Probity, Information and Digitisation. This approach precisely reflects the strategy of Tax Department which is now formulated. While revenue considerations always remain the focus of Revenue Department, we are trying to bring in maximum use of Information Technology to remove human contact with assesses as well as to plug tax avoidance. We will try to maximise our efforts for **e-assessment** in the coming year. We are also using a lot of data mining capability, both in-house and outsourced. We plan to enforce greater accountability of officers of Tax Department for specific act of commission and omission. I would like to assure everyone that honest, tax-compliant person would be treated with dignity and courtesy.

181. Madam Speaker, my direct tax proposals for exemptions, etc. would result in revenue loss of ₹22,700 crore but after counting for revenue gain of ₹2,700 crore for additional resource mobilisation proposal, the net revenue loss in direct tax would come to ₹20,000 crore. There is no significant loss or gain in my indirect tax proposals.

CONCLUSION

182. Madam Speaker, I have outlined the Budget proposals under our overarching agenda: “Transform, Energise and Clean India”. Our emphasis will now be on implementing all these proposals for the benefit of the farmers, the poor and the underprivileged sections of our society.

183. Madam Speaker, it is said: “When my aim is right, when my goal is in sight, the winds favour me and I fly”. There is no other day, which is more appropriate for this, than today.

184. With these words, Madam Speaker, I commend the Budget to the House.

Annex I to Part A

Other measures in the Financial Sector

1. The commodities and securities derivative markets will be further integrated by integrating the participants, brokers, and operational frameworks.
2. The process of registration of financial market intermediaries like mutual funds, brokers, portfolio managers, etc. will be made fully online by SEBI. This will improve ease of doing business.
3. A common application form for registration, opening of bank and demat accounts, and issue of PAN will be introduced for Foreign Portfolio Investors (FPIs). SEBI, RBI and CBDT will jointly put in place the necessary systems and procedures. This will greatly enhance operational flexibility and ease of access to Indian capital markets.
4. Steps will be taken for linking of individual demat accounts with Aadhar.
5. Presently institutions such as banks and insurance companies are categorised as Qualified Institutional Buyers (QIBs) by SEBI. They are eligible for participation in IPOs with specifically earmarked allocations. It is now proposed to allow systemically important NBFCs regulated by RBI and above a certain net worth, to be categorised as QIBs. This will strengthen the IPO market and channelize more investments.
6. Listing and trading of Security Receipts issued by a securitisation company or a reconstruction company under the SARFAESI Act will be permitted in SEBI registered stock exchanges. This will enhance capital flows in to the securitisation industry and will particularly be helpful to deal with bank NPAs.

Annex II-A to Part A

ALLOCATIONS OF IMPORTANT MINISTRIES, SECTORS and VULNERABLE SECTIONS				
		<i>(In Crores of Rupees)</i>		
Sl. No.	Name of the Ministry	BE 2016-2017	RE 2016-2017	BE 2017-2018
1	Ministry of Agriculture and Farmers' Welfare	44485	48072	51026
2	Ministry of Development of North Eastern Region	2430	2524	2682
3	Ministry of Drinking Water and Sanitation	14010	16512	20011
4	Ministry of Health and Family Welfare	38206	39688	48853
5	Ministry of Housing and Urban Poverty Alleviation	5411	5285	6406
6	Ministry of Human Resource Development	72394	73599	79686
7	Ministry of Micro, Small and Medium Enterprises	3465	5463	6482
8	Ministry of Minority Affairs	3827	3827	4195
9	Ministry of New and Renewable Energy	5036	4360	5473
10	Ministry of Railways	45000	46155	55000
11	Ministry of Road Transport and Highways	57976	52447	64900
12	Ministry of Rural Development	87765	97760	107758
13	Ministry of Skill Development and Entrepreneurship	1804	2173	3016
14	Ministry of Social Justice and Empowerment	7350	7353	7763
15	Ministry of Tribal Affairs	4827	4827	5329
16	Ministry of Urban Development	24523	32550	34212
17	Ministry of Water Resources, River Development and Ganga Rejuvenation	6201	4756	6887
18	Ministry of Women and Child Development	17408	17640	22095
ALLOCATION FOR WELFARE OF SC, ST, OTHER VULNERABLE GROUPS, WOMEN, CHILDREN AND NORTH EASTERN REGION				
	Description of the Allocation	BE 2016-2017	RE 2016-2017	BE 2017-2018
I	Allocation for the welfare of Scheduled Tribes across all ministries	24005	25602	31920
II	Allocation for the welfare of Scheduled Castes across all ministries	38833	40920	52393
III	Allocation for the Welfare of Other Vulnerable Groups	1873	1892	1976
IV	Allocation for North Eastern Region across all ministries	29125	32180	43245
V	Allocation under various schemes for the welfare of women across all ministries	90770	96332	113327
VI	Allocation under various schemes for the welfare of Children across all ministries	65758	66249	71305

Sector Totals				
		<i>(In Crores of Rupees)</i>		
Sl. No.	Sectors	BE 2016-2017	RE 2016-2017	BE 2017-2018
1	Agriculture and Allied sectors	48572	52821	58663
2	Rural Development	102543	114947	128560
3	Infrastructure	348952	358634	396135
3a	of which Transport	216268	216903	241387
4	Social sectors	168100	176225	195473
4a	Education and Health	112138	114806	130215
4b	Social sectors with welfare orientation	55962	61419	65258
5	Employment Generation, Skill and Livelihood	12141	14870	17273
6	Scientific Ministries	33467	34359	37435

Source : Expenditure Profile and Expenditure Budget 2017-18

Annex II-B to Part A

ALLOCATION FOR IMPORTANT SCHEMES				
		<i>(In Crores of Rupees)</i>		
Sl. No.	Name of scheme	BE 2016-2017	RE 2016-2017	BE 2017-2018
1	Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Programme	38500	47499	48000
2	Pradhan Mantri Awas Yojna	20075	20936	29043
3	National Rural Drinking Water Mission	5000	6000	6050
4	National Social Assistance Programme	9500	9500	9500
5	Pradhan Mantri Gram Sadak Yojna	19000	19000	19000
6	National Education Mission including Sarva Shiksha Abhiyan	28330	28251	29556
7	National Programme of Mid-Day Meal in Schools	9700	9700	10000
8	Integrated Child Development Services	16260	16580	20755
9	National Health Mission	20762	22598	27131
10	Swachh Bharat Mission	11300	12800	16248
11	National Livelihood Mission - Aajeevika	3325	3334	4849

Annex II-B to Part A

ALLOCATION FOR IMPORTANT SCHEMES				
		<i>(In Crores of Rupees)</i>		
Sl. No.	Name of scheme	BE 2016-2017	RE 2016-2017	BE 2017-2018
12	Urban Rejuvenation Mission : AMRUT & Smart Cities Mission	7296	9559	9000
13	Green Revolution	12560	10360	13741
14	White Revolution	1138	1312	1634
15	Blue Revolution	247	392	401
16	Pradhan Mantri Krishi Sinchai Yojana (PMKSY) aggregated across three ministries	5767	5189	7377
17	Mission for Empowerment and Protection for Women	907	821	1089
18	Environment, Forestry and Wildlife	850	819	962
19	Employment Generation Programmes other than MGNREGS, including PM Kaushal Vikas Yojana, ATUFS, PM Mudra Yojana, PMEGP and ASPIRE	8133	10682	11640
20	Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana	5500	13240	9000
21	Optical Fibre Cable based network for Defence Services	2710	3210	3000
22	Price Stabilisation Fund for pulses	900	3400	3500
23	Bharatnet	0	6000	10000
24	Metro Projects	10000	15700	18000
25	Recapitalization of Public Sector Banks according to the Indradhanush scheme	25000	25000	10000
26	Integrated Power Development Scheme and Deen Dayal Upadhyaya Gram Jyoti Yojna	8500	7874	10635
27	Namami Gange- National Ganga Plan	2150	1441	2250
28	Sagarmala	450	406	600
29	LPG connection to poor households	2000	2500	2500

Annex II-C to Part A

Resources Transferred to State and UTs with Legislature					
Sl. No.		(In Crores of Rupees)			
		Actuals 2015-16	BE 2016-17	RE 2016-17	BE 2017-18
1	Devolution of states' share in taxes	506193	570337	608000	674565
2	Finance Commission Transfers	84579	100646	99115	103101
3	Other Central Transfers to States	238572	254371	277649	303412
4	Total Central Transfers to States (Gross) (1+2+3)	829344	925354	984764	1081078
5	Total Central Transfers to UTs with Legislature (Gross)	5139	5320	5547	3996
6	Total Transfers (Gross) (4+5)	834483	930674	990311	1085074
7	Recovery of Loans and Advances (a+b)	11513	9473	9163	9516
a	<i>States</i>	11454	9028	8730	9083
b	<i>UTs</i>	59	445	433	433
8	Total Central Transfers to States (Net) (4-7a)	817890	916326	976034	1071995
9	Total Central Transfers to UTs with Legislature (Net) (5-7b)	5080	4875	5114	3563
10	Total Transfers from Centre (Net) (8+9)	822970	921201	981148	1075558
	<i>In addition</i>				
11	Special State Government Securities issued from National Small Savings Fund (NSSF)*	58750	26375	13000	15000
* Only Madhya Pradesh, Kerala, Arunachal Pradesh and Delhi have chosen to receive loans from NSSF starting from 2016-17.					

Source: Budget at a Glance 2017-18.

Annex III to Part B of Budget Speech**Direct Taxes:****1. Additional Revenue Mobilisation (ARM) and Anti-abuse Measures**

- 1.1 It is proposed to extend the provisions of section 115BBDA of the Income-tax Act which provides for levy of tax at the rate of ten per cent. on dividend income exceeding ₹ 10 lakh, to all resident persons except domestic companies or trust or institution or fund registered under section 12AA or referred to in section 10(23C). Presently, these provisions are applicable only to the individuals, Hindu undivided family (HUF) and firms.
- 1.2 It is proposed to widen the scope of section 56 of the Income-tax Act to provide that any money, immovable property or specified movable property received without consideration or with inadequate consideration, by any person, subject to certain exemption and exceptions, shall be taxable if its value exceeds rupees fifty thousand.
- 1.3 It is proposed to provide that in case of transfer of unquoted equity shares, where the fair market value, determined in the prescribed manner is less than the consideration received, such fair market value shall be the deemed value of consideration for the purpose of computation of capital gains.
- 1.4 It is proposed to restrict the exemption from long term capital gains in case of transfer of listed shares by providing that the exemption, subject to notification of certain exceptions, shall be available if security transaction tax has been paid at the time of acquisition of such shares where they have been acquired after 1st October, 2004.
- 1.5 It is proposed to introduce a new provision in the Income-tax Act to provide for tax deduction at source at the rate of five per cent. by an individual or HUF, other than those whose books of account are required to be audited, while making payment of rent of an amount exceeding ₹ 50,000 per month. It is also proposed to provide that such tax shall be deducted and deposited only once in a financial year through a challan-cum-statement. Further, the deductor shall not be required to obtain TAN or file any separate TDS return for this purpose.
- 1.6 In order to align the transfer pricing provisions with the OECD transfer pricing guidelines and international best practices, it is proposed to insert a new section to provide that the assessee shall make secondary adjustment where the primary adjustment to the transfer price has been made in certain cases. The provision shall apply if the primary adjustment exceeds one crore rupees and the excess money attributable to the adjustment is not brought to India within the prescribed time.
- 1.7 In order to address the issue of thin capitalisation, it is proposed to provide that the interest paid by an Indian company or permanent establishment of a foreign company, in excess of thirty percent of earnings before interest, taxes, depreciation and amortisation (EBITDA), or interest paid to its associated enterprise, whichever is less, shall not be allowed as deduction in computing its taxable profit. It is also proposed to allow carry forward and set off of the interest so disallowed for eight assessment years.
- 1.8 In order to address the existing anomaly of interest deduction in respect of let out property vis-à-vis self-occupied property, it is proposed to restrict set off of loss from house property against income under any other head during the current year up to Rs two lakhs. The loss not so set off would be allowed to be carried forward for set off against house property income for eight assessment years.
- 1.9 It is proposed that donation by an entity registered under section 12A or approved under section 10(23C), to other entity, registered under section 12A, with the direction that such donation shall form part of the corpus, shall not be treated as application of income for charitable purposes.

2. **Rationalisation Measures**

- 2.1 It is proposed to provide that in case of foreign company, sale of leftover stock of crude oil in case of strategic petroleum reserve after the expiry of agreement or the arrangement, subject to fulfilment of certain conditions, shall not be liable to tax in India.
- 2.2 It is proposed to provide a concessional tax rate of ten per cent. in case of income arising from sale of carbon credit.
- 2.3 It is proposed to exempt government, foreign missions and state PSUs engaged in business of transportation of passengers from Tax Collection at Source (TCS) provisions relating to purchase of vehicles.
- 2.4 It is proposed to provide that the fair market value of the asset which has been taken into account for the purpose of computation of accreted income on which tax has been paid in accordance with provisions of Chapter XII-EB of the Income-tax Act, shall be taken as the cost of acquisition of that asset.
- 2.5 It is proposed to modify the conditions of special taxation regime for off shore funds under section 9A of the Income-tax Act so as to provide that the maintenance of minimum fund size would not be necessary in the year in which the fund is being wound up.
- 2.6 In line with exemption available to the Prime Minister's Relief Fund and certain other funds, it is proposed to provide that the income of the Chief Minister's Relief Fund or the Lieutenant Governor's Relief Fund shall be exempt from tax.
- 2.7 It is proposed to do away with the provisions enabling the Assessing Officer not to process the return and thus withhold the refund in cases where the return is selected for scrutiny till the completion of assessment. It is however proposed that in cases where grant of refund is likely to adversely affect the interest of revenue, it can be withheld with the approval of the higher authority after recording the reasons in writing.
- 2.8 It is proposed to provide that certain entities, like, Investor Protection Funds, Core Settlement Guarantee Fund, Tea/Coffee/Rubber Boards, MPEDA, or APDEA; enjoying exemption from levy of income-tax under section 10 of the Income-tax Act shall be required to furnish return of their income.
- 2.9 In order to ensure timely filing of returns of income, it is proposed to levy a fee in case of delay in filing the return.
- 2.10 It is proposed to provide that if an accountant or a merchant banker or a registered valuer, furnishes incorrect information in a report or certificate, he shall be liable to a penalty of ten thousand rupees for each such default.
- 2.11 It is proposed to provide that where the amount of foreign tax credit (FTC) allowed against the tax paid under sections 115JB or 115JC of the Income-tax Act exceeds the amount of FTC admissible against the tax payable by the assessee on his income in accordance with the other provisions of the Act, such excess credit shall be ignored while computing the amount of credit under section 115JAA or section 115JD.
- 2.12 In a case where the foreign tax credit has not been granted to the assessee on the ground that payment of such tax is in dispute, it is proposed to provide, subject to certain conditions, additional time to the Assessing Officer for allowing the said tax credit after such dispute is settled.
- 2.13 It is proposed to provide that no person shall receive payment or aggregate of payments of an amount of three lakh rupees or more from a person in a day, or in respect of a single transaction, or in respect of transactions relating to one event or occasion, otherwise than by an account payee cheque or account payee bank draft or use of electronic clearing system through a bank account. Such restriction shall not apply to Government, banks or such other persons or class of persons or

- receipts notified by the Central Government. It is also proposed to provide for a penalty in case of contravention of this provision.
- 2.14 It is proposed to clarify that provisions relating to tax deduction at source shall not apply to exempt compensation received under the Right to Fair Compensation and Transparency in Land Acquisition, Rehabilitation and Resettlement Act, 2013.
- 2.15 It is proposed to lower the rate of deduction of tax in case of payments made to a person engaged only in the business of operation of call centre.
- 2.16 It is proposed to provide tax neutrality in case of conversion of preference shares of a company into equity shares of that company.
- 2.17 It is proposed to provide that the cost of acquisition of share of an Indian company in the hands of demerged foreign company in a tax neutral demerger, shall be taken as the cost of acquisition in the hands of resulting foreign company.
- 2.18 It is proposed to provide for grant of interest in case of refund of excess payment of TDS.
- 2.19 It is proposed to merge the Authority for Advance Ruling (AAR) for Income-Tax with AAR for Customs, Central Excise and Service Tax; and create common AAR. It is also proposed to amend the qualifications for appointment of Chairman and Members.
- 2.20 It is proposed to make the orders passed by the authority under section 10(23C) of the Income-tax Act, appealable before the Tribunal.
- 2.21 It is proposed to authorise the Central Board of Direct Taxes (CBDT), to issue directions or instructions in order to remove hardships faced by the taxpayers in connection with imposition of penalty relating to tax deduction or collection at source.
- 2.22 It is proposed to amend the provisions relating to computation of book profit for the purpose of levy of minimum alternate tax (MAT) so as to align it with the Indian Accounting Standards (Ind-AS).
- 2.23 It is proposed to clarify that the amendment made by the Finance Act, 2016 in Section 112 of the Income-tax Act providing for concessional rate of tax in respect of transfer of share of a private limited company shall be applicable retrospectively from assessment year 2013-14.
- 2.24 It is proposed to amend section 10AA of the Income-tax Act so as to provide that the amount of deduction referred therein shall be allowed from the total income computed in accordance with the provisions of the Act before giving effect to the provisions of the said section and that the said deduction shall not exceed the total income.
- 2.25 It is proposed to clarify that in the case of furnishing of information relating to payment to a non-resident of any sum whether or not chargeable to tax, the "person responsible for paying" shall be the payer himself, or, if the payer is a company, the company itself including the principal officer thereof.
- 2.26 It is proposed to provide that where any 'term' used in an agreement entered into under sub-section (1) of Section 90 and 90A of the Income-tax Act, is defined under the said agreement, the said term shall be assigned the meaning as provided in the said agreement and where the term is not defined in the agreement, but is defined in the Act, it shall be assigned the meaning as defined in the Act or any technical explanation issued by the Central Government.
- 2.27 It is proposed to provide that where the capital asset referred to in section 35AD of the Income-tax Act is used for an ineligible business and the benefit of said section is withdrawn, the actual cost to the assessee in respect of such asset shall be the actual cost to the assessee, as reduced by an amount equal to the amount of depreciation calculated at the rate in force that would have been allowable had the asset been used for the purposes of business since the date of its acquisition.

- 2.28 It is proposed to provide that a trust or an institution, which has been granted registration, and, has adopted or undertaken modification of the objects subsequently which do not conform to the conditions of registration, shall be required to obtain fresh registration.
- 2.29 In order to strengthen the TCS regime, it is proposed to provide that the collectee shall furnish his PAN to the collector, failing which, tax shall be collected at a higher rate.
- 2.30 In order to provide parity between an individual who is an employee and an individual who is self-employed, it is proposed to provide that the self-employed individual shall be eligible for deduction upto twenty per cent of his gross total income in respect of contribution made to National Pension System Trust.
- 2.31 It is proposed to provide that the authorised officer can, subject to conditions as specified, provisionally attach a property for a period of six months in order to protect the interest of revenue. It is also proposed to provide that he can make a reference to the valuation officer for the purpose of estimation of FMV of a property.
- 2.32 It is proposed to authorise the Joint Director, Deputy Director or the Assistant Director of Income-tax to call for information for the purpose of any enquiry without seeking approval of the higher authority.
- 2.33 It is proposed to expand the provision of section 133A of the Income-tax Act so as to include any place at which activity for charitable purpose is carried on.
- 2.34 It is proposed to authorise the CBDT to frame a scheme for centralised issuance of notice calling for information and documents for the purpose of verification of information in its possession, processing of such documents and making the outcome thereof available to the Assessing Officer.
- 2.35 In order to remove hardship, it is proposed to omit section 197(C) of the Finance Act, 2016 which provided for assessment of undisclosed income relating to any period prior to commencement of the Income Declaration Scheme, 2016. However, in search cases, it is proposed to provide that in case tangible evidence is found during the search, the Assessing Officer can assess income upto ten years preceding the year in which search took place.
- 2.36 In order to strengthen the TDS provisions, it is proposed to provide that a disallowance shall be made in respect of an expenditure incurred against income from other sources unless tax has been deducted thereon at applicable rates.
- 2.37 In order to maintain the confidentiality of the source of the information and the identity of the informer, it is proposed to clarify that the reasons to believe as recorded by the income-tax authority authorising a search operation or a requisition of books of account or asset, shall not be disclosed to any person, authority or appellate tribunal.
- 2.38 It is proposed to provide that in case of unit in the consolidated plan of a mutual fund scheme received in lieu of unit in the consolidating plan, the actual cost and the period of holding shall be the cost and the period of holding of the unit in the consolidating plan.
- 2.39 It is proposed to amend the provision of clause 4 of section 10 of the Income-tax Act, 1961 so as to make the correct reference to Foreign Exchange Management Act (FEMA).
- 2.40 It is proposed to provide a sun set clause in respect of deduction allowed to certain persons in respect of investment in listed equity shares and listed units of an equity oriented fund.
- 2.41 It is proposed to exempt capital gains arising out of transfer of a rupee denominated bond by a non-resident to a non-resident.

Indirect Taxes

I. PROPOSALS INVOLVING CHANGE IN DUTY / TAX RATES: CUSTOMS:

		Commodity	Rate of Duty	
			From	To
I.	Incentivizing domestic value addition, ‘Make in India’			
A.	Reduction in Customs duty on inputs and raw materials to reduce costs			
		Mineral fuels and Mineral oils		
	1.	Liquefied Natural Gas	BCD – 5%	BCD – 2.5%
		Chemicals & Petrochemicals		
	2.	Medium Quality Terephthalic Acid (MTA) & Qualified Terephthalic Acid (QTA)	BCD – 7.5%	BCD – 5%
		Metals		
	3.	Nickel	BCD – 2.5%	BCD – Nil
		Finished Leather		
	4.	Vegetable tanning extracts, namely, Wattle extract and Myrobalan fruit extract	BCD – 7.5%	BCD – 2.5%
		Capital Goods		
	5.	Ball screws, linear motion guides and CNC systems for use in the manufacture of CNC machine tools, subject to actual user condition	Ball screws and liner motion guides BCD – 7.5% CNC systems BCD – 10%	BCD – 2.5%
		Renewable Energy		
	6.	All items of machinery required for fuel cell based power generating systems to be set up in the country or for demonstration purposes, subject to certain specified conditions	BCD – 10% /7.5% CVD – 12.5%	BCD – 5% CVD – 6%
	7.	All items of machinery required for balance of systems operating on biogas/bio-methane/by-product hydrogen, subject to certain specified conditions	BCD – 10% /7.5% CVD – 12.5%	BCD – 5% CVD – 6%
		Miscellaneous		
	8.	All parts for use in the manufacture of LED lights or fixtures, including LED lamps, subject to actual user condition	Applicable BCD, CVD	BCD – 5% CVD – 6%
	9.	All inputs for use in the manufacture of LED Driver and MCPCB for LED lights or fixtures, including LED lamps, subject to actual user condition	Applicable BCD	5%

		Commodity	Rate of Duty	
			From	To
B.	Changes in Customs and Excise / CV duty to address the problem of duty inversions in certain sectors			
		Chemicals & Petrochemicals		
	10.	o-Xylene	BCD – 2.5%	BCD – Nil
	11.	2-Ethyl Anthraquinone [2914 69 90] for use in manufacture of hydrogen peroxide, subject to actual user condition	BCD – 7.5%	BCD – 2.5%
	12.	Vinyl Polyethylene Glycol (VPEG) for use in manufacture of Poly Carboxylate Ether, subject to actual user condition	BCD – 10%	BCD – 7.5%
		Textiles		
	13.	Nylon mono filament yarn for use in monofilament long line system for Tuna fishing, subject to certain specified conditions	BCD – 7.5%	BCD – 5%
		Metals		
	14.	Co-polymer coated MS tapes / stainless steel tapes for manufacture of specified telecommunication grade optical fibres or optical fibre cables, subject to actual user condition	BCD – Nil	BCD – 10%
	15.	MgO coated cold rolled steel coils [7225 19 90] for use in the manufacture of CRGO steel, subject to actual user condition	BCD – 10%	BCD – 5%
	16.	Hot Rolled Coils [7208] for use in the manufacture of welded tubes and pipes falling under heading 7305 or 7306, subject to actual user condition	BCD – 12.5%	BCD – 10%
		Automobiles		
	17.	Clay 2 Powder (Alumax) for use in ceramic substrate for catalytic convertors, subject to actual user conditon	BCD – 7.5%	BCD – 5%
		Renewable Energy		
	18.	Solar tempered glass for use in the manufacture of solar cells/panels/modules	BCD – 5%	BCD – Nil
	19.	Parts/raw materials for use in the manufacture of solar tempered glass for use in solar photovoltaic cells/modules, solar power generating equipment or systems, flat plate solar collector, solar photovoltaic module and panel for water pumping and other applications, subject to actual user condition	CVD – 12.5%	CVD – 6%

		Commodity	Rate of Duty	
			From	To
	20.	Resin and catalyst for use in the manufacture of cast components for Wind Operated Energy Generators [WOEG], subject to actual user condition	BCD – 7.5% CVD – 12.5% SAD – 4%	BCD – 5% CVD – Nil SAD – Nil
		Miscellaneous		
	21.	Membrane Sheet and Tricot / Spacer for use in the manufacture of RO membrane element for household type filters, subject to actual user condition	CVD – 12.5%	CVD – 6%
C.	Changes in Customs duty to provide adequate protection to domestic industry			
		Food Processing		
	22.	Cashew nut, roasted, salted or roasted and salted	BCD – 30%	BCD – 45%
		Electronics / Hardware		
	23.	Populated Printed Circuit Boards (PCBs) for use in the manufacture of mobile phones, subject to actual user condition	SAD – Nil	SAD – 2%
		Miscellaneous		
	24.	RO membrane element for household type filters	BCD – 7.5%	BCD – 10%
D.	Promotion of cashless transactions and promote domestic manufacturing of devices used therefor			
	25.	a) Miniaturized POS card reader for m-POS (not including mobile phones or tablet computer), b) Micro ATM as per standards version 1.5.1, c) Finger Print Reader / Scanner, and d) Iris Scanner	Applicable BCD, CVD SAD	BCD – Nil CVD – Nil SAD – Nil
	26.	Parts and components for manufacture of: a) miniaturized POS card reader for m-POS (not including mobile phones or tablet computer), b) micro ATM as per standards version 1.5.1, c) Finger Print Reader / Scanner, and d) Iris Scanner	Applicable BCD, CVD SAD	BCD – Nil CVD – Nil SAD – Nil
II.	Imposition of export duty to conserve domestic resources			
	27.	Other aluminium ores, including laterite	Nil	15%
III.	Improving ease of doing business and Export Promotion			
	28.	De-minimis customs duties exemption limit for goods imported through parcels, packets and letters	Duty payable not exceeding Rs.100 per consignment	CIF value not exceeding Rs.1000 per consignment
	29.	Limit of duty free import of eligible items for manufacture of leather footwear or synthetic footwear or other leather products for use in the manufacture of said goods for export	3% of FOB value of said goods exported during the preceding financial year	5% of FOB value of said goods exported during the preceding financial year

		Commodity	Rate of Duty	
			From	To
IV.	Anti-avoidance measure			
	30.	Silver medallion, silver coins, having silver content not below 99.9%, semi-manufactured form of silver and articles of silver	CVD – Nil	CVD – 12.5%

Note: (a) “Basic Customs Duty” means the customs duty levied under the Customs Act, 1962.

(b) “CVD” means the Additional Duty of Customs levied under sub-section (1) of section 3 of the Customs Tariff Act, 1975.

(c) “SAD” means the Special Additional Duty of Customs levied under sub-section (5) of section 3 of the Customs Tariff Act, 1975.

(d) “Export duty” means duty of Customs leviable on goods specified in the Second Schedule to the Customs Tariff Act, 1975.

EXCISE

		Commodity	Rate of Duty	
			From	To
I.	Public Health			
A.	Tobacco and Tobacco Products			
	1.	Cigar and cheroots	12.5% or Rs.3755 per thousand, whichever is higher	12.5% or Rs.4006 per thousand, whichever is higher
	2.	Cigarillos	12.5% or Rs.3755 per thousand, whichever is higher	12.5% or Rs.4006 per thousand, whichever is higher
	3.	Cigarettes of tobacco substitutes	Rs.3755 per thousand	Rs.4006 per thousand
	4.	Cigarillos of tobacco substitutes	12.5% or Rs.3755 per thousand, whichever is higher	12.5% or Rs.4006 per thousand, whichever is higher
	5.	Others of tobacco substitutes	12.5% or Rs.3755 per thousand, whichever is higher	12.5% or Rs.4006 per thousand, whichever is higher
	6.	Paper rolled biris – handmade	Rs.21 per thousand	Rs.28 per thousand
	7.	Paper rolled biris – machine made	Rs.21 per thousand	Rs.78 per thousand
II.	Incentivizing domestic value addition, ‘Make in India’			
A.	Renewable Energy			
	8.	All items of machinery required for balance of systems operating on biogas/bio-methane/by-product hydrogen	12.5%	6%

		Commodity	Rate of Duty	
			From	To
B.	Miscellaneous			
	9.	Membrane Sheet and Tricot/Spacer for use in the manufacture of RO membrane element for household type filters, subject to actual user condition	12.5%	6%
	10.	All parts for use in the manufacture of LED lights or fixtures, including LED lamps, subject to actual user condition	Applicable duty	6%
	11.	a. Waste and scrap of precious metals or metals clad with precious metals arising in course of manufacture of goods failing in Chapter 71 b. Strips, wires, sheets, plates and foils of silver c. Articles of silver jewellery, other than those studded with diamond, ruby, emerald or sapphire d. Silver coin of purity 99.9% and above, bearing a brand name when manufactured from silver on which appropriate duty of customs or excise has been paid	Nil	Nil, subject to the condition that no credit of duty paid on inputs or input services or capital goods has been availed by manufacturer of such goods
III.	Promotion of cashless transactions and promote domestic manufacturing of devices used therefor			
	12.	a) Miniaturized POS card reader for m-POS (not including mobile phones or tablet computers), b) micro ATM as per standards version 1.5.1, c) Finger Print Reader/Scanner, and d) Iris Scanner	Applicable duty	Nil

		Commodity	Rate of Duty	
			From	To
	13.	Parts and components for manufacture of: a) Miniaturized POS card reader for m-POS (not including mobile phones or tablet computers), b) Micro ATM as per standards version 1.5.1, c) Finger Print Reader/Scanner, and d) Iris Scanner	Applicable duty	Nil

Note: “Basic Excise Duty” means the excise duty set forth in the First Schedule to the Central Excise Tariff Act, 1985.

CHANGES IN RATE OF ADDITIONAL DUTY LEVIED UNDER SECTION 85 OF THE FINANCE ACT, 2005

		Commodity	Rate of duty	
			From	To
A.	Pan Masala			
	1.	Pan Masala	6%	9%
B.	Tobacco and Tobacco Products			
	2.	Unmanufactured tobacco	4.2%	8.3%
	3.	Non-filter Cigarettes of length not exceeding 65mm	Rs.215 per thousand	Rs.311 per thousand
	4.	Non-filter Cigarettes of length exceeding 65mm but not exceeding 70mm	Rs.370 per thousand	Rs.541 per thousand
	5.	Filter Cigarettes of length not exceeding 65mm	Rs.215 per thousand	Rs.311 per thousand
	6.	Filter Cigarettes of length exceeding 65mm but not exceeding 70mm	Rs.260 per thousand	Rs.386 per thousand
	7.	Filter Cigarettes of length exceeding 70mm but not exceeding 75mm	Rs.370 per thousand	Rs.541 per thousand
	8.	Other Cigarettes	Rs.560 per thousand	Rs.811 per thousand
	9.	Chewing tobacco (including filter khaini)	6%	12%
	10.	Jarda scented tobacco	6%	12%
	11.	Pan Masala containing Tobacco (Gutkha)	6%	12%

SERVICE TAX

	S. No.	Changes	Existing	Proposed
A.	Relief to the armed forces of the Union from service tax			
	1.	Services provided or agreed to be provided by the Army, Naval and Air Force Group Insurance Funds by way of life insurance to members of the Army, Navy and Air Force under the Group Insurance Schemes of the Central Government is being exempted from service tax from 10 th September, 2004 (the date when the services of life insurance became taxable).	14%	Nil
B.	Dispute resolution, certainty of taxation and avoidance of litigation			
	1.	Notification No. 41/2016-ST dated 22.09.2016, which has exempted from service tax, one time upfront amount (called as premium, salami, cost, price, development charges or by whatever name) payable for grant of long-term lease of industrial plots (30 years or more) by State Government industrial development corporations/undertakings to industrial units, is proposed to be made effective from 1.6.2007 (the date when the services of renting of immovable property became taxable).	14%	Nil
	2.	Rule 2A of the Service Tax (Determination of Value) Rules, 2006 is proposed to be amended from 01.07.2010 so as to make it clear that value of service portion in execution of works contract involving transfer of goods and land or undivided share of land, as the case may be, shall not include value of property in such land or undivided share of land.	4.2%	4.2%
C.	Promotion of Regional Connectivity Scheme of Ministry of Civil Aviation			
	1.	Under the Regional Connectivity Scheme (RCS), exemption from service tax is being provided in respect of the amount of viability gap funding (VGF) payable to the airline operator for providing the services of transport of passengers by air, embarking from or terminating in a Regional Connectivity Scheme (RCS) airport, for a period of one year from the date of commencement of operations of the Regional Connectivity Scheme (RCS) airport as notified by Ministry of Civil Aviation.	14%	Nil
D.	Rationalization Measures			
	1.	The exemption in respect of services provided by Indian Institutes of Management (IIMs) by way of two year full time residential Post Graduate Programmes (PGP) in Management for the Post Graduate Diploma in Management (PGDM), to which admissions are made on the basis of the Common Admission Test (CAT), conducted by IIMs, is being extended to include non-residential programmes.	14%	Nil
	2.	Explanation-I (e) to Rule 6 of CENVAT Credit Rules, 2004 is being amended so as to exclude banks and financial institutions including non-banking financial companies engaged in providing services by way of extending deposits, loans or advances from its ambit.		
	3.	The Negative List entry in respect of "services by way of carrying out any process amounting to manufacture or production of goods excluding alcoholic liquor for human consumption", in the Finance Act, 1994, is proposed to be omitted and instead placed in the exemption notification. Consequently, clause (40) of section 65B of the Finance Act, which defines ' <i>process amounting to manufacture</i> ' is also proposed to be omitted and instead placed in the exemption notification.	Nil	Nil

AMENDMENT IN THE FIRST SCHEDULE TO THE CUSTOMS TARIFF ACT, 1975

S. No.	Amendment
A.	Amendments not affecting rates of duty
1.	<p>The following amendments are being carried out to:</p> <ul style="list-style-type: none"> (i) Delete tariff items 1302 32 10 and 1302 32 20 and entries relating thereto and create new tariff items 1106 10 10 and 1106 10 90, in relation to Guar meal and its products so as to harmonize the Customs Tariff with HS Nomenclature. (ii) Create new tariff item 1511 90 30 for Refined bleached deodorized palm stearin, so as to harmonize Customs Tariff in accordance with WCO classification decision. (iii) Substitute tariff items 3823 11 11 to 3823 11 90 and entries relating thereto with tariff item 3823 11 00. (iv) Substitute tariff items 3904 10 10 to 3904 22 90 with tariff items 3904 10 10 to 3904 22 00 in relation to the PVC Resin.
2.	Chapter Note (4) of Chapter 98 is being amended so as to remove the non-applicability of headings 9803 and 9804 to goods imported through courier service. Also, heading 9804 is being amended so as to extend the classification of personal imports by courier, sea, or land under this heading.

PRASHANT GOYAL, Jt. Secy. (Budget)